हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

13 फरवरी, 2009

(पहली बैठक)

खण्ड 1, अंक 4

अधिकृत विवरण

विषय सूची

शुक्रवार, 13 फरवरी, 2009 (पहली बैठक)

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(4)1
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए	(4)20

तराकिंत प्रश्नों के लिखित उत्तर	
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, करनाल और राजकीय	(4)26
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बाला छावनी के विद्यार्थियों का अभिनन्दन अनुपस्थिति संबंधी सूचनाएं	(4)26
नियम 121 के अधीन प्रस्ताव	(4)27
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना	(4)28
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्म)	(4)29
अति विशिष्ट व्यक्तियों का अभिनंदन	(4)43
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्म)	(4)43
वर्ष 2008–09 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) प्रस्तुत करना	(4)67
प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना	(4)67
वर्ष 2008–2009 के लिए अनुपूरक अनुमानों की मांगों	(4)67
(द्वितीय किस्त) पर चर्चा तथा मतदान कार्य सूची की एक मद को अस्थगित करना	(4)74

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार 13 फरवरी, 2009

(पहली बैठक)

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर– 1, चण्डीगढ में 9.30 हुई। अध्यक्ष (डा० रघुबीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

ताराकिंत प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः ऑनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल जवाब होंगे।

ताराकिंत प्रश्न संख्या 1186

(इस समय माननीय सदस्य श्री दिनेश कौशिक सदन में उपस्थित नहीं मे इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया।)

Filling up the Vacant Posts in Government Schools

***1166. Sh. Tejender Pal Singh Mann:** Will the Education Minister be pleased to state—

(a) the number of posts lying vacant in G.S.S.Ss, G.H.Ss, G.M.Ss and G.P.Ss in Pai constituency togetherwith the steps being taken by the Government to fill up the said posts ; and

(b) whether the Government is planning to appoint Guest Teachers to fill up these vacancies ?

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता): श्रीमान जी,

(क) पाई निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न राजकीय विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों 'के ' 581 अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हैं जिनमें से 249 रिक्त पदों पर अतिथि अध्यापकों से काम चलाया जा रहा है। इन रिक्तियों को भरने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को मांग पत्र भेजा जा रहा है।

(ख) नए गैस्ट अध्यापक नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मानः अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और कई स्कूल अपग्रेड भी हुए थे। जब भी स्कूल अपग्रेड होता है तो उसमें यह प्रोब्लम आती है कि हर कोई यह चाहता है कि उस स्कूल में हैड मास्टर हो, टीचर्ज हों। अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां पर आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर टीचर्ज की बहुत कमी है। जो गांव शहरों से बहुत दूर हैं उन गांवों के लिए गैस्ट टीचर्ज की भर्ती बहुत ही बढ़िया चीज थी। पिछली सरकार के वक्त में हमारे यहां पर 40–40 और 50–50 टीचर्ज की एक–एक स्कूल में कमी थी। इस सरकार के आने के बाद ये जो गैस्ट टीचर्ज लगाए गए उसके बाद स्कूलों में 1000–1000 बच्चों की स्ट्रैंग्थ हो गई थी। मेरा सरकार से निवेदन है कि उन गांवों में टीचर्ज लगें जहां पर टीचर्ज की पोस्टस खाली हैं ताकि वहां पढ़ने वाले बच्चों का पढ़ाई की वजह से स्कूलों में

इन्ट्रस्ट बना रहे। इससे हम जो चाहते हैं तथा हमारा जो सपना है कि हर व्यक्ति हरियाणा में पड़े वह पूरा हो सकेगा।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय यह ठीक है कि लोगो की डिमांड के मुताबिक स्कूल अप–ग्रेड होते रहे जिसकी वजह से स्कूलों में टीचर्ज की कमी रही। हमारी सरकार ने भर्ती करने की कोशिश की लेकिन किन्हीं कारणों से हाईकोर्ट से भर्ती पर स्टे हो गया। दो साल स्टे रहा लेकिन पिछले साल आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से स्टे हटा। स्टे हटने के बाद जहां पर हमने जरूरत समझी वहां पर टीचर्ज लगाए। हमारे पास कोई और तरीका नहीं था इसलिए जहां पर हमने सख्त जरूरत समझी थी वहां पर गैस्ट टीचर्ज लगाए। उसके बाद हमने 10– 12 हजार टीचर्ज की रैगुलर भर्ती की और आगे भी करने जा रहे हैं। अध्यापकों की जो कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए भर्ती के लिए केस भैजा हुआ है। रैगुलर भर्ती करना हम ठीक समझते हैं। गैस्ट टीचर्ज की भर्ती बहुत बड़ी प्रोब्लम है क्योंकि बाद में वे चाहते हैं कि उनको रैगुलर कर दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री ने इस बारे में प्रयास भी किए और हमने कमेटी भी बनाई लेकिन हमें कोई भी कानूनी राय गैस्ट टीचर्ज को रैगुलर करने के बारे में नहीं मिल पा रही है। इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए हमने अब गैस्ट टीचर्ज की भर्ती पर बैन लगा दिया है कि आगे से गैस्ट टीचर्ज की भर्ती नहीं होगी।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मानः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जिस तरह से डाक्टरों की भर्ती के लिए सरकार ने एक रिवाल्विंग प्रक्रिया को अपनाया हुआ है, टीचर्ज की भर्ती के लिए भी वैसी ही कोई प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। यह जो टीचर्ज की कमी है वह बच्चों की पढ़ाई को इफैक्ट करती है, पूरी क्लास को इफैक्ट करती है, काफी बच्चों को इफैक्ट करती है। स्कूलों में जो इफ्लूशियल सैक्शन्ज के बच्चे होते हैं वे तो प्राईवेट स्कूलों में भी चले जाते हैं लेकिन जो गरीब बच्चे इन स्कूलों में रह जाते हैं उनके लिए जरूरी है कि शिक्षा प्रणाली में वे इन्वॉल्व रहें इसलिए टीचर्ज की वैकेन्सीज हमेशा भरी रहनी चाहिए। जिस तरह से डाक्टर्ज की अब भर्ती की जा रही है उसी तर्ज पर यदि टीचर्ज की भी भर्ती हो जाए तो मेरा ख्याल है कि सरकारी स्कूलों के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय सदस्य ने सवाल किया और शिक्षा मंत्री जी ने जबाव दिया है। एक बहुत ही अहम मुद्दा गैस्ट टीचर्ज का सामने आया है। ये गैस्ट टीचर्ज डेढ़–डेढ़, दो–दो साल से अपना कार्य कर रहे हैं। इसी कारण हमने एक कमेटी गठित की है। हम लीगली ऐग्जामिन कर रहे हैं। पूरी सहानुभूति के साथ हमारा प्रयास है कि कानून के दायरे के अंदर हम उनका समावेश करें उनको

रैगुलेराइज करें। इसका फैसला होते ही हम आगे नयी भर्ती करेंगे ताकि टीचर्ज की स्कूलों में कमी न रहे।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने बिलकुल वाजिब फरमाया है। जो हमारी कमेटी इस बारे में बनी है उसकी मीटिंग में हमने गैस्ट टीचर्ज को भी बिठाया था और उनको खुला ऑफर किया कि आप कोई भी इस बारे में अपनी लीगल राय दें, आप सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का कोई भी वकील ले आएं 'और उससे भी राय ले लें। हमें कोई ऐतराज नहीं है हम तो गैस्ट टीचर्स को रैगुलर करना चाहते हैं और मुख्यमंत्री जी का भी आदेश है। स्पीकर साहब, जब हमें इस बारे में कोई कानूनी राय मिल जाएगी तो हम आगे कार्यवाही करेंगे। स्पीकर साहब मैं तो आज एम०एल०एज० को भी इस बारे में इन्वाइट करता हूं कि वे हमें कोई प्रपोजल लाकर दे दें ताकि सरकार इनको रैगुलर कर सके। मान साहब, हमारे पास ये सरप्लस नहीं हैं हमारे पास तो वैकेसीज हैं हम तो इनको रैगुलर करना चाहते हैं लेकिन हमारी मजबूरी यह है कि कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। कल को ये नियुक्तियां फिर हाई कोर्ट में चौलेंज हो जाएंगी तो इसमें फिर सरकार की भक्त पिटेगी। फिर लोग कहेंगे कि आपने ठीक काम नहीं किया। स्पीकर साहब, सारी बात को मद् देनजर रखते हुए हम कानूनी निगाह से यह काम करना चाहते हैं, कर देंगे, कोशिश कर रहे हैं।

चौ० अरजन सिंहः स्पीकर साहब, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वैसे तो आश्वासन दे ही दिया है लेकिन मेरी भी इसी बारे में मांग थी। मैं मुख्यमंत्री जी के और मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मेरे हल्के के कुछ स्कूलों में भी टीचर्ज की पोस्ट खाली पड़ी हैं। कई जगह पर अंग्रेजी के या दूसरे सब्जैक्ट के टीचर्ज नहीं हैं इसलिए इस बारे में भी सरकार ध्यान दें।

श्री अध्यक्षः अरजन सिंह जी, आप इस बारे में लिखकर भिजवा देना और वहां पर यदि कोई टीचर लगना चाहता है तो उनके नाम भी आप लिखकर भिजवा देना।

चौ० अरजन सिंहः ठीक है सर।

डॉ० सीता रामः स्पीकर सर, वैसे तो मेरा इस बारे में एक क्वैश्चन भी है लेकिन आपने मुझे सप्लीमैंट्री पूछने का मौका भी दिया है इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में टीचर्ज की कुल कितनी पोस्ट खाली हैं और क्या यह सरकार अपने इस कार्यकाल में उनको भरने का काम करेगी?

श्री अध्यक्षः डाक्टर साहब, ये सारी बातें तो जो रिप्लाई आपकी टेबल पर दिया हुआ है उसमें दी हुई हैं।

डा० सीता रामः नहीं सर, टोटल नहीं दिया हुआ है, मैंने देखा है इसलिए मैं वही जानना चाहता हूं।

श्री मांगे राम गुप्ताः सर, हमारे पास आज 28700 के करीब जे०बी०टी० और मास्टर्ज की वैकेंसीज हैं इसमें से 16900 तो अभी गैस्ट टीचर्ज लगे हुए हैं और 11000 टीचर्ज की आज भी हमारे पास वैकेंसीज हैं इसलिए हमने कहा है कि गैस्ट टीचर्ज हमारे पास सरप्लस नहीं हैं। सर, हमने एच०एस०एस०सी० को इन पोस्ट्स को भरने के लिए कहा हुआ है बहुत जल्दी भर्ती हो जाएगी। इसलिए कोई भी स्कूल ऐसा नहीं रहेगा जिसमें रैगुलर टीचर्ज न हों।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): स्पीकर सर, माननीय मंत्री जी ने जो बात की है मैं आपकी अनुमति से उसको आगे ले जाते हुए सदन को बताना चाहूंगा कि जब मौजूदा सरकार सत्ता में आयी थी तो उस समय अध्यापकों की हजारों पोस्ट्स खाली थी। इन्होंने तो पूरे हरियाणा को अनपढ़ बनाने का काम किया हुआ था। हमारे मुख्यमंत्री थी। ने फौरी तौर पर 16 हजार गैस्ट टीचर्ज की भर्ती करवायी है। उस समय तीस हजार टीचर्ज की वैकेंसीज खाली थी। इन्होंने जो टीचर्ज लगाए थे उनकी डिग्रियां भी आज तक नहीं मिल रही हैं इसलिए उनकी जांच चल रही है। इन्होंने फर्जी तरीके से सब अपने कार्यकर्ता टीचर्ज लगाए थे। ये उस समय तीस हजार वैकेंसीज खाली छोड़कर गए थे इसलिए इन्होंने तो पूरे हरियाणा को अनपढ़ बनाने का काम किया था। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार ने दोबारा से हरियाणा को शिक्षित करने की एक नयी पहल की है लेकिन इसमें भी

इनको पीड़ा है कि क्यों यह सरकार हरियाणा को शिक्षित कर रही है, क्यों हरियाणा के लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं।

डा० सीता रामः स्पीकर साहब, ये अपनी नाकामियों को छिपा रहे हैं। (विघन)

डॉ० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, ...

डा० सीता रामः अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्षः ये जो कुछ कह रहे हैं उसे रिकार्ड न किया जाए। सीता राम जी, एक बार आप प्रैस गैलरी की तरफ देखते हो फिर बोलते हो, फिर वहां देखकर फिर बोलते हो। (शोर एवं व्यवधान) कोई चाहे या न चाहे, डैमोक्रेसी में प्रैस का एक अहम् रोल है। बिजली मंत्री (जी रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि मेरे काबिल साथी प्रैस की आजादी की बात करते हैं। इनके नेता ने सिरसा के सारे पत्रकार काल कोठरी में बंद किए थे। (शोर एवं व्यवधान) ये यह भी बताएं कि परमानंद गोयल की हत्या किसने करवाई थी। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Indora ji, I understand this but behave properly. You can raise your point in a responsible manner. मेरे लिए 90 के 90 विधायक बराबर हैं।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, सीता राम जी ने जो प्रश्न किया है कि शिक्षा एक बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण

विषय है और इसमें सरकार की चिंता होनी चाहिए। कोई भी बच्चा पड़े बगैर न रहे। गांव–गांव में स्कूल खोले जाएं, अपग्रेड किए जाएं और टीचर्ज लगाए जाएं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के कार्यों के बारे में तो इन्होंने कमी महसूस की है। मैं लांछन की बात नहीं करता लेकिन मैं इनके समय का जिक्र करना चाहूंगा कि मेवात जो हमारा सबसे पिछड़ा हुआ एरिया है वहां पढ़ाई के हिसाब से सबसे कम ऐवरेज है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः मेरा ऐसा मानना है कि अपोजीशन का भी उतना ही अहम् रोल है जितना कि ट्रेजरी का है। आप 54 मिनट बोले और 19 मिनट तक रामफल चिढ़ाना बोले।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, इनके समय में 2001 से 2004–05 तक मेवात में इन्होंने ईवन सिंगल स्कूल भी अपग्रेड नहीं किया। हमारी सरकार के समय में वर्ष 2005–06 में और वर्ष 2008–09 में मेवात के एरिया में 172 स्कूलों को अपग्रेड किया गया है। अगर सारे हरियाणा की बात करें तो इनकी सरकार के समय में कुल 817 स्कूल अपग्रेड किये गये थे जबकि वर्तमान सरकार के समय में 1727 स्कूलो को अपग्रेड किया गया है। पहले स्कूल अपग्रेड होते हैं उसके बाद टीचर्ज की पोस्ट सैंक्शन होती हैं और उसके बाद टीचर्ज की भर्ती की जाती है। हम क्वालिफाईड टीचर्ज को लगायेंगे। यह सरकार इस बारे में पूर्ण तौर से चिंतित है। सरकार का प्रयास है कि हरियाणा का कोई भी गरीब से गरीब बच्चा भी अनपढ़ न रहे। मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष को शिक्षा का

वर्ष मनाने के बारे में घोषणा की थी, मैं यह बात अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि जितनी फैसिलिटीज आज हरियाणा सरकार ने गरीब से गरीब बच्चों को दी हैं उतनी सारे हिन्दुस्तान में कहीं पर भी नहीं हैं। यही कारण है कि आज हरियाणा में कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रह सकता है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार के समय में जो जे०बी०टी० टीचर्ज लगाये थे उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इनके नेता और उनके बेटे को चार्जशीट किया हुआ है। सारा रिकार्ड वहां गया हुआ है।

श्री एस०एस० सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपना जवाब देते हुए कहा है कि गैस्ट यईचर्ज से पूछा गया और विधायकों की राय लेने के लिए आमंत्रित किया है और इस बारे में लीगल राय ली जायेगी। गैस्ट टीचर्ज को रैगुलर करने के बारे में कोई न कोई तरीका सरकार निकालने का प्रयास कर रही है। अध्यक्ष महोदय, सरकार के पास तो ऐडवोकेट जनरल है, सब कुछ अवेलेबल है जो कानूनी परामर्श दाता है। सुप्रीम कोर्ट में वे भी सरकार के पास मौजूद हैं सरकार के लिए तो यह बहुत ही मामूली बात है आप उनको बुलाकर डिस्कस कर लीजिए और इस बारे में कोई तरीका निकाल लें कि सरकार इस मामले में क्या कर सकती है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष जी, सुरजेवाला साहब को भी उस मीटिंग में शामिल कर लो।

श्री मांगे राम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, हमने गेस्ट टीचर्ज को बुलाकर पूछा उनको पूरा आफर दिया। एक मीटिंग इस बारे में बुलाई और उनको कहा कि we are ready for you सरकार अपनी तरफ से पूरा इस मामले को एग्जामिन कर रही है। ली डिपार्टमैंट के ली आफिसर हमारे साथ बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक लेटैस्ट डिसीजन इस बारे में आया हुआ है। गैस्ट टीचर्ज भी हमारे सामने सैटिस्फाई होकर गये हैं और उनकी जो जायज मांगे थी वे सभी सरकार ने मान ली हैं। इस बारे में भी सरकार पूर्ण रूप से विचार कर रही है।

श्री साहिदा खान: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे मेवात के हैडक्वार्टर नूंह में आज तक गवर्नमैंट सीनियर सैकेण्डरी स्कूल नहीं हैं। माननीय मंत्री जी शिक्षा के बारे में बड़ी–बड़ी बातें कर रहे हैं। इसी प्रकार से मेवात हल्के में छायसा गांव जो अब हथीन हल्के में चला गया है वहां पर 22 गैस्ट टीचर्ज लगाये गये थे। जिनमें से वहां के स्थानीय तो 4–5 ही हैं और उन पर हमेशा से तलवार लटकती रहती है कि जब भी सर्विस सैलेक्शन बोर्ड से नये रैगुलर टीचर्ज 'आयेंगे तो उनकी नौकरी चली जायेगी इस कारण से वे न तो बच्चों को ठीक प्रकार से पढ़ा सकते हैं क्योकि उनकी मानसिकता हमेशा ऐसी रहती है कि पता नहीं कब उनकी नौकरी

चली जाये, कोई टीचर्ज अगर ट्रांसफर करवा कर आ गये तो उनकी नौकरी चली जायेगी। इसलिए उन गैस्ट टीचर्ज को सरकार पक्का करने का कोई स्थाई समाधान बतायें। We are ready for it.

श्री अध्यक्षः साहिदा जी, सदन के नेता ने गैस्ट टीचर्ज के बारे में एक बात कही थी शायद आपने वह ठीक प्रकार से सुनी नहीं।

श्री साहिदा खानः अध्यक्ष महोदय, रअच्छा काम करेंगे तो हम प्रशंसा करेंगे। यह एजुकेशन का मामला है।

श्री अध्यक्षः इस बारे में सदन के नेता ने घोषणा कर दी है। आपका सवाल क्या

श्री साहिदा खानः अध्यक्ष महोदय, जो गैस्ट टीचर्ज लगाये हैं वे उस एरिया के तो लगाये नहीं बाहर के ही लगाये हैं। शनिवार आता है तो वे भागने की कोशिश करते हैं। सोमवार शाम को पहुंचते हैं। छः दिन के सप्ताह में से चार दिन ही रहते हैं।

श्री अध्यक्षः आप जिनको वहां लगवाना चाहते हैं उनके नाम मुझे दे देना।

श्री साहिदा खानः अध्यक्ष महोदय, ठीक है, आपका धन्यवाद।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, केवल नूह को ही नहीं बल्कि जैसा हमने कहा है कि हमने पूरे मेवात को शिक्षा के

क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इनकी सरकार के समय का तो मैंने बता ही दिया है कि इनकी सरकार ने अपने समय में एक भी स्कूल अपग्रेड नहीं किया था। हमने तो 172 स्कूल अपग्रेड किए हैं। जहां तक प्रोपर नूंह की बात है तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि हमने मेवात को शिक्षा के क्षेत्र में डिवैल्प करने के लिए मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड अथोरिटी को यह पावर दे दी है कि वह मेवात में जहां भी स्कूल खोलना चाहे खोल सकती है और जहां टीचर्स भर्ती करना चाहे, कर सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधायक जी को बताना चाहूंगा कि नूंह में जल्दी ही हम हायर सैकेण्डरी स्कूल खोलने जा रहे हें।

श्री साहिदा खानः अध्यक्ष महोदय, वहां बिहार और यू०पी० के टीचर्स ही लगाए जाते हैं। मेवात का एक भी टीचर नहीं लगता।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जहां तक गैस्ट टीचर्स की इन्होंने वात की है कि गैस्ट टीचर्स कच्चे हैं और उन्हें हटा देते हैं। हमने गैस्ट टीचर्स का कोई डर बाकी नहीं छोड़ रखा। जो गैस्ट टीचर्स आलरेडी हैं उनको डर था कि रैगुलर टीचर्स आएंगे तो हमें हटा देंगे। इस समस्या का हमने हल निकाल दिया है। हमने कहा है कोई भी गैस्ट टीचर जिसकी 6 महीने की सर्विस एज ए गैस्ट टीचर हो गई है, उसका करैक्टर अच्छा है और उसकी ऐजुकेशन अच्छी है तो उसको रैगुलर भर्ती करेंगे तथा किसी भी गैस्ट टीचर

को रिलीव नहीं करेंगे। यदि उसके स्थान पर कोई रैगुलर टीचर आ गया तो हम उस गैस्ट टीचर को किसी दूसरी जगह जहां सीट खाली है, वहां लगाएंगे और उसको अपनी च्वाइस का स्टेशन देकर उसकी रैगुलर भर्ती करेंगे। किसी को हटाने का कोई डर बाकी नहीं रह गया।

श्री ईश्वर सिंह पलाकाः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बता रहे थे कि बहुत से स्कूल अपग्रेड किए गए हैं तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि रादौर विधान सभा क्षेत्र में कितने स्कूल अपग्रेड किए गए हैं? मंत्री जी यह भी कह रहे हैं कि गैस्ट टीचर्स सैटिसफाई होकर गए हैं। यदि गैस्ट टीचर्स सैटिसफाई होकर गए हैं तो उनका प्रमोशन करने का तो कोई मतलब ही नहीं था। जब पक्के ही करने थे तौ कमेटी बनाने का क्या औचित्य था, इस बारे में सरकार एकदम से आदेश जारी करे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः पलाका जी, आपका प्रश्न हो गया कि रादौर विधान सभा में कितने स्कूल अपग्रेड किए गए हैं और जहां तक आपने गैस्ट टीचर्स की बात की तो गैस्ट टीचर्स के बारे में मुख्यमंत्री महोदय बता चुके हैं। मंत्री जी, क्या यह बताना पौसीबल है कि रादौर में कितने स्कूल अपग्रेड किए गए हैं?

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पाई कांस्टीच्यूएंसी का था। 90 हल्कों की डिटेल मेरे पास नहीं है। 90

हल्कों की बात मैं यहां नहीं बता सकता, 90 हल्कों की बात ऑन रिकार्ड कहनी पड़ेगी इसलिए ये लिखकर अपनी डिमांड भेज दें इनको जवाब भेज दिया जाएगा।

श्री नरेश यादवः अध्यक्ष महोदय, गैस्ट टीचर्स के बारे में मुख्यमंत्री महोदय जी ने बता दिया। पिछले दिनों जो रैगुलर भर्ती हुई उस वजह से स्कूलों के गैस्ट टीचर्स या लैक्चरार जिनका दो–दो या ढाई–ढाई साल को ऐक्सपीरियंस हो गया था,. उनको हटा दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि जिन टीचर्स का दो या ढाई साल का ऐक्सपीरियंस हो गया था और उनको हटा दिया गया था, अब उनमें बहुत चिंता बनी हुई है इसलिए उनको जल्दी समायोजित कर लिया जाए।

श्री अध्यक्षः यादव जी, वह बात आ गई। शायद आप यहां थे नहीं जब मुख्यमंत्री महोदय ने इस बारे में सदन में आश्वासन दिया था।

श्री नरेश यादवः अध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी निवेदन है कि राजस्थान में भी पोलिसी बनाकर 25 हजार टीचर्स समायोजित किए गए हैं। उसी तरह यहां भी गैस्ट टीचर्स समायोजित किए जाएं तो ठीक होगा।

Mr. Speaker: Yadav Sahib, there is no use of repetition of things. मुख्यमंत्री जी ने सदन में इस बारे में

आश्वासन दिया है उस समय शायद आप यहां नहीं थे। उनकी यह बात कल अखबार में भी आ जाएगी आप पड़ लेना।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, गैस्ट टीचर्स के लिए 3 महत्वपूर्ण रिलीफ दिए गए हैं। पहला रिलीफ तो रैगुलर भर्ती करने के लिए टीचर्स के लिए जो सैट टैस्ट पास करना जरूरी किया है उस सैट टैस्ट के एग्जाम से इन गैस्ट टीचर्स को ऐगजैम्ट किया गया है और उनको ऐज फैक्टर में भी ऐग्जम्पशन दे रहे हैं जिन गैस्ट टीचर्स की सर्विस 6 महीने से ज्यादा चौन गई है! उन सूखको हम नहीं हटा रहे हैँ तथा उनकी रैगुलर भर्ती कर रहे हैं उनको रैगुलर करने में हम प्रैफरैंस दे रहे हैं और कोई तरीका निकाल रहे हैं कि उनको हम रैगुलर कर सकें।

ताराकिंत प्रश्न संख्याः 1210

(इस समय माननीय सदस्य श्री भूपिन्द्र चौधरी सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया।)

Un-even level of the Pohar Minor

***1090. Dr. Sushi! Indora:** Will the Irrigation Minister be pleased to state whether any complaint has been received by the Government about the uneven level of the Pohar Minor near the Musli Gond; if so, whether any enquiry has been got conducted by the Government in this regard ?

Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav): No Sir, there is no Pohar Minor. However, there is Poharkan Sub

Minor, which is a katcha Kharif Channel. This channel was constructed by the contractor as per design levels, which were checked by the Department after construction. However, due to blown up sand, the channel got silted up by about 1.0' from RD 1000' to 5000'. This channel will be got desilted at the cost of contractor before the Kharif season.

डा० सुशील इदौराः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि उनको जो यह जानकारी उनके विभाग द्वारा दी गई है वह निराधार है। हकीकत में शेखूखेडा के पास से जो नहर निकलती है वह शेखूखेडा, हुमायूंखेडा, मूसली और पोडका गांवों के पास से निकलती है। यह ठीक है कि यह कच्चा सब–माईनर है इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वे लैवलिग को किस प्रकार से ठीक करवायेंगे?

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि मौजूदा सरकार ने सबसे बड़ा काम 68.69 करोड़ रुपये की लागत से ओटू लेक की खुदाई का काम किया है और बरसात के दिनों में हमने लगातार चार महीने तक वहां पर पानी चलाया। माननीय सदस्य की जब सरकार थी तो उसेने ओटू झील के बारे में कुछ नहीं किया था। इनकी सरकार के समय में घग्गर नदी के जितने भी चौनल थे वे सारे बंद हो चुके थे लेकिन मौजूदा सरकार ने आकर उनको चालू करवाया। हमने ओटू झील की खुदाई का 25 परसैंट काम पूरा कर

दिया है और इस पर कुल खर्च लगभग 1650 करोड़ रुपये किया गया है। स्पीकर सर, ये जो पोहर माईनर है इस पर तकरीबन 41 लाख की लागत से यह काम किया गया था। यह काम समय पर पूरा हो गया था। कुछ काम रह गया था जो कि धनीपुर कोआपरेटिव सोसायटी नामक कम्पनी ने पूरा कर दिया था। यह कच्चा चौनल है और इसके अंदर काफी रेत है जिस कारण वह मिट्टी से भर गया था। मैं माननीय सदस्य को ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस यह आश्वासन देना चाहता हूं कि खरीफ का सीजन शुरू होने से पहले हम उसकी सफाई करवा देंगे। हमने इस उद्देश्य के लिए साढ़े तीन लाख रुपये कैट्रक्टैर के रोक लिये हैं जबकि यह काम सिर्फ 70 हजार का है। हम खरीफ सीजन क्ष होने से पहले इस चौनल को साफ करवाकर इसमे पानी भी चलवा देंगे।

डॉ० सुशील इन्दौराः स्पीकर सर, जिस प्रकार से पोहर सब–माईनर की बात है वह कच्ची है ड्सी प्रकार से खारिया से लेकर ननवाना होते हुए बनी माईनर के साथ–साथ एक कच्ची फ्लडी नहर निकाली है, मेरी जानकारी के हिसाब से उस पर पुल भी बन गये हैं लेकिन उसमें अभी तक पानी नहीं छोड़ा गया है। जैसे कि सभी जानते हैं कि किसान को पानी की सख्त जरूरत है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उसमें कब तक पानी छोड़ा जायेगा?

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जब बरसात का मौसम आयेगा और ओटू झील में पानी भरेगा तो सभी संबंधित चौनलों में पानी आ जायेगा। स्पीकर सर, इन्हें मौजूदा सरकार का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि इनकी सरकार के समय में तो ओटू झील के बारे में कुछ भी नहीं किया गया। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने वाटर बॉडीज के बेहतर प्रबन्धन के लिए अनेक कदम उठाये हैं। स्पीकर सर, वहां के किसान सरकार के इस काम के लिए सरकार का गुणगान कर रहे हैं ' हमने चार महीने तक उन चौनलों में पानी चलाया है।

Repair of roads in Bhiwani

***1068. Dr. Shiv Shankar Bhardwaj:** Will the P.W.D. (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the roads damaged during the recent floods in Bhiwani, if so, the time by which the said roads are likely to be repaired ?

Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav): Sir, out of a total road length of 145.26 km. belonging to PWD B&R in Bhiwani Constituency, road length of 18.49 km. is reported to be affected by floods. Repair works on road length of 12.067 km. have already been allotted on 01.12.2008 to a contractor who is likely to complete the same by 30.06.2009.

10.00 बजे

डॉ० शिवशंकर भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने यह रिपेयर का काम शुरू करवा दिया है। अध्यक्ष महोदय, रोड खराब होने के कुछ कारण हैं जब तक उनका निवारण नहीं होगा तब तक रोड ठीक नहीं रह सकती।

श्री अध्यक्षः भारद्वाज साहब, आप स्पेसिफिक प्रश्न पूछिए। कारणों के बारे में न बतायें इसके लिए इनके पास टैक्नीकल इंजीनियर होते हैं। ये अपने–आप उन कारणों का पता भी लगा लेंगे और उनको रिफ्ट करने का भी इनको पता है। आप स्पेसिफिक प्रश्न पूछिये।

डॉ० शिव शंकर भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, मैं स्पेसिफिक प्रश्न ही पूछ रहा हूं। एक तो रोड के साथ ड्रेनेज सिस्टम नहीं है जिसके कारण रोड जल्दी टूटती हैं। दूसरा कारण है डिफैंट डिपार्टमैंटूस का 'आपस में तालमेल न होना। पी०डब्ल्यू०डी० (वी० एण्ड आर०) रोड बना देता है और पब्लिक हैल्थ विभाग वाले मे रोड को खोद देते हैं जिससे रोड जल्दी टूटती हैं तथा सरकार का पैसा खराब होता है और तीसरा कारण है बाई–पास का न होना। यह रोड शहर के वीच से जाती है जिसके कारण ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होता।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने जिक्र किया है कि रोड्स के किनारे ड्रेनेज सिस्टम नहीं

है तो जहां पर ड्रेनेज की दिक्कत है वहां हम नाली बनवा देंगे। इनके हल्के में बरसात के कारण 1949 किलोमीटर सड़क खराब हो गई थी। हमने इनके हल्के में 73.19 किलोमीटर और सड़क के लिए टैंडर किए हैं और बाकी बची 65 किलोमीटर सड़क को भी उसमें इनकल्यूड कर दिया है और उसके भी टैंडर हमने मंगवा दिए हैं। सर, इनकी 19.49 किलोमीटर सड़क की पूरी रिपेयर हम करवायेंगे। अध्यक्ष महोदय, इनकी दूसरी मांग थी तालमेल की, तो वह भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि विभागों में तालमेल हो।

श्री अध्यक्षः कैप्टन साहब, माननीय सदस्य की यह बात बिल्कुल वाजिब है कि विभागों का आपस में तालमेल न होने की वजह से रोड जल्दी टूटती हैं। बी०एण्ड आर० रोड बना देता है और बाद में पब्लिक हैल्थ वाले उसको खोद देते हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, हम तालमेल करने की पूरी कोशिश करेंगे।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि इन्द्री से करनाल सड़क पर बजरी और रेत से भरे ट्रक/ट्रालियों का बहुत हैवी ट्रैफिक रहता है उसकी हालत बहुत खराब है। तीन शुगर मिल लगते हैं। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उस रोड को बनवाने का कोई प्रावधान है?

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, चूंकि इन्द्री से करनाल की सड़क एक क्वेरी रोड है इसलिए उसको हम बी०ओ०टी० बेसिज पर लेने के लिए बातचीत कर रहे हैं। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मौजूदा सरकार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2700 किलोमीटर की रोड्स की वाइडनिग और स्ट्रैन्थनिंग का काम कर रही है जिस पर तकरीबन 1102 करोड़ रुपए की लागत आयेगी। नाबार्ड के तहत 1020 किलोमीटर पर तकरीबन 502 करोड़ रुपये की लागत से हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से एन०सी०आर० में 825 किलोमीटर की हम रिपेयर कर रहे हैं तथा सी०आर०एफ० के तहत 492 किलोमीटर की रिपेयर कर रहे हैं। कुल मिलाकर 4900 किलोमीटर पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत काम चल रहा है। 3850 करोड़ रुपये की लागत से हम सड्कों की स्ट्रैन्थनिंग के लिए काम कर रहे हैं। पूरे राज्य में तकरीबन कुल 23500 किलोमीटर सड़क हैं जिसमें से 12000 किलोमीटर सड़क तो बिलकुल सही है। 6500 किलोमीटर पर हम पहले ही काम कर रहे है वर्क प्रोग्रैस पर है। बाकी बची तकरीबन 5 हजार किलोमीटर सड़क में से 1500 किलोमीटर बहुत ज्यादा खराब है, उसको हम ठीक करवायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मान साहब की जो करनाल से इन्द्री तक की सड़क है, उसको हम बी०ओ०टी० बेसिज पर बनायेंगे।

श्री बलवन्त सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जगाधरी से को अम्बाला रोड जाती है उस पर जी०टी० रोड के बराबर रश रहता है। उस पर बहुत एक्सीडैंट होते हैं। कग इस सड़क को चौड़ा करने का काम सरकार के विचाराधीन है?

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इसके लिए अलग से नोटिस दे दें। इस समय मेरे पास इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

श्री साहिदा खानः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कुछ रोड्ज के बारे में जानना चाहता हूं। मैं जब से विधान सभा में आया हूं मैंने रोड्स के बारे में आवाज उठाई है। रोड्स के मामले में मेवात का जो बुरा हाल है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है।

श्री अध्यक्षः इस बारे में तो कल बात हो गई थी।

श्री साहिदा खानः अध्यक्ष महोदय, कल बात तो हुई थी लेकिन जिन रोड्स की जानकारी मुझे है जो टूटे हुए हैं, मैं माननीय मंत्री जी को उनमें से कुछ रोड्स के नाम बताना चाहता हूं। तावडू से भोगीपुर रोड जाता है।

श्री अध्यक्षः रिपेयर होनी है क्या?

श्री साहिदा खानः हां सर रिपेयर ही होनी है, नई सड़क तो हमारे हिस्से आती ही नहीं।

श्री अध्यक्षः आप लिख कर भिजवा देना। वैसे तो मंत्री जी ने बता दिया है कि इतनी सड़कें रिपेयर हो चुकी हैं और करीब 6000 सड्कों की रिपेयर का काम चल रहा है। आप लिख कर भिजवा दें, मंत्री जी आपके हल्के की खराब सड्कों की भी रिपेयर करवा देंगे।

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी से कहना चाहूंगा कि ये लिख कर भिजवा दें इनकी जो सड़कें खराब हैं वह हम ठीक करवा देंगे (विघ्न)

डा० शिव शंकर भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, भिवानी में जीतू वाला फाटक से लेकर दिनोद बाईपास तक बहुत छोटा सा सड़क का टुकड़ा है। इसके इधर भी बी०एण्ड आर० की सड़क है और उधर भी बी० एण्ड आर० की सड़क है। करीब पांच सौ गज यह टुकड़ा हे। अगर यह टुकड़ा बी० एण्ड आर० विभाग ले ले तो पूरी सड़क बी० एण्ड आर० विभाग की हो जाएगी और सारी समस्या भी हल हो सकती है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर सर, हम इसको एग्जामिन करवा लेंगे। इनसे पहले अम्बाला से जगाधरी वाली सड़क के बारे में माननीय साथी ने जो बात कही थी इसके बारे में वर्ल्ड बैंक की अस्सिटैंस लेकर हुसको भी हम चौड़ा करवाएंगे।

जगाधरी–अम्बाला रोड की मरम्मत भी करवाएंगे और उसकी वाईडनिग भी करवाएंगे।

Veterinery Hospital at Noorsar Talab

***1085, Sh. Bachan Singh Arya:** Will the Animal Husbandry & Dairy Minister be pleased to state--

(a) Whether it is a fact that the building of Veterinary Hospital Noorsar Talab at Safidon city was got constructed by the farmers with their own funds and it was registered in the name of Government ;

(b) Whether it is also a fact that the said Hospital was inaugurated on 17.11.1981 by the then Animal Husbandry Minister and thereafter the doctor posted there was withdrawn after two months ; and

(c) if so, the time by which the appointment of doctor and regularization of said Hospital will be made ?

Agriculture Minister (Sardar H.S. Chatha)

(a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) A Government Veterinary Hospital is already functioning in Safidon town and Noorsar Talab is part of the town. As per policy of the Government, two Veterinary institutions cannot be sanctioned in one place.

श्री बचन सिंह आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री, महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पहले मैंने

जो सवाल पूछा था उसके लिए मंत्री जी ने ही कहा है उसके लिए इनका धन्यवाद। (विघन)

श्री अध्यक्षः आर्य साहब, आपकी स्पैसिफिक सप्लीमैंट्री क्या है?

श्री बचन सिंह आर्यः स्पीकर सर, मेरा स्पैसिफिक सवाल यह है कि जब मंत्री जी यह मान रहे हैं कि 17.11.1981 को उस समय के पशु पालन मंत्री श्री शिव राम जी ने उस बिल्डिंग का उद्घाटन किया था। उसकी रजिस्ट्री सरकार के नाम से करवा दी गई है और वह बिल्डिंग भी सरकार को हैंड ओवर कर दी गई है। वहाँ पर पत्थर भी लगा हुआ है यह एक टाउन की बात नहीं है। जैसे कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इसके बीच में नहर आती है जो अस्पताल है वह इस समय मण्डी में है जबकि यह हिस्सा शहर में आता है। वहां पर सिख भाइयों के कम से कम 200–250 डेरे हैं जहां वे रहते हैं वहां पर अनेकों एक्सीडैंट्स हो चुके हैं। वहां पर रेलवे ट्रैक हैं लेकिन वहां पर फाटक नहीं लगा है। अभी चार दिन पहले सफीदों में एक हादसा हुआ था जिसमें पशु ले जाते हुए तीन आदमियों की डैथ हो गई थी। स्पीकर सर, यह मांग बहुत पुरानी है और वहां पर हरियाणा सरकार का पत्थर भी लगा हुआ है। मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि पहले तो वहां पर डाक्टर भी था। सरकार के पास यह डिस्पैंसरी पंजीकृत भी हो चुकी है और मंत्री जी अपने उत्तर में इसको मान भी चुके हैं। वहां

पर इसकी बड़ी जबरदस्त मांग है इसलिए इसको नियमित किया जाए और वहां पर डाक्टर भी बिठाने की कृपा करें।

सरदार एच.एस. चट्ठाः स्पीकर सर, हॉस्पीटल वह नहीं होता जहां पर कमरा खड़ा कर दिया अरि गफ वी०एल०डी०ए० भेज दिया।

श्री अध्यक्षः मंत्री जी, सरकार ने इसे मान लिया है और होस्पीटल को रजिस्टर्ड कर लिया है। इसमें बिल्डिंग का तो क्वैश्चन ही नहीं है because hospital has been recognized by the Government.

सरदार एच०एस० चट्ठाः स्पीकर सर, मैं वही बताने लगा हूं यह recognized नहीं है (विघ्न) 1992 में लेट श्री हरमिन्द्र सिंह जी ने वहां जाकर इसका उद्घाटन किया या। यह कोई रिकोग्नाईज्ड नहीं था दूसरे होस्पीटल से एक वी०एल०डी०ए० वहां भेज दिया था, जो वहां पर जाता रहा और कॉन्टीन्यू रहा। सर, यह म्यूनिसिपल कमेटी के एरिया में है। जब यह गवर्नमैंट आई तो इस सरकार ने यह फैसला किया कि इसे बंद कर दिया जाए क्योंकि वहां पर सिर्फ एक कमरा और एक बरामदा है। वहां पर रहने का कोई इन्तजाम नहीं है। इस सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी कि सारी स्टेट में एक शहर में एक ही होस्पीटल होगा और वह होस्पीटल बड़ा होगा। जहां तक इनकी डिमाण्ड है कि रास्ते में रेलवे फाटक है, शहर बड़ा है। सफीदों शहर कितना बड़ा है यह आप जानते ही हैं। इनके हल्के में 48 होस्पीटल्ल हैं। मेरे

ख्याल से पूरे हरियाणा में इतने होस्पीटल्ज और किसी एरिया में नहीं होंगे। 48 में से 18 होस्पीटल्ज हैं और 50 डिस्पैंसरियां हैं नार्मली दूसरे हल्कों में इतने होस्पीटल्ज और डिस्पैंसरियां नहीं हैं। अगर फिर भी इनको तसल्ली नहीं हे तो मैं गवर्नमैंट की पालिसी नहीं बदल सकता हूं।

श्री बचन सिंह आर्यः अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मंत्री जी मान चुके हैं और मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि गांवों की बात नहीं है, जो पुराने शहर हैं वहां पर लोग खेती करते हैं और सफीदों शहर पुराना शहर है और बहुत बड़ा है, वहां पर 40 हजार की आबादी है। जिस होस्पिटल की बात मंत्री जी कर रहे हैं वह तो मण्डी से परले पार है उसमें 3 किलोमीटर का अन्तर है। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास रजिस्ट्री भी है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर 2–2 पशुपालन मंत्री जी जा चुके हैं।

श्री अध्यक्षः इसमें आप यह पूछो कि अकॉर्डिंग दू दि नार्मज ऑफ दि गवर्नमैंट, क्या वहां पर हास्पिटल की बिल्डिंग बन जाएगी? आर्य जी, वहां पर हास्पिटल नहीं है वहां पर एक कमरा और बरामदा है।

श्री बचन सिंह आर्यः अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि वहां पर एक कमरा नहीं है। वहां पर लोगों ने चन्दा इक्ट्ठा करके दो बहुत बड़े कमरे बनवाए हुए हैं, आगे बरामदा है और चार दीवारी वहां पर किसानों ने करवाई हुई है। आप वहां

पर मौके पर जाकर देखें कि वहां पर हौस्पिटल का पत्थर लगा हुआ है। वह पत्थर 17.11.1998 को पशु पालन मंत्री शिवराज वर्मा जी ने लगाया था। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि इसको तुरन्त बनवाने की जरूरत है।

श्री अध्यक्षः चट्ठा साहब, अगर नार्मज मे है तो वहां पर हौस्पीटल बनवा देना। आर्य जी, आप इस बारे में मंत्री जो को लिखकर भिजवा दें।

Sardar H.S. Chatha: Sir, 1 am very sorry to say, I can't start second hospital in the same city.

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मैत्री जी से जानना चाहती हूं कि पिछली सरकार के वक्त में कई जगहों पर बिल्डिग्ज बना कर छोड़ दी गई थी। ऐसा कलायत में भी है कि कई जगहों पर बिल्डिंग्ज बनी हुई हैं। क्या वहां पर नई पोस्ट्स सैंक्शन होगीं और जैसे मेरे यहां पर खेड़ी लाम्बा है, खेड़ी शेरखा गांव है वहां पर वैटरनरी सर्जन की कमी है। क्या यह सरकार वहां पर नई भर्तियां कर रही है?

सरदार एस०एस० चट्ठाः अध्यक्ष महोदय, बहन जी का सवाल बिल्कुल सही है कि पिछली सरकार ने तो ऐसे फैसले कर दिए थे जिन पर इम्पलीमैंट करना ही बहुत मुश्किल है। उन्होंने एक कमरा और एक बरामदा बना दिया और कह दिया कि हमने हास्पिटल बना दिया। अध्यक्ष महोदय, अगर वी०एल०डी०ए० डिस्पैंसरी में लगाना है तो वहां पर वी०एल०डी०ए० के लिए क्वार्टर

भी चाहिए, दो क्लास फोर के लिए कमरे भी चाहिएं। मिनिमम एक एकड़ जमीन चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अगर एक चूक में हास्पिटल बना दो तो वह हास्पिटल नहीं होता है। हमारे सी०एम० साहब ने 80 हास्पिटल्ज/डिस्पैंसरीज बनाने की परमिशन दी है या तो ये नए बनाए जाएंगे या अपग्रेड किए जाएंगे। उनकी लोकेशन का फैसला अभी नहीं हुआ है।

श्री आनंद सिंह दांगीः स्पीकर सर, पहले सभी बड़े हॉस्पिटल्स में दो–दो वी०एल० डी०एज० की व्यवस्था होती थी लेकिन सरकार ने एक वी०एल०डी०ए० वापिस ले लिया है। लेकिन जिन गांवों की आबादी 25–25 हजार की है और वहां के लोगों का मेन धंधा ही पशुओं का है। उसमें एक वी०एल०डी०ए० से काम नहीं चलता है। कम से कम पहले का जो सैटअप था, उसी प्रकार से वहां पर व्यवस्था करनी चाहिए। डिसपैंसरीज में तो एक वी०एल०डी०ए० चलेगा लेकिन जहां पर हॉस्पिटल हैं वहां पर दो वी०एल०डी०ए० का होना जरूरी है। स्पीकर सर, मेरी कास्टीयुएँसी के दो गांव मोखरा और निदाना हैं उनमें हास्पिटल भी है और अलग से डिसपैंसरी भी बनी हुई है पहले वहां पर वी०एल०डी०ए० बैठता था लेकिन अब वह विदड्रा हो गया है। आप इस बारे में कुछ करें।

सरदार एच०एस० चट्ठाः स्पीकर सर, इनकी बात दुरुस्त है। इस बात पर विचार किया जाएगा कि जो बड़े हॉस्पिटल्ल हैं वहां पर और स्टाफ दिया जाएगा।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मानः स्पीकर सर, कैथल जिला मुर्राह ब्रीड की डिवैल्पमैंट के लिए इंक्लूड कर लिया गया है। मंत्री जी ने जैसा बताया है कि वहां 90 होस्पिटल्ल/डिस्पैंसरीज और खोलेंगे। स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि हर गांव में डिस्पैंसरीज हों। हमारे यहां पर बहुत कैटल वैल्थ है।

सरदार एच०एस० चट्ठाः सर, अभी पॉलिसी तो बनाई नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मान साहब की सैटिसफैक्शन हो।

श्री देवेन्द्र कुमार बंसलः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि अम्बाला में जो वैटरनरी हास्पिटल है वहां पर एक ही कमरा है और सिर्फ एक ही डाक्टर है। अगर वहां पर कोई पशु बीमार हो जाता है तो हमें पशुओं के इलाज के लिए कभी पंचकुला जाना पड़ता है और कभी लुधियाना जाना पड़ता है।

सरदार एच०एस० चट्ठाः स्पीकर सर, ऐसी कोई बात नहीं है अगर ये करने शौक के लिए अम्बाला छावनी से पशुओं को इलाज के लिए पंचकूला ले आए तो वह इनकी मर्जी है। अम्बाला शहर में वैटरनरी अस्पताल है इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। अगर थोड़ी पर ये बैठकर पंचकूला आना चाहें तो वह अलग बात है।

श्री देवेन्द्र कुमार वैसलः सर, वहां के वैटरनरी होस्पीटल में एक कमरा ही है।

श्री अध्यक्षः ठीक है, इनका कहना है कि घोड़ियों पर बैठकर पशुओं को लेकर आते है

श्री देवेन्द्र कुमार बंसलः नहीं सर, ट्रांसपोर्ट करके लेकर आते हैं। एक बार तो मैंने खुद ट्रांसपोर्ट मुहैय्या करवायी है।

श्री अध्यक्षः ठीक है, अब आप बैठें।

श्रीमती अनिता यादवः स्पीकर साहब, हमारे सामने एक छोटी सी समस्या और है। वैसे तो हमारी सरकार ने अभी वैटरनरी डिसपैंसरीज खोलने की बात कही है और वैटरनरी डाक्टर्ज एवं वी०एल०डी०ए० की भर्ती भी की है। जो वी०एल०डी०ए० हरियाणा सरकार ने अभी कुछ समय पहले लगाए थे वे आफिस के समय में अस्पताल में न बैठकर प्राईवेट प्रैक्टिस करते हैं।

श्री अध्यक्षः अनिता जी, यदि आपको इस बारे में कोई सपैसिफिक शिकायत हे तो आप लिखकर भिजवा देना। इंडीविजुअल इम्पलाई ऐबसैंट है वह होस्पीटल में नहीं आता है या इररैगुलर है तो आप लिखकर भिजवा देना।

श्रीमती अनिता यादवः स्पीकर साहब, हर वी०एल०डी०ए० प्राईवेट प्रैक्टिस करके राजी है। वह वैटरनरी अस्पताल में नहीं बैठता है तो क्या सरकार इस बारे में कोई कदम उठाएगी?

श्री अध्यक्षः अगर कोई पटीकुलर वी०एल०डी०ए० आपके ध्यान में है तो आप उसके बारे में लिखकर भिजवा देना। The proper action will be taken.

श्रीमती अनिता यादवः ठीक है जी।

श्री राधे शाम शर्माः स्पीकर साहब, मेरे हल्के में पशु पालन की कुछ डिस्पैंसरीज कच्ची हैं। मैंने इस बारे में मंत्री जी को लिखकर भी भिजवाया था। क्या मंत्री जी इस बारे में ध्यान देंगे?

सरदार एच०एस० चट्ठाः स्पीकर साहब, मैंने अभी विनती की है इसलिए पंडित जी ने समझ ही लिया होगा कि हम 80 डिस्पैंसरीज और अस्पताल अपग्रेड कर रहे हैं इसलिए अब किसी हल्के के साथ भेदभाव नहीं होगा। जिस–जिस इलाके में जरूरत होगी वहां हम डिस्पैंसरीज बना देंगे।

Repair of Roads

***1043. Shri Radhey Shyam Sherma:** Will the P.W.D. (B&R) Minister be pleased to state the time by which the following roads are likely to be repaired—

(a) from Nangal Chaudhary Nizampur road leading to Donkhera road ; and

(b) from Nangal Chaudhary to Gothri and the road leading up to the boundary of village Tasing of Rajasthan

Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav): Sir,

the road at Sr. No. (i) is being repaired and will be strengthened in due course of time. Work of widening and strengthening of road at Sr. No. (ii) has already been allotted on 16-01-2009 to MIS Shivalaya Construction Co. under Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojna and it is likely to be completed by October, 2009.

श्री राधे शाम शर्मा अमरः अध्यक्ष महोदय, मेरे जवाब में जो दूसरी रोड नांगल चौधरी से गोठडी तथा राजस्थान के गांव तसिंग तक जाने वाली सड़क है उसके लिए मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं क्योंकि उस पर काम शुरू हो गया है। मेरे सवाल में जो पहली रोड नांगल चौधरी से निजामपुर सड़क से दोंखेडा तक की रोड है उस पर काम शुरू नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस रोड पर काम कब तक शुरू हो जाएगा?

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर साहब, जो नांगल चौधरी से निजामपुर सड़क से दोखेडा तक रोड जाती है यह 6 किलोमीटर लम्बी सड़क है। 2002 में इस पर कारपेटिंग हुई थी। 2009– 10 का जो हमारा वर्क प्रोग्राम है उसमें हम इस सड़क को इन्कलूड कर रहे हैं। उस वक्त हम इसकी रिपेयर और स्ट्रैंग्थनिंग करवा देंगे।

श्री अमीर चन्द मक्कडः अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी मंत्री जी से दरखास्त की थी कि हांसी से गढ़ी मुंढाल तक जो जी०टी० रोड है उसकी हालत वस्तु खराब है। वहां पर पैदल भी

नहीं चला जा सकता। मैं जानना चाहूंगा कि इसकी रिपेयर कब तक करवा दी जाएगी? इसी तरह से हांसी से उमरा तक जो रोड है वह बनते ही छ महीने में खराब हो गयी थी इसलिए उसकी इंक्वायरी भी हुई थी। मेँ आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या इस बारे में किसी ऑफिसर या ठेकेदार की जिम्मेवारी फिक्स की है और कब तक उस रोड को बनवा देंगे?

Mr. Speaker: Makkar Sahib, it is not possible to give the reply. So, please ask a separate question in this regard.

श्रीमती गीता भुक्कलः स्पीकर सर, मेरे हल्के में कलायत से दाता सिंह वाला तक जो सड़क है उसके टैंडर दो तीन सालों से कई बार काल भी किए जा रहे हैं लेकिन अभी तक भी उसका निर्माण कार्य प्र नहीं हुआ है। इसी तरह से तीतरम से नरवाना तक की सड़क की वाईडनिंग का काम पूरा हो गया है लेकिन खरक पांडव से पिंजपूरा तक दो किलोमीटर का ऐसा टुकड़ा है जिसका निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि कब तक यह काम शुरू हो जाएगा?

कैप्टन अजय सिंह यादवः आप इस बारे में लिखित में दे देना। इसके बाद ही मैं आपको बता सकता हूं कि उसकी क्या स्थिति है।

श्री अध्यक्षः ठीक है भुक्कल जी, आप दोबारा से लिखकर उनको भिजवा देना।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी को पिछले साल भी लिखकर दिया था।

श्री अध्यक्षः क्या आपने पहले कभी इस बारे में पूछा है?

श्रीमती गीता भुक्कलः जी हाँ।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैंने इनको बता दिया है कि हम इसको ऐग्जामिन करवाकर इनको बताएंगे।

प्रो० छत्तर पाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो हिसार में नेशनल हाइवे नं० 66 है, वहां धांसू से सुलखणी तक वाईडनिंग और स्ट्रैंग्थनिंग का काम मंत्री जी ने शुरू करवाया है उसके बारे में डिमांड यह है कि उसे हांसी बरवाला स्टेट जी०टी० रोड है, उस तक लिंक होना चाहिए। दूसरा धिराय गांव से पाबडा से जोधपुर गांव तक वाईडनिंग स्ट्रैंग्थनिंग का काम होना था। इस बारे में भी मंत्री जी को लिखकर दिया हुआ है, उन पर कब तक काम शुरू करवाएंगे?

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, इसके लिए ये अलग से नोटिस दे दें। प्रो० छत्तर पाल सिंहः नोटिस आलरेडी दिया हुआ है।

श्री रणधीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राखी पड़ी से जींद हांसी रोड पर जो सड़क मिलती है उसमें बीच में 2 किलोमीटर का टुकड़ा अभी तक बनाया गया है। पिल्ले सैशन में भी मैंने इस बारे में क्वैशचन लगाया था और उसमें कोर्ट केस था, उसके बारे में क्या स्टेट्स है, यह बताए।

श्री अध्यक्षः कोर्ट केस के बारे में क्या आपको पता नहीं है?

श्री रणधीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, महकमे का मालिकान का कोर्ट केस है। उसके बारे में मुझे पता नहीं है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, इस क्वैश्चन से इसका कोई कनैक्शन नहीं है लेकिन फिर भी माननीय सदस्य लिखित में दें तो कार्यवाही करेंगे।

Losses borne by Haryana Roadways Depot, Gurgaon

***1112 Shri Dharambir Guuba:** Will the Transport be pleased to state the losses borne by Haryana Roadways Depot, Gurgaon during the years 2005-2006. 2006-2007 and 2007-08 ; the number of buses condemned and whether all the norms were kept into consideration ?

परिवहन मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता): श्रीमान जी, हरियाणा राज्य परिवहन के गुड़गांव डिपो द्वारा क्री गई गीन व कण्डम बसों की सँख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

क्र० सं०	वर्ष	अस्थाई हानि (रुपये करोड़)	कण्डम बसों की संख्या
1.	2005-06	-4.24	26
2.	2006-07	-6.15	4
3.	2007-08	-5.17	25

नॉर्म के अनुसार बसों को 6 लाख कि०मी० व 7 वर्ष की अवधि पूर्ण करने के पश्चात् कण्डम किया गया है।

Shri Dharambir Gauba: Speaker Sir, I want to ask three questions.

(a) what are the reasons for the huge loss in the depot No. 1?

(b) has the Government taken any step to minimize the loss?

(c) has the Government will take any action against the officer who was responsible for the loss ?

श्री मांगे राम गुप्ताः सर, हर डिपो में तकरीबन नुक्सान की स्थिति है। गुडगांव की अकेले बात नहीं है। यह ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट कोई प्रौफिट का डिपार्टमैंट अब नहीं रहा। जनता की सेवा करने के लिए सरकार ने बसें चला रखी हैं। इसमें 150 करोड़ रुपये का सालाना नुक्सान है। ऐसी कितनी कैटेगरीज हैं

जिनको कसैशन दिया हुआ है और उस वजह से 150 करोड़ रुपये सालाना का नुक्सान होता है। नुक्सान के और भी कुछ कारण हें। बहुत से कारण तो मुझे पता नहीं है लेकिन कुछ समय से ड्राइवरों और कंडक्टर्ज की कमी रही जिसकी वजह से बसें खड़ी रही। गुडगांव में भी ड्राइवरों और कंडक्टर्ज की कमी रही जिसकी वजह से गुडगांव डिपो में भी बसें खड़ी रहीं और इस वजह से नुक्सान रहा। एक कारण यह भी रहा कि तीन साल से डीजल के रेट बढ़ते चले गए। एक रुपये डीजल के रेट बढ़ने में 75–80 लाख रुपये महीने का नुक्सान हमारा होता था। हमने जब किराया मुकर्रर किया तो उस वक्त डीजल का रेट 28 रुपये कुछ पैसे था और बाद में 23 रुपये तक डीजल का रेट बढ़ गया लेकिन हमने किराया नहीं बढ़ाया इसलिए नुकसान तो होता रहा है। अब भी डीजल के रेट घटने के बाद भी वह नुकसान पूरा नहीं हुआ है। उस नुकसान को घटाने के प्रयास किये हैं। चाहे गुड़गांव हो या दूसरे डिपो हों, जहां पर ड्राइवर्ज और कण्डक्टर्ज नहीं थे उनकी कमी को पूरा करने के लिए हमने ड्राईवर्ज और कण्डक्टर्ज की भर्ती की है। अब हमारी कोई बस ऐसी नहीं है जो बगैर ड्राईवर और कण्डक्टर के खड़ी हो। कोई ब्रेक डाउन हो जाए तो अलग बात है। डीजल के रेट घटने के बाद भी हमें नुकसान हुआ है। जहां तक कन्सैशन देने की बात है इस बारे में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि जो कन्सैशन जनता के इन्ट्रस्ट मैं दिए जाते हें हम उसका ऐतराज नहीं करना चाहते लेकिन जिन विभागों की रिकमैंडेशन पर यह कन्सैशन दिए जाते हैं हमने उसके

बारे में डिमाण्ड रखी है कि जिस विभाग को कन्सैशन दिया जाता है वह विभाग हमें कम्पनसेट करें तो हम समझते हैं कि परिवहन विभाग को कोई नुकसान नहीं होगा।

श्री साहिदा खानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे नूंह सब डिपो में 42 बसें हैं, पूरे हरियाणा में जिन बसों को कण्डम कर दिया गया है वे बसे नूंह सब डिपो में भेजी हुई हैं और आज उन बसों में से 13 बसें बगैर ड़ाईवर और कण्डक्टर्ज के खड़ी हुई हैं जो अधिकारी गुड़गांव में लगा रखे हैं वही मेवात में लगा रखे हैं जो अपनी मन मर्जी से बसों को कभी किसी रूट पर भेज देते हैं और कभी कहीं पर भेज देते हैं।

श्री अध्यक्षः आपका सवाल क्या है?

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मेवात की बहुत बड़ी समस्या यह है कि वहां पर कोई भी ड़ाईवर, कण्डक्टर या कोई अधिकारी अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहा है क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे एलीमैंट्स हैं जो उन ड्राईवर्ज, कण्डक्टर्ज और अधिकारियों को पीटकर भगा देते हैं। सरकार ने इस बारे में प्रयास भी किए हैं पुलिस आफिसर्ज की ड्यूटी भी लगाई है लेकिन यह समस्या बड़ी गम्मीर है इस पर काबू पाना बड़ा मुश्किल है। मैं आदरणीय विधायक जी से कहूंगा कि अपने

उन ऐलीमैंट्स को रोको, जिनको तुमने हवा दे रखी है। सरकार को बदनाम करने के लिए उन आदमियों को वहां बैठा रखा है।

श्री अध्यक्ष: साहिदा खान जी, आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं आप उनको समझा सकते हैं।

Repair of roads in Tehsil Narnaul

***1206. Shri Naresh Yadav:** Will the P.W.D. (B&R) Minister be pleased to

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the approach roads of the villages falling in tehsil Narnaul keeping in view the bad condition of the said roads ;

(b) if so, the time by which the said roads will be repaired togetherwith the details of such roads ; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the new roads in district Mahendergarh ; if so, the details thereof.

Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav):

(a) & (b) 10 roads having length of 26.32 kms have already been repaired during the year 2008-09. 9 roads having length of 36.63 kms. have been further taken up for repairs and the tenders for the same have been received on 6.2.2009. The works are likely to start by March, 2009 and are expected to be completed by September, 2009.

(c) Work on construction of 8 new roads having a

total length of 18.15 kms. is in progress.

श्री नरेश यादवः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिला महेन्द्रगढ़ में कौन–कौन सी सड्कों और गांवों के एप्रोच रोड्ज हैं जौ अब तक ठीक की गई हैं? मेरा स्पेसिफिक क्वैश्चन है।

श्री अध्यक्षः आपका एक्सीडैंट हुआ है इसलिए आपको पता होगा रोड्ज ठीक हैं या नहीं?

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर सर, माननीय सदस्य के हल्के अटेली में टोटल 271 किलोमीटर की सड़क है, जिसमें से 63 किलोमीटर सड़क की रिपेयर कर दी गई थी और 56 किलोमीटर सड़क पर सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना' के तहत काम करवा रखा है तथा 15 किलोमीटर सड़क सी०आर० एफ० के तहत ठीक की गयी है। इस सरकार के शासन काल में 51 करोड़ रुपये माननीय सदस्य के हल्के की सड्कों को ठीक करने के लिए लगाये गए हैं।

श्री नरेश यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि मंत्री जी एक गांव का नाम बतायें जिसकी सड़क ठीक करवाई हो।

कैप्टन अजय सिंह यादवः हमने बेवल से खुराना–खुरानी की सडक के टैण्डर इन्वाईट किए हुए हैं। अटेली से खेड़ी, खेड़ी से रामपुरा की सड़क के टैण्डर भी बुला रखे हैं

जो टोटल 36.63 किलोमीटर सड़क को बनाने के लिए 6.2.2009 को खोले गये हैं।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the question hour is over.

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

I.T.I. at Kushak

***1124. Shri Udai Bhan:** Will the Industrial Training & Vocational Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open an I.T.I. at Kushak in Hassanpur constituency ; if so, the time by which the said is likely to be opened ?

शहरी विकास मंत्री (श्री ए०सी० चौधरी): हां! श्रीमान जी, इस आई०टी०आई के भवनों का निर्माण कार्य मार्च, 2010 तक पूरा होने की सम्भावना है तथा सत्र 2010 से इस संस्थान के आरम्भ होने की सम्भावना है।

Industrial Hub at Dadri

***1103. Maj. Nirpender Singh Sangwan:** Will the Industries Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up an Industrial Hub at Dadri?

उद्योग मंत्री (श्री लगन दास अरोड़ा):

नहीं श्रीमान्।

Plying of Bus from Hisar to Bahal

***1175. Shri Somvir Singh:** Will the Transport Minister be pleased to state whether it is a fact that the bus of Hisar Depot which was plying from Hisar to Bahal at 5.00 P.M. and from Bahal to Hisar at 7.00 A.M. has been stopped for the last many months ; if so, whether the plying of said bus will be started again ?

परिवहन मंत्री (श्री मांगे गुप्ता): श्रीमान् जी! यह बस सेवा दिनांक 30.1.2009 से पुनः आरम्भ कर दी गई है।

Construction of Mahila Chaupals

***1128. Smt. Geeta Bhukal:** Will the Women & Child Development Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide training and equipments for upgradation of traditional skills of women in Mahila Chaupals ;

(b) who will be the nodal officer to monitor the construction/functioning of Mahila Chaupals ; and

(c) the district wise number of Mahila Chaupals constructed or under constructions in the state ?

स्वास्थ मंत्री (बहिन करतार देवी): हां, श्रीमान बिन्दुवार उत्तर निम्न प्रकार से है– (क) महिला चौपाल, जिनका नाम महिला शक्ति सदन रखा गया है, निर्माणाधीन हैं। इन चौपालों में ग्राम स्तरीय महिला कार्यकर्ताओं जैसा कि साक्षर महिला समूह, स्वयं

सहायता धुप, ग्राम स्तरीय समिति व अन्य महिलाओं के ग्रूपों की बैठकें आयोजित की जायेंगी। महिलाओं की दक्षता के बढ़ावे हेतु सम्बन्धित गांव की महिलाओं की मांग अनुसार उन्हें प्रशिक्षण एवं मशीनरी प्रदान की जा सकती है।

(ख) चौपालों का निर्माण जिला प्रशासन की पूर्ण देखरेख में ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है। निर्माण के लिए सम्बन्धित जिले के अतिरिक्त उपायुक्त नोडल अधिकारी हैं एवं कार्यप्रणाली हेतु कार्यक्रम अधिकारी जिला स्तरीय आई० सी०डी०एस० सैल जिला स्तर पर नोडल अधिकारी होंगे।

(ग) प्रथम चरण में 537 चौपालें निर्माणाधीन हैं, ये महिला चौपालें फेल्ड मैनर में निर्मित की जाएंगी। निर्माणाधीन चौपालों की सुची सदन के पटल पर रखी गई हैं, अनुबन्ध कं' पर संलग्न है।

अनुबन्ध क

जिलावार निर्माणाधीन 537 चौपालों की सूची

क्र. स.	जिला का नाम	स्वीकृत राशि लाखों में (रुपये लाखों में)	निर्माणाधीन कार्य
1.	अम्बाला	222.00	74

2.	भिवानी	99.00	31
3.	फरीदाबाद	66.00	21
4.	फतेहाबाद	108.00	36
5.	गुडगांव	27.00	6
6.	हिसार	93.00	31
7.	झज्जर	78.00	26
8.	जीन्द	39.00	13
9.	कैथल	90.00	30
10.	करनाल	87.00	28
11.	कुरुक्षेत्र	78.00	26
12.	मेवात	39.00	13
13.	महेन्द्रगढ़	12.00	4
14.	पंचकूला	33.00	8
15.	पानीपत	27.00	9
16.	रिवाड़ी	15.00	5

17.	रोहतक	132.00	44
18.	सिरसा	72.00	24
19.	सोनीपत	27.00	9
20.	यमुनानगर	309.00	99
	कुल जोड़	1653.00	537

Special Development Grant / Package

***1133. Sh. Sher Singh:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government for a special development grant/package for the Municipal Committee of Julana ?

शहरी विकास मंत्री (श्री ए०सी० चौधरी): हां, श्रीमान जी।

Separate High Court for Haryana

***1139. Dr. Sita Ram:** Will the Chief Minister, Haryana be pleased to state the latest position regarding formation of separate High Court for Haryana State in Chandigarh togetherwith the efforts being made by Haryana Government in this regard ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): सदन के पटल पर कथन रखा जाता है।

कथन

चण्डीगढ़ में हरियाणा के लिए पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए हरियाणा सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं –

1. 14.03.2002 को हरियाणा विधान सभा ने पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के द्विशाखन के लिए तथा चण्डीगढ़ में पृथक उच्च न्यायालय के सृजन के लिए प्रस्ताव पास किया। मामला तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा उनके अर्ध सरकारी पत्र दिनांक 27.3.2002 द्वारा भारत सरकार के सम्मुख रखा गया।

2. जैसा कि 17.05.2004 से नई लोक सभा अस्तित्व में आई, यह महसूस किया गया कि मामला संसद के सम्मुख रखा जाना चाहिए। तदानुसार मंत्रिपरिषद्, हरियाणा ने अपनी बैठक जोकि 23.11.2006 को आयोजित की गई, में अनुमोदित किया कि संशोधन विधेयक के लिए अनुरोध करने हेतु तथा हरियाणा राज्य के लिए पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए विधेयक को पास करने हेतु संसद को अनुरोध करने के लिए प्रस्ताव किया जाए।

3. तत्पश्चात 15.12.2006 को हरियाणा सरकार द्वारा चण्डीगढ़ में हरियाणा के लिए पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना

के संबंध में प्रस्ताव किया गया जो उसी दिन विधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। हरियाणा राज्य की विधान सभा कृत संकल्प हुई कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 में उपयुक्त संशोधन करने के लिए समुचित विधेयक प्रस्तुत करें तथा चण्डीगढ़, जो हरियाणा की राजधानी है, में अवस्थित किए जाने वाले हरियाणा राज्य के लिए पृथक उच्च न्यायालय का उपबंध करें।

यह मुख्यमंत्री के अर्ध सरकारी पत्र दिनांक 13.1.2006 द्वारा संघ विधि तथा न्याय मंत्री को राज्य की राजधानी, चण्डीगढ़ मैं अवस्थित किए जाने वाले पृथक उच्च न्यायालय के सृजन के लिए तुरंत समुचित कार्यवाही करने के लिए अनुरोध करते हुए उठाया गया था।

4. विधि तथा न्याय विभाग, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की एफ टीम, जिसका नेतृत्व उनके अपर सचिव द्वारा किया गया, चण्डीगढ में आई तथा 2.5.2006 को हरियाणा के मुख्यमंत्री को हरियाणा के पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए मिली। संघ विधि मंत्री ने अपने अर्थ सरकारी पत्र दिनांक 26. 5.2006 द्वारा उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए स्थल तथा बनाने के बारे में कतिपय जानकारी मांगी जिसका उत्तर पत्र दिनांक 2.6.2006 द्वारा दिया गया। संघ विधि मंत्री ने अपने अर्ध सरकारी पत्र दिनांक 30.6.2006 द्वारा कतिपय आपत्ति उठाई।

5. मुख्यमंत्री, हरियाणा ने अपने अर्ध सरकारी पत्र दिनांक 12.7.2006 द्वारा माननीय संघ विधि मंत्री द्वारा उठाई गई आपत्तियों का उत्तर देते हुए कहा कि चण्डीगढ़ में हरियाणा के लिए पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना में कोई विधिक अड़चन नहीं है। जैसा कि राज्य का विधान मण्डल भी यहां पर अवस्थित है। यह भी बताया गया कि यदि संघ विधि मंत्री द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार हरियाणा के संघ क्षेत्र में हरियाणा का उच्च न्यायालय अवस्थित किया जा सकता है, तब वही तर्क पंजाब राज्य पर भी लागू होगा। वहां विधान सभा तथा सचिवालय भवनों के द्विशाखन में कोई विधिक अड़चन नहीं थी, ऐसा करने के लिए केवल पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 में उपयुक्त संशोधन करने की आवश्यक्ला थी।

6. मुख्यमंत्री हरियाणा ने अपने अर्थ सरकारी पत्र दिनांक 12.7.2006 द्वारा भी माननीय प्रधान मंत्री को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 का केन्द्रीय अधिनियम 31 के भाग–4 अर्थात् अधिनियम की धारा 29 से 41 में उपयुक्त संशोधन करने के लिए तथा चण्डीगढ़ में अवस्थित हरियाणा राज्य के लिए पृथक उच्च न्यायालय का उपबंध करने हेतु समुचित विधेयक प्रस्तुत करने के लिए तुरंत आवश्यक कार्यवाही करने के लिए भी अनुरोध किया।

7. तत्पश्चात मुख्यमंत्री द्वारा विधि तथा न्याय मंत्री, भारत सरकार को अर्ध सरकारी पत्र दिनांक 16.4.2008 द्वारा भी एक और अनुरोध किया गया।

8. 19.4.2009 को राज्य के मुख्य मंत्रियों तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीशों के सम्मेलन में मुख्य मंत्री ने चण्डीगढ़ में हरियाणा राज्य के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए हरियाणा सरकार के अनुरोध को पुनः दोहराया।

Rules Enacted for Prevention of Corruption

***1050. Sh. Karan Singh Dalal:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the state Government has enacted any special Laws for Prevention of Corruption among Public Servants under the purview of the State Government in State so far: if so, the details thereof togetherwith date of application and notification of said Rules ;

(b) whether the provisions of Prevention of Corruption Act, 1988 passed by Parliament has been adopted for the purpose as mentioned above ; and

(c) the number of cases registered under the provision of Prevention of Corruption Act, 1988 in state ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्रसिंह हुड्डा):

(क व ख) नहीं, श्रीमान जी लोकसभा द्वारा पारित भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम, 1988 हरियाणा राज्य में लागू है।

(ग) राज्य में वर्ष 2000–01 से अब तक भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत 1270 अभियोग अंकित किए गए।

Facilities for Cancer Patients

***1194. Smt. Sumita Singh:** Will the Health Minister be pleased to state whether the Government has provided the facility/service of complete Medical Tests and sale of medicines for the cancer patients at District Headquarters; if so, the name of Districts in which such facilities/services have been provided ?

स्वास्थ्य मंत्री (बहिन करतार देवी): नहीं, श्रीमान जी क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, पी०जी०आई० एम०एस०, रोहतक में कैंसर रोगियों के लिए विस्तृत जांच सुविधाएं उपलब्ध हैं। जिला हस्पतालों में मूल जांच सुविधाएं उपलब्ध हैं।

Old Tanks in the Villages of M.C. Faridabad

***1152. Sh. Mahender Partap Singh:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state—

(a) the number and name of villages which falls in the urban residential area of Faridabad Municipal Corporation in which there are old tanks filled with water ; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to develop the above said tanks into parks or stadiums ; if so, the details thereof ?

शहरी विकास मंत्री (श्री ए०सी० चौधरी):

(क) फरीदाबाद नगर निगम के किसी भी गांव में ऐसा कोई पुराना तालाब नहीं है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

Upgrading of Madiauda Sub Tehsil to a Tehsil

***1161. Smt. Raj Rani Poonam:** Will the Minister of State for Revenue & Disaster Management be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Sub-Tehsil Madlauda to a Tehsil ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री जिन्दल): जी, नहीं।

Upgradation of Schools

1215. Sh. Shahida Khan: Will the Education Minister be pleased to state the number of schools upgraded in district Mewat and whether the Government is formulating any scheme to raise the level of the education in the said district as the level of the education is very low there ?

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता): श्रीमान जी, मेवात जिले में 2005–09 के दौरान 172 विद्यालयों का दर्जा बढ़ाया गया है तथा इस जिले में शिक्षा कै सार कौ०पर उठाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित को जा रही हैं।

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, करनाल और राजकिय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बाला अपनी के विद्यार्थियों का अभिनन्दन

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन को बताना चाहूंगा कि हर दिन की भांति आज भी गवर्नमैंट कालेज करनाल और गवर्नमैंट कालेज अम्बाला कैंट के छात्र–छात्राएं सदन की कार्यवाही को देखने के लिए दर्शक दीर्घा में मौजूद हैं। मैं विपक्ष और पक्ष दोनों के काबिल साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप सभी सदस्य अपनी बात रखें लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि ये देश की अगली पीढ़ी हैं। आपके आचरण से ये शिक्षा लेंगे कि चुने हुए प्रतिनिधि किस तरह का जिम्मेदाराना आचरण करते हैं, ये देश की अगली पीढ़ी के लिए देखना और जानना जरूरी हे। मैं उन सभी छात्र, छात्राओं को सदन के नेता की तरफ से और पूरे सदन की तरफ से मुबारिकबाद देता हूं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। मैं यह भी आशा करता हूं कि देश और प्रदेश की प्रगति में वे अपनी रचनात्मक भूमिका निभा पाएंगे।

अनुपस्थिति संबंधी सूचनाएं

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I am to inform the House that I have received a letter from Smt. Kartar Devi, Health Minister, dated 13th February, 2009, vide which she has informed that due to fever, she will not be able to attend the Session of Haryana Vidhan Sabha today, the 13th

February, 2009.

Hon'ble Members, I am also to inform the House that I have received a letter from Major Nirpender Singh Sangwan, MLA vide which he has informed that he would not be able to attend the Session of Haryana Vidhan Sabha today, the 13th February, 2009 as he has to go to Suratgarh (Rajasthan) to attend the 225th Raising Day of his Regiment 7th Light Cavalry.

नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 121, regarding nomination of various Committees.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That the provisions of Rules 231, 233, 235 and 270 of the Rules of Procedure and conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in-so-far as they relate to the constitution of the-

(i) Committee on Public Accounts ;

(ii) Committee on Estimates ;

(iii) Committee on Public Undertakings ; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes, for the year 2009-2010 be suspended. Sir, I beg to move—

That this House authorizes the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 2009-2010, keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the provisions of Rules 231, 233, 235 and 270 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in-so-far as they relate to the constitution of the-

(i) Committee on Public Accounts ;

(ii) Committee on Estimates ;

(iii) Committee on Public Undertakings ; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes, for the year 2009-2010 be suspended. Also

That this House authorizes the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 2009-2010, keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

Mr. Speaker: Question is—

That the provisions of Rules 231, 233, 235 and 270 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative

Assembly in-so-far as they relate to the constitution of the—

(i) Committee on Public Accounts ;

(ii) Committee on Estimates ;

(iii) Committee on Public Undertakings ; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes, for the year 2009-2010 be suspended.

Also

That this House authorizes the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 2009-2010, keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

The motion was carried

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना

डा० सुशील इन्दौराः स्पीकर सर, इससे पहले कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर डिस्कशन शुरू हो, मैं एक बात कहना चाहूंगा। हरियाणा प्रदेश में पिछले दिनों 18 जनवरी के आसपास और अभी दो–चार दिन पहले भी बहुत तेज अंधड़ आया था और ओले भी पड़े थे जिससे किसानों की सरसों, चने और गेहूं की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा था। इस बारे में सरकार ने अभी तक किसानों को मुआवजे का कोई आश्वासन नहीं दिया। मैंने इस बारे में कालिंग अटेंशन मोशन भी दिया हुआ है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस बारे में सदन में एक स्टेटमैंट

लेकर आये और किसानों को इससे जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई भी करे। मैं यह भी चाहता हूं कि ज्यादा नही तो कम से कम किसान का जो लागत मूल्य है जो कि बहुत ज्यादा है उसकी तो सरकार द्वारा भरपाई की ही जानी चाहिए।

श्री अध्यक्षः डॉ० इन्दौरा आपका इस बारे में जो कालिंग अटैशन मोशन विधान सभा में प्राप्त हुआ है उसे आगामी कार्यवाही हेतु गवर्नमैंट को भेजा हुआ है और गवर्नमैंट से कमैंट्स प्राप्त होने के उपरांत तदानुसार आपको इन्फार्म कर दिया जायेगा।

डा० सुशील इन्दौराः ठीक है सर। धन्यवाद।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Members, now discussion on Governor's Address will resume, I.G. Sher Singh, please resume the discussion on Governor's Address.

आई०जी० शेर सिंह (जुलाना): स्पीकर सर, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय प्रदान किया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। स्पीकर सर, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। स्पीकर सर, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमारे महान् योद्धा चाहे वे आजादी के दीवाने हों चाहे आजादी दिलाने में या उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन देशहित और जन

कल्याणार्थ समर्पित किया। इसके साथ–साथ जो इस प्रकार के महापुरुष इस संसार से चले गये ओर बाद में जो महापुरुष रह गये उन्होंने अपने जीवन को जन साधारण के लिए एक उच्चकोटि का उदाहरण बनाया ताकि लोग उनके जीवन से अधिक शिक्षा ग्रहण करके देश और समाज के लिए अपना विशेष योगदान दे सकें। उन महापुरुषों में हमारे एक बहुत ही महान् व्यक्ति जिनका महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी अपने अभिभाषण में जिक्र किया है और जिनका सभी लोगों ने जिक्र किया है मैं भी उनके बारे में दो शब्द बोलना चाहूंगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है हमारे देश में ऐसे अनेक महान् योद्धा पहले भी थे और आज भी हैं लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जिनका पूरा जीवन एक पाठशाला बन जाता है। इसके विपरीत बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो पशु पक्षियों से भी नीचे के लैवल का जीवन जीकर इस संसार से चले जाते हैं। आम तौर पर इस संसार में दो प्रकार के इन्सान होते हैं एक तो यह कहते हैं कि देश मुझे क्या देगा और दूसरी प्रकार के वे लोग हैं जो कि बहुत थोड़े ही होते हैं वे कहते हैं कि मैं देश को क्या पै सकता हूं। मैं यही कहूंगा कि हमारे माननीय चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी जो कि आज स्वर्ग में हैं मैं यह कहूंगा कि उनके जो आखिरी शब्द हैं वे ये हैं कि अपने देश के लिए मैं क्या दे सकता हूं यह अपने आप में एक उच्चकोटि का उदाहरण है जिसका हम सभी को अनुसरण करना चाहिए और इसे अपने व्यावहारिक जीवन में उतारते हुए अपने देश कै लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना चाहिए। (इस समय सभापतियों की सूची में

से एक सदस्य डॉ० सुशील इन्दौरा पदासीन स्टे मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि I, as a soldier of the people salute them for their smilingly sacrifice their today for our tomorrow. यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण होता है उसमें सरकार की मंशा औंर कार्य करने की प्रणाली को दर्शाया जाता हे। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और उनके लिए जिस प्रकार से धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है वह अपने आप में काबिले तारीफ है। यहां यह बात भी देखने योग्य है कि जब मौजूदा सरकार वर्ष 2006 में सत्ता में आई तो किस प्रकार से एनुअल प्लान बजट में बढ़ोतरी हुई है। उस समय 2236 करोड़ रुपये का प्लान बजट था और आज यह 10 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह दिखाता है कि सरकार किस प्रकार आगे बढ़ रही है। इस प्रकार से इसमें लगभग 50.37 प्रतिशत की बढ़ौतरी है और यह छ गुणा वृद्धि है। इसमें बहुत से हैडिंग दिये गये हैं और सरकार ने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से प्राथमिकता दिखलाई है कि किस तरीके से हरियाणा का विकास हो सकता है। जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है, it is itself an encyclopedia of a progress, showing the country or showing the interest taken by our Hon'ble Chief Minister Shri Hooda ji, has been shown in this book. सभापति महोदय, इसी प्रकार से कृषि और किसान के बारे में हम सभी जानते हैं कि हम सब हरियाणावासी कृषि पर निर्भर हैं। अगर कृषि में हम आगे बढ़ेंगे

तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा हरियाणा प्रदेश और हमारा देश और आगे जायेगा। चाहे खाद्य रख आपूर्ति हो, चाहे डेयरी विकास हो या सिंचाई हो सरकार ने सभी क्षेत्रों में बहुत प्रयास किये हैं बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि सरकार ने हर क्षेत्र में निर्णायक कदम बढ़ाये हैं। सिंचाई के बारे में मेरा कहना है कि सरकार ने पानी का समान बंटवारा किया है और जो क्षेत्र नहरी पानी से वंचित रह गये थे उनको हांसी–बुटाना लिंक नहर बनाकर पानी पहुंचाया जायेगा। जन–स्वास्थ्य के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि चाहे किसी भी प्रकार की मांग थी उसके लिए सरकार ने पूरा पैसा दिया है। इसी प्रकार से बिजली के बारे में कहना चाहूंगा कि घरेलू कारखानों और किसानों के लिए बिजली की बहुत अहम् भूमिका है। लेकिन जब हरियाणा बना था उस समय बिजली के बारे में जरूर सोचा गया था और कुछ कारखाने लगाये गये थे। लेकिन उसके बाद में जो सरकारें बुआई उन्होंने इस तरफ कोई खास ध्यान कहीं दिया। 2005 में जब चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार आई तो इन्होंने यह निर्णय लिया कि बिजली के संकट से जूझने का और कोई विकल्प नहीं है केवल एक ही विकल्प है कि बिजली पैदा की जाये। बाहर से जो ले रहे हैं वह तो जब तक जरूरत है तब तक लेते रहेंगे लेकिन जब तक अपने घर में हम बिजली नहीं बनायेंगे तब तक इसकी पूर्ति नहीं कर सक्ते हैं। आज भी कई लोग कहते हैं कि बिजली कहां बन रही है? उन लोगों से मेरा कहना है कि आज खेदड में देखें, झाडली, यमुनानगर में देखें जहा चारों तरफ बिजली उत्पादन की दिशा में युद्ध स्तर पर कार्य

चल रहा है। जिन लोगों की आखें नहीं खुली हैं उनको वहां जाकर देखना चाहिए जहां पर बिजली के लिए दिन रात कार्य चल रहा है। भवन और सड्कों के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा कि सड्कों के०पर बहुत पैसा लगावा गया है। लेकिन मैं सरकार से निवदेन करना चाहूंगा कि मेरे हल्के की कुछ सड़कें टूटी हूई हैं उनकी रिपेयर जल्दी से जल्दी को जाये जिनके नाम इस प्रकार हैं – इगराह से कागश्री, इगराह से गोहाना, इगराह से धर्मखेडी, रोहतक रोड से बूरा डहर, हकवाता से पाली, अकालगढ से जुलाना, कसौला सें रामकली, जैज्वंती से खरैंटी, झमौला से घडवाली। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि नई सड्कों की भी हमें प्राथमिकता के आधार पर जरूरत है।

Mr. Chairman: I.G. Sahib, your time is over. आपका समय समाप्त हो गया है, आप अपनी बात एक मिनट में खल करें। You can take only one minute more.

आई०जी० शेर सिंहः चेयरमैन सर, मुझे बोलने के लिए थोड़ा और समय देने की कृपा करें।

श्री सभापतिः आई०जी० साहब, आपको पांच मिनट का समय और देते हैं।

आई०जी० शेर सिंहः इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जब से यह सरकार आई है इसने एजुकेशन के बारे में बहुत काम किये। बगैर ऐजुकेशन के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं।

पिछली सरकार के समय में आप भी यहां पर थे और मैं भी था उस समय कितने स्कूल खोले शे और कितने टीचर्ज लगाए थे उसकी पूरी जानकारी आपको है। (विघ्न) इस सरकार के वक्त में कितने स्कूल खुले हैं, कितने टीचर्ज लगे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जबसे हमारे हुड्डा साहब मुख्य मंत्री बने हैं कांग्रेस सरकार ने यह सोचा है कि लोगों को किस प्रकार से नौकरी दिलाई जा सकती है। सभापति महोदय, आज टैक्नोलोजी का जमाना है। यह बात सबके सामने है कि टैक्नोलोजी के बारे नें प्रायोरिटी देते हुए कितने ही टैक्नीकल कॉलेजिज खोले गये हैं कितने ही मैडीकल कॉलेजिज खोले गये हैं। कितने ही नये कॉलेजिज खोलने के आवेदन हैं मेवात में भी कॉलेजिज खोल रहे हैं। खानपुर में गर्ल्ज के लिए कॉलेज है और इसी तरीके से कितने ही और कॉलेजिज हैं लेकिन मैं इस बारे में सरकार का ध्यान एक विशेष बात की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें कोई शक की बात नहीं है मैंने एक सवाल पूछा था कि जीन्द हल्के में 10 जमा दो के स्कूलों में साईंस सब्जैक्ट कितने स्कूलों में है। सभापति महोदय, जीन्द हल्के में 95 स्कूल्ज दस जमा दो के हैं– जिनमें से साईंस सब्जैक्ट केवल 12 स्कूलों में पढ़ाया जाता है। हम कहते हैं कि हमारे लडके बाहर पढ़ने के लिए न जाएं और हमारे लड़के यहीं पर रहे। अगर हमारे लड़को के लिए साईंस इन्ट्रोंडयूस नहीं की जाएगी तो हम इन टेक्नीकल कॉलेजों और मैडीकल कालेजों के लिए पनीरी कहां से लाएंगे। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले स्कूल खोलने को

प्राथमिकता दी जाती है फिर स्कूल अपग्रेड किये जाते हैं और स्कूल अपग्रेड किये भी जाने चाहिएं लेकिन वहां पर साईस सबजैक्ट इन्ट्रोडयूस करना जरूरी है ताकि हमारे बच्चे कम्पीटीटिव एग्जामिनेशन्ज में, मैडीकल और टैक्नीकल कालेजिज में ऐडमिशन ले पाएं। प्राईमरी स्कूल और ऐलिमैंट्री –स्कूल्ज से कक्षा आठ, कक्षा दस तथा कक्षा बारह के स्कूलों को भरमार है और मेरे हल्के में इस सरकार द्वारा खूब स्कूल अपग्रेड किये गये हे लेकिन मैं समझता हूं कि अभी भी कुछ ऐसे गांव हैं जैसे भूरा डहर, किशन पुरा, वराड, लजवाना खुर्द, ढाणी बीडवाली खेमाखेडी आदि में अभी तक ऐलिमैंटी स्कूल्ज हैं। सरकार से मेरा निवेदन है कि इन स्कूलों का कम से कम आठवीं कक्षा तक का दर्जा, जरूर किया जाए। सभापति महोदय, दो–तीन स्कूल ऐसे भी हैं जो अपग्रेड किये जाने चाहिए। मेरे अपने झारा गांव में वोकेशनल स्कूल था जिसको यद किया गया है और अब वह हाई स्कूल ही रह गया हे। मेरा यह निवेदन है कि कम्पनसेट करने के लिए डस स्कूल को कम से कम दस जमा दो का रूरल अपग्रेड करने की कृपा करें। जुलाना मे गवर्नमैंट कॉलेज बनाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से, मरी सबसे पहली डिमांड यही थी कि वहां पर कॉलेज जरूर बनाया जाए, वहां पर कालेज बन गया हैं। कुछ लोगों को यह शक हें कि वहां पर कॉलेज नहीं बना हैं उसके विषय मे मैं शिक्षा मंत्री महोदय तथा सरकार से भी बात करना चाहूंगा कि उस कॉलेज में क्लासिज शुरू हो चुकी है लेकिन वे क्लासिज अभी तक बाहर ही चल रही हैं और सैकण्ड ईयर तक की क्लासिज यहां

चल रही है। यह क्लासिज 2007 के सैशन से शुरू हुई थीं लेकिन इस कॉलेज की बिल्डिंग अभी तक कम्पलीट नहीं हुई हें। सरकार से मैं यह निवेदन करना चाहूगा कि इस बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी कम्पलीट किया जाए जिससे अगले सत्र कें बच्चे और हमारे कॉलेज की लड़कियां और लड़के उनमें पद सकें। जुलाना से करेला और झमोला गांव काफी दूर हैं और नजदीक में केवल एक ही स्कूल है मेरी मांग है कि वहां भी 10 जमा 2 का स्कूल किया जाए। सभापति महोदय, इसी प्रकार से मैं सोलजर्ज के वारे में कहूँगा कि इस सरकार ने इनको बहुत क्त दिया है। ये सैनिक हमारी सीमाओ पर पहरा देते हैं और इनमें से कई अपने आप को देश पर न्यौछावर करके चले भी जाते हैं तथा अपना पूरा जीवन देश पर कुर्बान कर देते हैं। उनका जो जीवन रह जाता है वह उस जीवन को जिस प्रकार से निभाते हैं वह बहुत ही सराहनीय है। सभापति महोदय, मैं सरकार से एक ओर निवेदन करना चाहूंगा। They have got a lobby of defence personnel but the paramilitary forces and police forces are debarred from such lobbies. मैं यह रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि हरियाणा में पैरा मिल्ट्री फासिंज को फोजों जैसा मान–देय दिया जाना चाहिए।

श्री सभापतिः शेर सिंह जी, आप कन्कल्यूड करें।

आई०जी० शेर सिंहः सर, मान–देय कं, मामले में हमारे मुख्यमंत्री जी ने. हमारे डिफैंस पर्सनल्ज को बहुत कुछ दिया है। लेकिन पैरा मिली फोर्सिज जो हैं वे अन्डर दि डिफैंस मिनिस्टरी

होम अफेयर्ज आती हैं। उनको थोड़ा सा दूर रखा गया है। मैंने इसके बारे में चीफ मिनिस्टर साहब को लैटर भी दिया था और मैंने इस बारे में चौक भी किया था और शायद वह चिट्ठी गृह मंत्रालय में पड़ी हुई है। सरकार ने उनकी उत्कृष्ट सेवा और बहादुरी के लिए बहुत कुछ दिया है जो कि और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से रिक्वैस्ट करना चाहूंगा पैरा मिष्टी फोर्सिज के लिए भी कुछ किया जाए। इसी तरह से मैं पुलिस फोर्सिज के लिए भी कहना चाहूंगा। आज ला एंड आर्डर मेनटेन करने के लिए प्राईम रोल पुलिस का होता है और हर तरीके से पुलिस 24 घंटे जनता की सेवा करती रहती है। मैं उनकी राशन मनी के बारे में कहना चाहता हूं कि पहले आम सिपाही को राशन मनी 300 रुपए मिलती थी और इसमें जो अलग कैटगरी है उसको अलग मिलती है। लेकिन जो जरनल सिपाही है या रैंक एंड फाईल अप हू इन्सपैक्टर लैवल हे उनकी राशन मनी को इस सरकार ने 300 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि आज महंगाई को देखते हुए इस राशन मनी को 1000 रुपये जरूर करना चाहिए। (विघ्न) इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि पुलिस में एक डिस्पैरिटी है among the people how they are being promoted. हम अभी भी पुरानी लाईन को ही पकड़े हुए हैं। मैं सीनियोरिटी के बारे में बताना चाहता हूं कि एक रेंज में सीनियोरिटी एक तरह की होती है और दूसरी रेंज में सीनियोरिटी दूसरी तरह की होती है, सैशली कांस्टेबल से

इन्सपैक्टर के लैवल तक। सभापति महोदय, आज समय आ गया है कि फौज की तरह सबकी सीनियोरिटी एक कर दी जानी चाहिए। जैसे हिसार रेंज है और अम्बाला रेंज है। अगर अम्बाला रेंज में किसी जूनियर को परमोशन हो जाती है क्योंकि वह पर वैकेंसी है। इसको सैंट्रेलाईज करना और रैशनेलाईज करना आज समय की पुकार है और इससे उनमें जो ऐनोमलीज हैं वह भी दूर होगी। सभापति महोदय, जैसे बी०एस०एफ० और सी०आर०पी०एफ० में सीनियोरिटी नेशनेलाईजड हो चुकी है तो हरियाणा पुलिस फोर्स ने भी यह सब होना चाहिए।

श्री सभापतिः .आप वाईंड–अप करें। आपका टाईम खत्म हो गया है। अब आप बैठें।

श्रीमती अनीता यादव (साल्हावास): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, इस कथन में माननीय गवर्नर साहब ने जो अभिभाषण पढ़ा था उस पर मैं बोलना चाहती हूं। सबसे पहले उसमें चौधरी रणबीर सिंह जी के बारे में जिक्र किया गया है और मैं भी उनके बारे में ही कहना चाहूंगी कि वे एक सच्चे राष्ट्रवादी थे। संविधान सभा के अन्तिम जीवित सदस्य थे। उन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत योगदान दिया था। वे किसानों और गरीबों के मसीहा थे। सभापति महोदय, मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने सदन में जिक्र किया कि उनका एक स्टैच्यू संसद में लगना चाहिए। मैं भी आपके माध्यम से पुरजोर अपील

करती हूं कि उनका स्टैच्यू संसद में लगना चाहिए। साथ ही साथ में यह जिक्र करना चाहूंगी कि इस सरकार से पहले वाली सरकार हमेशा लोगों को यह कहती थी कि बिजली के बिल मत भरना। जब हम सत्ता में सप्तको तो न बिजली का मीटर होगा और न ही मीटर रीडर होगा। लेकिन हमारी सरकार ने जो कभी कहा ही नहीं, वह भी कर दिखाया। सभापति महोदय, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की वजारत में सभी ने सोचा कि ऐसे कैसे काम चलेगा, कब तक पेडू कटते रहेंगे, कब तक सड्कों गर जाम लगता रहेगा, कब तक बच्चों का भविष्य धूमिल होता रहेगा। इस सरकार ने सोचा कि क्यों न हम अपने ही घर में बिजली का कारखाना, बिजली का प्लांट लगाएं जो हरियाणा प्रदेश को देश में नम्बर एक पर ले जाएगा और यह ऐतिहासिक फैसला होगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सोच एक कदम आगे बढ़कर है। चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को बधाई देना चाहती हूं कि एक तरफ वह सरकार थी जिसने किसानों की जमीनों को कोड़ियों के भाव में खरीदा था और वह भी कभी खरीदते थे तो लाख डेढ़ लाख रुपये वैसे ही देकर उनको फारिग कर देते थे लेकिन आज हुड्डा साहब की सोच अलग ही है। किसान और जमींदार की जमीन को किस तरह से अधिग्रहण किया जाता है यह उन्होंने बताया है। अब जिन किसानों की जमीन बिजली कै प्लांट्स लगाने के लिए ऐक्वायर की गयी है उनको 21 से 22 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से राशि दी गयी है। इसके अलावा 33 साल तक एक इजाफा और

जोड़ दिया है और वह यह कि जिनकी जमीन बिजली के प्लांट्स लगाने के लिए ली गयी है उनको हर साल 15 हजार रुपये की राशि भी मिलेगी। मैं यह बताना चाहती हूं कि एक उस समय की सरकार का फैसला था और एक आज की सरकार का फैसला है। उस समय तो किसी की भी जमीन हथिया ली जाती थी, काबू कर ली जाती थी और उस पर बुत लगा दिए जाते थे—लेकिन आज अगर किसी की जमीन ली जाती है तो उसको 22 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा राशि दी जाती है।

श्री सभापतिः अनिता जी,० सरकार को अच्छे सुझाव दीजिए।

श्रीमती अनिता यादवः चेयरमैन साहब, आप सुनें तो सही मैं सुझाव ही दे रही हूं। मैं गवर्नर ऐड्रैस पुर बोल रही हूं। आप मेरी बात सुनें तो सही। चेयरमैन साहब, माननीय मुख्यमत्री जी की सोच है कि किस तरह से किसान को आगे लाया जाए और किस तरह से बेरोजगार भाइयों को रोजगार देकर बेरोजगारी को दूर किया जाए। चेयरमैन साहब, इस सरकार के चार साल के कार्यकाल में चार बिजली के प्लांट्स लगे हैं। मुझे यह कहते हुए हर्ष होता है कि मेरा साल्हावास विधान सभा क्षेत्र जोकि रोहतक लोक सभा क्षेत्र में आता है वहां से मुख्यमंत्री जी चौधरी देवीलाल को लगातार चार बार हराकर एम०पी० बने थे। अब उनके बेटे दीपेन्द्र सिंह जी हुड्डा की सोच भी इसी तरह की है वे भी अपने पिता जी के साथ मिलकर हरियाणा को नम्बर एक पर ले जाने के

लिए कार्य कर रहे हे। वे हमेशा यह सोचते रहते हैं कि किस तरह से हरियाणा प्रदेश को आगे रख सकते हैं। चेयरमैन साहब, बिजली का एक प्लांट झाडली में एन०टी०पी०सी० के सहयोग से लगेगा और दूसरा प्लांट एफ०सी०एल० के सहयोग से खानपुर खुर्द में लगेगा। इससे हमारे कितने ही भाइयों को रोजगार मिल रहा है जिसके कारण उनकी बेरोजगारी दूर हो गयी है, कितने ही भाइयों को वहां पर काम करने का मौका मिला है, किने वहां पर ट्रैक्टर्ज लगाए गए हैं, कितनी ही वहां पर जे०सी०बी० मशीनें हमारे भाइयों ने खरीदकर लगायी हैं। चेयरमैन साहब, चौधरी रणबीर सिंह के नाम पर स्वराज के स्वर नाम से जो किताब निकाली गयी है वह भी बहुत अच्छी बात है। उसी स्वर को मैं जोड़ती हुई कहती हूं कि मुख्यमंत्री जी की सोच से न जाने कितने ही लोगों को रोजगार दिया है। अब वहां पर कोई भाई चाय बना रहा है, कोई भाई प्रोपर्टी का काम कर रहा है तथा कोई भाई वहां पर पंचर लगाने का काम कर रहा है क्योंकि वहां पर कितनी ही जे०सी०बी० काग कर रही हैं, कितने ही ट्रैक्टर्ज वहां पर लगे हुए हैं, स्कूटर्ज हैं, साईकिल्ज हैं जिनसे लोग वहां पर काम करने के लिए आते हैं। इस तरह से अब वहां पर कितने ही लोगो को काम मिलने से उनकी बेरोजगारी दूर हो गयी है। चेयरमैन साहब, इसलिए ये सारी बातें देखने की होती हैं। इस तरह से यह एक लम्बी सोच की बात है। इनके नेता तो जाड धिसाई के भी पैसे लेते थे। वे कहते थे कि अगर हम रोटी खाने आयेंगे तो उसमें समय खर्च होगा इसलिए कितनी मालाएं आप डालोगे। मैं आपके माध्यम से

विपक्ष के भाइयों से कहना चाहती हूं कि वह भी कम से कम इस बारे में सोचें और अपने नेता को सलाह दें। एक सोच वह थी कि जाहू घिसाई के नाम से पैसे लिए जाते थे।

श्री सभापतिः अनिता जी, आप अभिभाषण पर हो चर्चा कीजिए और आप चेयर को ही एड्रैस कीजिए।

श्रीमती अनिता यादवः चेयरमैन साहव, मैं गवर्नर ऐड्रैस का ही जिक्र कर रही हूं। में बिजली का जिक्र कर रही हूं। बिजली के प्लांट्स लगने से बहुत से लोगों को रोजगार मिला है। हमारे बच्चों के लिए, हमारे लोगों के लिए अब तक बहुत महंगी बिजली खरीदी जाती थी लेकिन जय ये सारे बिजली के प्रोजैक्ट लग जाएने तो फिर इतनी महंगी बिजली खरीदने की जरूरत नहीं रहेगी। यमुनानगर का बिजली का प्रोजेक्ट, झाडली का प्रोजैक्ट, खेदडू का प्रोजैक्ट, हिसार का प्रोजैक्ट ये प्रोजैक्ट जब बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे तो फिर बिजली की दिक्कत नहीं रहेगी। चेयरमैन साहब, इनको तो इस बात की सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। इनके नेता कहते थे कि काट दो पेडू, बिजली का बिल भी न मरो, बिजली का मीटर भी नहीं होगा और न रीडर होगा। प्रदेश में इस तरह के बिजली के कारखाने लगाये जा रहे हैं। प्रदेश को नंबर– 1 बनाने मेँ बिजली की अहम् भूमिका है। किसान को उसकी भूमि के मुआवजे के रूप में 20 से 22 लाख रुपये प्रति एक्क के हिसाब से मिल रहे हैं और 33 साल तक इजाफे का भी लाभ मिलेगा। आप जैसे भाइयों को तो तौर पर इस बात की

खुशी होनी चाहिए कि सरकार इतने बड़े ऐतिहासिक कदम उठा रही है। गवर्नर साहब के ऐड्रस में भी इन सब बातों का जिक्र है। (विघ्न)

11.00 बजे

Mr. Chairperson: Please make the dignity of the Chair. Please sit down, Do not comment on the Chair.

श्रीमती अनीता यादवः चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने हरियाणा प्रदेश को एक नंबर का प्रदेश बनाने में बहुत भारी योगदान दिया है।

डा० सीता रामः सभापति महोदय, मेरा प्यायंट आफ ऑर्डर है। अनीता जी के दो रूप हैं। यहां कुछ खेलती हैं बाहर क्त बोलती हैं। जब ये यहां एंटर करती हैं तो हमसे अलग तरीके से बात करती हैं ये दो रूप नहीं होने चाहिएं।

Mr. Chairperson: Please sit down. This is not a point of order.

श्रीमती अनीता यादवः चेयरमैन सर विपक्ष की तरफ से अच्छे–अच्छे सुझाव आने चाहिए। दो मिनट की श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही थी उस समय भी ये लोग हाउस में नहीं थे। ये साथी तो सुनेने लायक भी नहीं हैं। थें काबिल भी नहीं हैं। जन मैं शिक्षा के बारे में कुछ सुझाव देना चाहती हूं। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश को (बहुत आगे ले गए हैं।

इन्फोर्मेशन टैक्नोलाजी का जमाना आ रहा है। सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है। सभी ऑफिसिज में कम्यूटर लग गए हैं। बच्चे हर तरह की पात्रता पूरा करते हैं। डिपार्टमैंटल जॉब भी दिये जा रहे हैं। सरकार बेरोजगार नौजवानों को नौकरियों में सैट करने में लगी हुई है और रोजगार के साधन जुटा रही है।। पिछली सरकार ने तो इस दिशा में कुछ भी नहीं किया था। पिछली बार के सदन में जब हम यहां बैठते तो एसा लगता था कि अनपढ लोगों को फौज यही पर बैठी हुई हो। अव तो यहां पर डॉक्टर, वकील और बहुत ही अच्छे पड़े लिखे लोग हैं। दक्षिणी हरियाणा में पढ़ाई की हमेशा से कमी रही है। अब एक विश्वविद्यालय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से हमें मिला है।

Parliamentary Secretary (Rao Pan Singh): Chairperson Sir, I am on a point of order.

Mr. Chairperson: Where is your seat ?

Rao Dan Singh: Chairman Sir, I am going on my seat. सर, मैं यह बताना चाहता हूं कि दक्षिणी हरियाणा को एक विश्वविधालय नहीं मिला बल्कि डिफैंस यूनिवार्सिटी, सैनिक स्कूल और मैडीकल कॉलेज भी आ गया है।

श्रीमती अनीता यादवः सभापति महोदय, रोहतक जिले को शैक्षणिक नगरी का नाम दिया गया है। यह बहुत ही प्रशंसा की बात है कि हमारा प्रदेश शिक्षा के स्तर पर कितनी उन्नति कर रहा हे। (विघ्न)

राव दान सिंहः मैं बताना चाहता हूं कि जो कुछ इस सरकार ने किया है उसका शब्दो– में वर्णन नही किया जा सकता। पिछली सरकार के समय मे प्रदेश में विकास की गति को रोककर प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया गया था। चार पांच ऐसी मुख्य बातें हैं जिनका कोई पैरेलल नहीं है। केन्द्र सरकार से 16 विश्वविद्यालय मिले हैं जिनमें से एक हरियाणा प्रदेश को मिला है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि एक विश्वविद्यालय महेन्द्रगढ़ जिले में बनाया गया है। जिससे उस इलाके में जो शिक्षित रूप से पीछे था वह आगे चला गया है। एक डिफेंस यूनिवर्सिटी का प्रोपोजल हुआ, वह भी दक्षिणी हरियाणा के गुडगांव में दिया गया है। एक सैनिक स्कूल बनाने का मामला जो काफी समय से लम्बित पड़ा था वह मो दक्षिणी हरियाणा के रेवाड़ी में स्थापित किया गया है। दो मैडीकल कालेज भी दक्षिणी हरियाणा को दिए गये हैं। इस बात से स्पष्ट अंदाजा लगाया जा सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे हरियाणा का समुचित विकास करने का संकल्प लिया था उसे पूरा करने के लिए कोई ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं छोड़ा जहां पर विकास की गति को नहीं पहुंचाया हो। चेयरमैन साहब, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।

श्रीमती अनिता यादवः चेयरमैन साहब, अब मैं सिंचाई के बारे में कहना चाहती. हूं।

श्री सभापतिः अनिता जी, आप जल्दी से वाईंड अप कीजिए।

श्रीमती अनिता यादवः चेयरमैन साहब, आज सिंचाई के मामले का जो श्रेय जाता है वह हमारे दिवंगत स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी को जाता है समय में भाखड़ा जैसा डैम बनाया गया है। इसके बारे में मैं कह सकती हूं कि यह एक भावना की बात है में इसके लिए एक लाईन कहना चाहती हूं:–

समय नदी की धार है समय नदी की धार। धार में सब वह गए, माननीय चौधरी रणवीर सिंह जो ऐसे जननायक थे, जो भाखड़ा डैम बना गए।

माननीय चेयरमैन साहब, उनकी देन की वजह से और माननीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सोच है कि एक रोटी के चार टुकड़े करके मैं हरियाणा के हिस्से में बराबर बाटूंगा और कैप्टन अजय सिंह यादव को सिंचाई मंत्री बनाकर उन्होंने दक्षिणी हरियाणा में पानी पहुंचाया है। इससे पहले जो चीफ मिनिस्टर होते थे वे सारा पानी ढाई जिलों में ही दिया करते थे और सारा हर्रियाणा सूखे से तड़पता रहता था और हमारी आखों का पानी सूख गया था। आज कहते हुए हमें हर्ष 'खेता है कि नारनौल का जो राधेश्याम जी का क्षेत्र हे उस क्षेत्र में भो आज पानी पहुंच गया है। आज जो काम किया गया है वह माननीय

मुख्यमंत्री जी की सोच ने किया है और इन्होंने पानी का बंटवारा सही हिसाब से किया है।

श्री सभापतिः अनिता जी, वाईड अप कीजिए।

श्रीमती अनिता यादवः चेयरमैन साहब, मैं आधा मिनट और बोलना चाहती हूं इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

Mr. Chairperson: But not take more than half a minute.

श्रीमती अनिता यादवः चेयरमैन साहव. यहां पर पिछ्ली सरकार की वजह से रोड इतने खराब थे कि सड़क में इतने गड्ढे बने हुए थे कि मुझे पता नहीं लगता था। आज इस सरकार ने ऐसे रोड बना दिये थे कि हमने केवल टेलीविजन पर ही ऐसे रोड देखे थे अमेरिका जैसे रोड हम सोच भी नहीं सकते कि हम 20 मिनट में झज्जर आ जायेंगे। सारी उस हम टूटे रोड्ज पर चलते रहे। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश को नम्बर वन वनाने में जो रोड्ज की व्यवस्था इतनी खराब थी और इतनी गली सड़ी व्यवस्था इनको मिली थी उसके बावजूद रोड्ज को वनाने में इन्होंने इतना अच्छा काम किया है। उसके लिए मैं पी०डब्ल्यू०डी० मंत्री जी का भी धन्यवाद करती हूं और उनसे आग्रह करना चाहती हूं कि थोड़ा सा आप मैटीरियल ठीक लगायें ताकि रोड्ज बार–बार न टूट सकें।

Mr. Chairperson: No, please sit down. Your one minute has been completed.

श्रीमती अनिता यादवः चेयरमैन साहब, मैं पब्लिक हैल्थ के बारे में बोलना चाहती हूं। मुख्यमंत्री जी ने हरिजन भाइयों को सी और 200 लीटर की पानी की टंकी दी है उसके लिए माननीय

मुख्यमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करती हूं। यह एक सराहनीय कदम है।

Mr. Chairperson: Thank you, please sit down; यह सब लिखकर भिजवा देना, अब आप बैठ जाइये।

श्रीमती अनिता यादवः चेयरमैन साहब, आपको पता है कि हरिजन भाइयों को कितने लीटर की टंकी दी है और आज उनको सुचारू रूप से पानी मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहती हूं कि उनकी इस तरह की सोच से उठ बिरादरी को आज वे एक नम्बर पर लेकर परो हैं। मैं गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर पेश हुए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हूं और आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूं।

श्री राधेश्याम शर्मा अमरः चेयरमैन साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। आदरणीय वहन अनीता यादव यह कह रही थी कि हांसी बुटाना लिंक नहर के माध्यम से दक्षिणी हरियाणा को पानी पहुंचेगा। आज आप इस गरिमामय सदन की चेयर पर बैठे हुए हैं। आप इस समय इस हाउस के कस्टोडियन हैं क्या आप इनैलो पार्टी को यह आदेश देने को कृपा करेंगे कि ये उस नहर के पानी छोड़ने में बाधा न पहुंचाये और ये अपने साथी अपने अंकल बादल से मिलकर सुप्रीम कोर्ट में जो रिट डाली हुई है, उसको वापिस लें। सभापति महोदय क्या आप ये आदेश देने की कृपा करेंगे?

Being custodian of the House, it is expected from you that you must pass order that they should withdraw the writ petition.

श्री सभापतिः बलवंत सिंह सढौरा जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं?

श्री राधेश्याम शर्मा अमरः सभापति महोदय, ये इस बारे में क्या कहेंगे। हम आपसे आदेश चाहते हैं क्योंकि चेयर आदेश देती है।

श्री सभापतिः इनकी बात तो आने दो।

श्री बलवंत सिंहः सभापति महोदय, ये मेरे काबिल दोस्त हैं ये जानबूझकर इस प्रश्न को उलझाना चाहते हैं। हम इस नहर के बनाने के पक्षधर हैं कि नहर बनें लेकिन हमने पहले कहा था कि नहर को बनाने से पहले सबकी मंजूरी लो। प्रदेश का 582 करोड़ रुपया इसको बनाने में मिट्टी में बहा दिया है और यह अमाउंट अब तकरीबन 500 करोड़ के करीब पहुंचने वाला है। इसका नुकसान हरियाणा के लोगों को हुआ है। यह सरकार इसके लिए दोषी है न कि इनैलो पार्टी।

श्री सभापतिः मैं समझता हूं कि इनैलो पार्टी समान पानी के बंटवारे– के अगेंस्ट नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राधेश्याम शर्मा अमरः सभापति महोदय, आप हमारी बात नहीं सुनते। ये नहर बना रहे हैं और एक हमारा सदस्य

कहता है कि इन्होंने इतने पैसे मिट्टी में दबा दिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापतिः आप बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

बलवंत सिंहः सभापति महोदय, सरकार को चाहिए था कि नहर बनाने से पहले सबकी परमीशन ले क्योंकि यह तीन स्टेट्स का मामला है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापतिः आनरेबल मैम्बर्ज, आप बैठें। जब मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे तो सारी बात सामने आ जाएगी। (शोर एवं व्यवधान) मैंने इनैलो के साथियों के भाव को पढ़ते हुए यह महसूस किया कि समान पानी के बंटवारे के खिलाफ ये नहीं हैं लेकिन मुख्यमंत्री जी जब जवाब देंगे तो आपके सामने सारी बात आ जाएगी। (शोर एवं व्यवधान) श्री राधेश्याम शर्मा अमरः सभापति महोदय, ये साथी यहां कह रहे हैं कि 392 करोड़ रुपये मिट्टी में बहा दिए। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। (शोर एवं व्यवधान) सभापति महोदय, बताइए कि इससे बड़ी शर्म की कोई और बात हो सकती है?

श्री सभापतिः माननीय चीफ पार्लियांमैंट्री सैक्रेटरी बोलने के लिए खड़े हैं इसलिए आप सब बैंठें। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)

मुख्य संसदीय सचिव (श्री धर्मबीर): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। सतलुज और व्यास का पानी सारे दक्षिणी

हरियाणा और सारे प्रदेश में से केवल दा या ढाई डिस्ट्रिक्ट में ही जाता है। वहां सेम आ चुकी थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सरकार बनते ही तकरीवन साढे न करोड़ रुपये की लागत से हांसी बुटाना लिंक नहर बनवाई। सारे प्रदेश को इस चीज की बड़ी खुशी हुई और लोगों पै इस खुशी को एक त्यौहार के रूप में मनाया लेकिन बड़े दुख की बात है कि विपक्ष के चौटाला जैसे आदमी इस बात का विरोध कर रहे हैं। एक तरफ पीने का पानी नहीं जाता और दूसरी तरफ आपके इलाके में सेम आई हुई थी। इनको इस सदन में सारे प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए थी।

डॉ० सीता रामः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा था कि एस०वाई०एल० नहर बनाएंगे लेकिन आज 4 साल बीत गए हैं लेकिन उसको बनवाने का नाम ही नहीं है। ये केवल राजनीति करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धर्मवीरः अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने पड़ोस के पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के साथ मिलकर और भजनलाल के साथियों से मिलकर हाई कोर्ट में पंचायतों के प्रस्ताव दिए और इन लोगों ने ओब्जैक्शन लगाए कि हमारा पानी महेन्द्रगढ़, झज्जर, नारनौल और रोहतक में नहीं जाना चाहिए। यह बड़े शर्म की बात है और इसके लिए इनको प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट औफ आर्डर है। इनैलो पार्टी के किसी भी नेता ने यह नहीं कहा कि हम समान पानी के बंटवारे के खिलाफ हैं। लेकिन आज ये कहते हैं कि नहर बना रहे हैं। 600–700 करोड़ रुपये लगा रहे हैं। क्या इनके लिए यह जरूरी नहीं था कि इसको बनाने से पहले ये सबकी मंजूरी लेते।

डॉ० सीता रामः .....

श्री अध्यक्षः सीताराम जी जो कह रहे है वह रिकार्ड न किया जाए। Mr. Gian Chand Oadh, you may please resume discussion on Governor's Address.

डॉ० सुशील इन्दौराः .....

डॉ० सीता रामः .....

Mr. Speaker: Nothing is to be recorded. डा० इन्दौरा, आप कृपया करके बैठ जाइये क्योंकि आपकी पार्टी के मैम्बर श्री ज्ञान चन्द ओढ़ जी बोलने. के लिए खड़े हुए हैं। (शोर एवं व्यवधान) Gian Chandji, please resume the discussion on the Governor's Address. (Noises & Interruptions) ज्ञान चन्द ओह जी आप बोलिए।

श्री ज्ञानचन्द औढ (रतिया) (एस०सी०): स्पीकर सर, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि यह जो नहर की बात चल रही है

अगर सरकार पहले ही इसका सहो ढंग से समाधान करती और हायर अथारिटी से परमिशन ले ली जाती तो आज ये दिन नइकी देखने पड़ते। ऐसा करके इस सरकार ने एक बहाना लिया है कि हम नहर खोद लेंगे और पानी नहों मिलेगा तो लोकदल की सरकार आने की स्थिति में उस के०पर यह लांछन लग जायेगा कि वह हमारे द्वारा खोदी गई नहर में पानी नहीं ला सकी।

श्री अध्यक्षः ज्ञान चन्द जी, आप गवर्नर फैल पर बोलिए।

सिचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): सीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। स्पीकर सर, राधेश्याम जी ने जो बात रखी यह बिल्कुल सही बात है. कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि हांसी–बुटाना लिंक नहर बने। स्पीकर सर, श्री अजय सिंह चौटाला जो कि इनैलो पार्टी के राज्यसभा में सांसद हैं उन्होंने यह कहा था कि अगर हांसी–बुटाना लिंक नहर बनी तो गुह युद्ध हो जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मंत्री जी, जो लोग हाउस में नहीं हैं आप उनके नाम का जिक्र न करके ''कुछ लोग' शब्द कहो।

कैप्टन अजय सिंह यादवः ठीक है स्पीकर सर। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं इनेलो के साथियों को यह बताना चाहूंगा इस बारे में सैंट्रल वाटर कमीशन ने यह कहा है कि "The Project has been found in order from the inter-State angle." यह सैंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट है। (शोर एवं व्यवधान) सैंट्रल

वाटर कमीशन की रिपोर्ट में आगे यह लिखा है कि "The project authorities have been....."

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, ये साथी जो चर्चा कर रहे हें। मैं इनको बताना चाहूंगा कि एस०वाई०एल० और बी०एम०एल० हरियाणा के लोगों की लाईफ लाईन है। एक बहुत अहम् मुद्दा छै। जहां तक एस०वाई०एल० का सवाल है सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी अवार्ड और राजीव–लौंगोवाल समझौते को आधार बनाकर हरियाणा के हक में फैसला दे दिया है। विपक्ष के साथी मुझे यह बतायें कि राजीव–लौंगौवाल समझौते का विरोध किसने किया। अगर इनकी पार्टी और इनके नेताओं ने राजीव–लौंगोवाल समझौते का विरोध न किया होता तो एस०वाई०एल० का निर्माण कभी का हो जाता। एस०वाई०एल० के निर्माण में होने वाली देरी के लिए ये लोग, इनकी पार्टी और इनके नेता पूरी तरह से जिम्मेदार है। जहां तक हांसी–बुटाना लिंक नहर की बात है इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस परियोजना के तहत हमारी सरकार ने उपलब्ध नहरी पानी का न्यायोचित बंटवारा करते हुए दक्षिणी हरियाणा के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का निर्णय लिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं क्लीयर कह रहा हूं कि इनके नेता ने गोहाना में यह वयान दिया था कि यह नहर खुद गई तो गृहयुद्ध हो। तो मैंने यह वयान दिया था कि गृहयुद्ध की बात तो छोड़िये हम तो महायुद्ध के चर भी तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय ये साथी कह रहे थे कि 382 करोड़ रुपये मिट्टी में मिला दिये। मैं इस बात के लिए आज भी कह रहा हूं। इनके

नेता ने एक बार बयान दिया था कि हमारी सरकार आ गई तो हम 382 करोड़ रुपये की रिक्वरी इनसे करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं तो कहता हूं कि 382 करोड़ रुपये की दया बात है आखिरी छोर तक पानी देने के लिए मैं अपने प्राण तक देने के लिए तैयार हूं। (इस समय मेजें थपथपाई गइ)

डॉ० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कहो कि राजीव लौंगोवाल समझौते के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः डा० इन्दौरा, प्लीज, ऐसा है आप एक मिनट बैठिए, मैं आपको बताता हूं। इसमें आपने दो–तीन बातें उठाई थी कि कितना पैसा लगा और पानी के समान बंटवारे के बारे मैं कुछ कहा था। इस बारे में सदन के नेता ने पोजीशन क्लीयर कर दी है.। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, यह सुप्रीम कोर्ट का तथ्य है। सी०डब्ल्यू०सी० की रिपोर्ट माननीय मंत्री जी ने सदन में पढ़ी है। उसमें क्लीयर लिखा हुआ है कि हरियाणा अपने हिस्से का पानी यहां तक ले जा रहा है किसी और का हिस्सा नहीं स्के रहा है। यह तो पंजाब के साग मिल कर हरियाणा के खिलाफ साजिश रची जा रही है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Please resume the discussion on the Governor's Address. (शोर एवं व्यवधान)

डा० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, यह हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय है। सर, मैं राजीव लौंगोवाल समझौते की स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान) बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, हांसी–बुटाना लिंक नहर का निर्माण, केन्द्रीय हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा के लिए जीवन रेखा है। इसके निर्माण में सबसे बडा रोड़ा अगर कोई है तो इनके नेता और उनके बेटे हैं जो गृहयुद्ध की बात करते हैं। अध्यश महोदय, आज भी इस प्रकार की अनर्गल बातें कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जब एस०वाई०एल० का निर्माण हो रहा था तो इनके नेता ने इराडी ट्रिब्यूनल को साईमन कमीशन की संज्ञा दी थी। ये हमेशा ही हरियाणा के हितों पर कुठाराघात करते हैं। इनके नेता हमेशा ही हरियाणा के हितों को अपोज करते हैं। (शोर एवं व्यवधान) डा० सीता उनः अध्यक्ष महोदय, ये कैसी बातें कर रहे हें? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः डॉ० सीता राम जी, आपके साथी डॉ० इन्दौरा बोल रहे हैं, इसलिए आप शांत हो जाइये। डा० इन्दौरा, आप इनको चुप तो करवाओ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, शोर मचाने से सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। हरियाणा के लोगों के सामने इनकी कलई पूरी तरह से खुल गई है। इनका पर्दाफाश हो चुका है। (शोर एवं व्यवधान)

डा. सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, राजीव लौंगोवाल समझौते के तहत पंजाव और हरियाणा को 3.5 एम०ए०एफ० के बराबर का पानी मिला था। पहले समझौते में यह, था कि पंजाब और हरियाणा को बराबर का पानी मिलेगा। लेकिन बाद में राजीव लौंगोवाल समझौते में यह हुआ कि जो वर्तमान पानी पंजाब को दिया जा रहा है, वह पंजाब को मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, जब तक पंजाब का पानी घटेगा ही नहीं तो हरियाणा को पानी कैसे मिलेगा? फिर आप बताइये कि उसका विरोध करेंगे या उसका समर्थन करेंगे?

श्री अध्यक्षः सदन के नेता नै यह बात कही है कि एस०वाई०एल० को पूरा क्रने का जो फैसला लिया गया है, वह राजीव लौंगोवाल समझौते के आधार पर ही लिय' गया है कि यह कम्पलीट होनी चाहिए। सदन के नेता ने यही बात कही है। क्या आप सुप्रीम कोर्ट की भावना से वैरी करते हैं?

डा० सुशील इन्दौराः स्पीकर सर, राजीव–लौंगोवाल समझौते का विरोध हमने किया था और वह विरोध इसलिए किया था क्योंकि हमारा पानी का हिस्सा पंजाव को दिया जा रहा था और हमारे इलाके भी पंजाब को दिये जा रहे थे। (विघ्न अगर हम उसका विरोध न करें तो बताइये फिर हम यहां पर किस लिए बैठे हुए हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः डॉ० साहब, वह एक अलग बात है। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। (विघ्न) स्पीकर सर, यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। इनके नेता ने उस समय राजीव–लौंगोवाल समझौते का विरोध किया था। क्या यह सच नहीं हे कि इनके नेता ने इराडी कमीशन को काले झण्डे दिखाए थे और उसको साईमन कमीशन की संज्ञा दी थी। इराडी कमीशन का उन्होंने विरोध किया था और इराडी कमीशन का बहिष्कार किया था। यह कांग्रेस पार्टी की सरकार ही थी जो 3 .6 मिलियन एकड़ फुट नहीं बल्कि 3.58 मिलियर एकड़ फुट पानी जीत कर लाई थी। स्पीकर साहब, माननीय साथी को शायद पूरे फैक्ट्स मालूम नहीं हैं। (विघ्न एवं शोर)

Mr. Speaker: Please, now resume the discussion on the Governor Address. पलाका साहब, अब आप गवर्नर एड्रैस पर बोलें। (विघ्न एवं शोर)

डॉ० सुशील इन्दौराः स्पीकर सर, ...

Mr. Speaker: Nothing is to be recorded. इन्दौरा जी आप बैठें। resume the discussion, please take your seats. (विघ्न) पलाका साहब, अब आप गवर्नर एड्रैस पर बोलें।

श्री ईश्वर सिंह पलाका (रादौर) (एच०सी०): स्पीकर साहब, आपने मुझे गवर्नर एड्रैस पर बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। सर, महामहिम राज्यपाल

महोदय के अभिभाषण को मैंने बड़े गौर से पड़ा है लेकिन मुझे कहीं यह नजर नहीं आया कि सरकार हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए कोई खास जन–कल्याणकारी नीतियां बना पाई है। गवर्नर एड्रैस मॅ यह होता है कि सरकार लोगों को क्या–क्या सुविधाएं देना चाहती हे और सरकार की मन्शा क्या है। सरकार की नीति और नीयत क्या है इसकी झलक भी इससे मिलती है। स्पीकर सर, गवर्नर एड्रैस में वर्ष 2009 को मजदूर किसान वर्ष मनाने की चर्चा की गई है। सर, आज किसान की हालत सबसे ज्यादा खराब है। हरियाणा प्रदेश में बिजली की बहुत बुरी हालत है। आज सर्दी के मौसम में भी बिजली मुश्किल से दो घण्टे आती है और उसमें भी कई–कई बार ट्रिपिंग होती है। (विघ्न) क्योंकि हमारे इलाके में सिंचाई टयूबवैल्ज से होती है जब बिजली आएगी तभी किसान को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। बिना विजली के न तो मजदूर का काम चलता है, न का काम चलता है और न ही व्यापारी का काम चलता है। स्पीकर सर, बिजली ही एक ऐसा साधन हैं जिससे हम सिंचाई कर सक्ते हैं। (विघ्न)

अति विशिष्ट व्यक्तियों का अभिनंदन

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, वी०आई०पी० गैलरी में श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा, सांसद एवं श्री कुलदीप शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी मौजूद हैं मैं सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ। (विघ्न)

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

श्री ईश्वर सिंह पलाकाः पिल्ले दिनों किसानों की जीरी औने–पौने दामों पर खरीदी गई। किसान कई–कई दिनों तक मण्डियों में पड़े रहते थे। (विघ्न) स्पीकर सर, ये लोग मेरी बात सुनना नहीं चाहते हैं। (विघ्न)

श्री रमेश गुप्ताः स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मैं आपके माध्यम से सदन में यह बताना चाहता हूँ कि पलाका जी बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। जीरी के किसानों को ठीक दाम मिले है। (विघ्न)

श्री ईश्वर सिंह पलाकाः स्पीकर सर, हमने सरकार से प्रार्थना की थी कि 1121 नम्बर धान को बासमती में कन्वर्ट कर दें। लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। स्पीकर सर, इसके अलावा मैं सदन में यह कहना चाहता हूं कि जब जीरी किसानों के हाथ में थी जब तक उस पर टैक्स लगाए रखा जैसे ही जीरी उनके हाथ से निकल गई तो उस पर से टैक्स हटा लिया गया। स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में आश्वासन दिया था कि ये धान की किस्म नश्वर 1121 को बासमती में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन इन्होंने अपना वह वायदा पूरा नहीं किया है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, मैं अन्पके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि हमने अपना वायदा पूरा कर दिया है और यह इनको पता नहीं है।

श्री ईश्वर सिंह पलाका: स्पीकर सर, आज किसान लाडवा में आलू की ज्यादा फसल लगाते हैं। जब किसान आलू की फसल ट्रैक्टर में लाद कर मण्डियों में बेचने के लिए जाता है तो मण्डियों में उसकी एक बोरी 80 रुपये से कम में खरीदी जाती है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: आप इस बारे में क्या सुझाव देना चाहते हैं जिससे कि इस बारे में इम्प्रूवमैंट हो सकती हो।

श्री ईश्वर लिह पलाका: मेरा इस बारे में यह सुझाव है कि किसान को उसकी फसल का उचित दाम मिलना चाहिए। आज अपने आपको किसानों की हितैषी कहलाने वाली यह सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही हैं। आज जो किसान सूरजमुखी की फसल पैदा करता है, आज उसमें सूरजमुखी के बीज लेने के लिए त्राहि–त्राहि मची हुई है। यह बड़े शर्म की बात है। आज हम किसान को समय पर बीज उपलब्ध नहीं करवा सक्ते हैं, समय पर बिजली नहीं दे सक्ते हैं किसान को समय पर खाद नहीं मिलती है। स्पीकर सर, मैं डी०ए०पी० खाद के लिए मार्किटिंग प्रोसैसिंग कमेटी जगाधरी में चला गया वहां पर मुझे 10 किसान मिले। (विष्य)

श्री अध्यक्षः आप कितने किल्ले के जमीदार हैं।

श्री ईश्वर सिंह पलाकाः स्पीकर सर, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वहां पर किसान मुझे कहने लगे कि हमें रा शन कार्ड पर दो कट्टे खाद ही मिलती है जिससे उनकी जरूरत पूरी नहीं होती है। स्पीकर सर, आज किसान को जब खाद और दवाई की जरुरत होती है तो वह ब्लैक होनी शुरू हो जाती है। (विघन) स्पीकर शर, आज ब्लैक माकिर्टिंग करने वाले लोग कौन हैं वे लोग ३ हैं। जो समय पर किसानों को सुविधा मुहैया होने नहीं देते हैं। (विघ्न)

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): स्पीकर सर, इन्होंने जो 'शब्द का प्रयोग किया है उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री अध्यक्षः इस शब्द को कार्यवाही से निकाल. दिया जाए।

श्री ईश्वर सिंह पलाकाः इसमें इनैलो का कोई भी नहीं है कृ ने सारा भट्ठा बिठा दिया है। आज किसान और मजदूर त्राहि–त्राहि कर रहे हैं। आज महंगाई की वजह से बहुत बुरी हालत है। (विघ्न) स्पीकर सर मैंने पिछले सत्र में भी रेट लिस्ट पढ़कर सुनाई थी। इसके बारे में मुझे मेरे हल्के के लोग मिलते हैं और कांग्रेस के साथियों को भी मिलते होंगे। स्पीकर सर, हरियाणा में पीले कार्डज की बहुत ही बुरी हालत है। जिन लोगों

को पीले कार्डज की जरूरत होती है उनको तो मिलते नहीं है और जिन लोगा को जरूरत नहीं हे उनके पीले कार्ड सिफारिश के द्वारा बना दिए जाते हैं। (विघन) इनके राज में गरीब आदमी को मार दिया गया है, वह गरीब आदमी दो रोटी के लिए तरस रहा है। आज इस सरकार के द्वारा बड़ा प्रचार किया जा रहा है कि दलित लोगों को प्लाट देंगे। हमें कुछ समझ नहीं आता है कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। (विघन)

Mr. Speaker: Dr. Indora, don't tutor the member. आप उनको टयूट कर रहे है। (विघन) ऐसे नहीं डाक्टर साहब, आपने अपना बोलने का पूरा समय लिया है। (विघ्न) श्री ईश्वर सिंह पलासः स्पीकर सर, आज मजदूरों और किसानों को यार–बार सड़कों पर संघर्ष करना पड़ता है। इस बारे में आप भी अखबारों में पढ़ते होंगे। आप भी जब सड़क से आते होंगे तो जाम में फंस जाते होंगे। (विष्य)

श्री अध्यक्षः हम कभी नहीं फंसे हैं।

श्री ईश्वर सिंह पलाकाः स्पीकर सर, आपके पास तो. पायलट गाडियां हैं और आप हुटर मार कर जल्दी निकल जाते होंगे लेकिन हम तो जाम में फंस जाते हैं। सीकर सर, आज किसान और मजदूर का बहुत बुरा हाल है और इनको दो वक्त की रोटी भी नही मिलती है। बिजली के मामले में जहां तक बात है बिजली की हालत खराब है। सर, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि आज तो एक नाई का काम भी बिजली के

बिना नहीं चलता है। एक नाई मेरे को मिला मैंने उससे पूछा कि तेरा काम कैसे चल रहा है वह कहने लगा कि बिजली ही नहीं है। मैंने उससे कहा कि यह कांग्रेस की बिजली है मुझे पता नही कि यह आएगी भी या नहीं आएगी।

श्री अध्यक्षः क्या आप वहाँ पर दाढ़ी बनवाने के लिए गये थे?

श्री ईश्वर सिंह पलाकाः नहीं सर, वैसे ही फिल गया था लेंकिन कभी–कभी नाई सं भी दाढ़ी मनवानी पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक घंटा वेट करके वापस घर आ गया लेकिन बिजली नहीं आयी। शाम को जब खाना खाने का वक्त होता है तो उस वक्त भी लाईट नहीं होती है। इस तरह से आज बिजली की प्रदेश मैँ यह हालत है। मैं आपके माध्यम से बिजली मंत्री से कहना चाहता हूं कि जब गांवों में कोई ट्रांसफार्मर सह जाए तो उसको 24 घंटों के अंदर ही बदल देना चाहिए।

श्री अध्यक्षः पलाका साहब अब आप कंक्लूड करें। आपको बोलते हुए दस मिनट हो गये है।

श्री ईश्वर सिंह पलाकाः सर, मैंने तो अभी बोलना ही शुरू किया है। अभी तो मैंने बहुत कुछ बोलना, से। मैं तो आज पूरी तैयारी करके आया हूं क्त तो मेरे को टाईम ही नहीं मिला था।

श्री अध्यक्षः आप अपने हल्के की मोटी–मोटी बात बता दें।

श्री ईश्वर सिंह पलाकाः स्पीकर साहब, जहां तक ट्रांसपोर्ट की बात है परिवहन मंत्री जी बैठे हैं। मैं एक अखबार की कटिंग सबूत के तौर पर लेकर आया हूं। मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारी आने वाली भविष्य की पीढ़ी है उसकी क्या हालत है। हमारे जो बच्चे इंजीनियरिंग या पोलिटैक्निक कर रहे हैं उनको आने–जाने के लिए बस की सुविधा नहीं है। यह बड़े शर्म की बात है कि हम उनको ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी नहीं दे पा रहे हैं।

श्री अध्यक्षः शर्म और बेशर्म शब्द क्या आपकी डिक्शनरी में हैं?

श्री ईश्वर सिंह पलाकाः स्पीकर साहब, आज भी वे मैक्सी कैद में लटक–लटक कर जाते हैं क्योंकि हम उनको ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं दे पाए हैं। वे मैक्सी कैबों में लटक कर अपने कालेज जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक अखबार की कटिंग आपके पास भिजवा रहा हूं। यह अखवार मेरा छापा हुआ नहीं है। जो हमारे बच्चे इंजीनियर बनने जा रहे हैं, जो हमारे बच्चे डाक्टर बनने जा रहे हैं तो क्या वे बस की छत के०पर बैठकर पढ़ने के लिए जाएंगे? वह हमारे से क्या उम्मीद कर सकते हैं। स्पीकर साहब, मैं यह अखबार आपकी अनुमति से सदन में पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

Mr. Speaker: Palaka ji, newspaper reading is not allowed in the House. आप डाक्टर इंदौरा जी से भी पूछ लो कि क्या रीडिंग अलाउड है? डॉक्टर इंदौरा इस मामले में एक्सपर्ट हैं।

डा० सुशील इन्दौराः सर, मैं अपने सदस्यों को ठीक गाईड करता हूं क्योंकि यह मेरी मोरल डयूटी भी है।

श्री अध्यक्षः ठीक है।

श्री ईश्वर सिंह पलाकाः अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के मामले में कहा जाता है कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा के बिना इंसान पशु समान होता है।

श्री अध्यक्षः शिक्षा के बारे में तो गुप्ता जी ने एक घंटा जबाव दे दिया है।

श्री ईश्वर सिंह पलाकाः जितनी ज्यादा से ज्यादा कोई एजूकेशन कोई हासिल कर लेता है उसका उतना ही सम्मान बढ़ता चला जाता है। लेकिन आज हरियाणा में प्राथमिक स्कूलों में और उच्च विद्यालयों में .अध्यापक ही नहीं हैं। मैं भी गांव के एक स्कूल में पड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्षः पलाका जी, इस बात का जबाव आ गया था। गैस्ट टीचर्ज की पॉलिसी सदन के नेता ने अनाउंस की है तथा दूसरी जो वैकेंसीज खाली पड़ी हैं उनके बारे में गुप्ता जी ने बता दिया है।

श्री ईश्वर सिंह पलाकाः स्पीकर साहब, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका तो टाईम निवस्त्र जाएगा, उनका टाईम कब वापस आएगा? ये पॉलिसी बनाते बनाते ही रह जाएंगे लेकिन बच्चों का टाईम तो खराब होने लग रहा है। यदि कोई सांप निकल जाएं और हम यदि उसकी लकीर को ही पीटते रह जाएं तो यह अच्छा नहीं लगता, इसलिए सरकार को इस बारे में ठोस कदम उठाने चाहिएं।

श्री अध्यक्षः गुप्ता जी, टीचर्ज की वैकेंसीज के बारे में इनका सुझाव है इसलिए आप इस बारे में ठोस कदम उठाए।

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता): स्पीकर साहब, हम जल्दी से जल्दी इन पोस्ट्स को भर रहे हैं।

श्री ईश्वर सिंह पलाकाः स्पीकर साहब, जल्दी नहीं बल्कि मुख्यमंत्री जी सदन में आश्वासन दें कि एक हफ्ते के अंदर–अंदर हम किसी भी प्राईमरी स्कूल में टीचर्ज की पोस्ट खाली नहीं रहने देंगे।

डॉ० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने गैस्ट टीचर्ज के बारे में कहा था। मैं कहना चाहता हू कि सरकार के पास तो बहुत अच्छा प्रावधान होता है। यदि सरकार कोई काम हरियाणा के हित के लिए करना चाहती है तो वह एफ आडीनैंस ले आती है और फिर उस बारे में कानून बना देती है। क्या गैस्ट टीचर्ज के बारे में भी सरकार कोई

आडर्निस लाकर कानून नहीं बना सकती है। सर, अगर हम प्रदेश हित की बात करें तो सरकार ऐसा कर सकती है।

श्री मांगे एम गुप्ताः स्पीकर साहब, मैं समझता था कि इंदौरा साहब बहुत काबिल पार्लियामैंटेरियन हैं परन्तु मुझे आज यह पता चला कि यह काबिल भी नहीं है बल्कि अनपढ़ है। सर, यह आर्डीनैंस की बात नही थी। (विघन)

श्री अध्यक्षः गुप्ता रुपी, इनका सुझाव आ गया है। इनकी सारी बातों का जबाव देना जरूरी नहीं है इसलिए आप बैठें। ये तौ कहने लग रहे हैं इनकी सारी बातों का जवाब जरूरी न ही है।

श्री ईश्वर सिंह पलाकाः स्पीकर साहब, इसी तरह से प्रदेश को सड़कों का भी बुरा हाल है।

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर साहब, माफ करना, हमने हाउस में यह कहा है कि अगर किसी एम०एल०ए० के पास इनको रैगुलर करने का कोई लीगल रास्ता है तो उसके बारे में वह हमें बता दैं, हम वैसा ही कर देंगे। आप हमें वह तरीका दें।

डॉ० सीता रामः मंत्री जी, आप इस बारे में हमें यस' और जो' में बताइए।

श्री मांगे राम गुप्ताः हम हाउस में विश्वास दे रहे डे कि हम ये करना चाहते हैं। **मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा):** डा०

सीताराम जी एक और रास्ता है यदि आप आज अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दें तो हम आपको टिकट दे देते हैं।

डॉ० सीता रामः अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरे क्षेत्र की जनता ने चुनकर भेजा है और मैं उनके प्रति पूरी तरह से जवाबदेह हूं और बदलूंगा नहीं।

Mr, Speaker: Hon'ble Members, please don't waste the time ofthe House. Please resume the discussion on the Governor's Address.

श्री ईश्वर सिंह पलाकाः ऐजूकेशन मिनिस्टर भी बैठे हैं यदि वे चाहें तो कोई भी स्कूल बिना अध्यापक के नहीं रह सकता। जहां अध्यापक नहीं हैं वहां अब भी दोबारा से गैस्ट टीचर लग सकते हैं।

श्री अध्यक्षः ईश्वर सिंह पलाका जी, आपको बोलते हुए 15 मिनट का समय हो गया है।

श्री ईश्वर सिंह पलाकाः मेरे हल्के में जो जस स्टैण्ड है उसकी हालत वहुत ज्यादा खराब है। मैंने पिछले सत्र में भी मंत्री महोदय से कहा था। वहां लोग खड़े होते हैं और यदि ऐसे में वह गिर जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। सर, आप मंत्री महोदय को आदेश करें और तहां नये दस स्टैण्ड का निर्माण किया जाए। सर, ग्रामीण के बारे में हमने तो अपने हल्के के बारे में मुख्यमंत्री जो

से भी मांग को कि हमें भी पैसा दो। वह क्षेत्र विकास के मामले में न के बराबर है। कहीं भी विकास नहीं दिखता।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, विधायक जौ कभी भी मेरे पास नहीं आए कि मेरा यह काम कर दो। पलाका जी, आप लोगों को गुमराह न करो।

श्री ईश्वर सिंह पलाका: अध्यक्ष महोदय, हम लोग इकट्ठा हो कर गए थे। रादौर में अस्पताल है लेकिन वहां एक भी डॉक्टर नहीं है। स्पीकर सर, सरकारी अस्पताल में कौन जाता है इलाज के लिए। गरीब लोग जाते हैं और जब डॉक्टर नहीं मिलर? तो मायूस होकर लोट आते हैं। सर, हर बार सदन में यह सुनने को मिलता है कि डॉक्टरों की भर्ती कर पेड़ हैं। आखिर कब भर्ती करेंगे, जब सरकार चली जाएगी तव भर्ती करेंगे। वहां एक्स–रे मशीन ठीक पडी है मेंने सी०एम० ओ० को कहा, मंत्री महोदय को भी कहा लेकिन उसके बावजूद भी वहां कोई रेडेयोलाजिस्ट या ऐक्सरे मशीन ऑपरेटर नही आया। यह बात दो साल पहले की है। सरकार स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं है। आजादी के 60 साल बाद भी हम लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधायें नहीं दे पाएं हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए जो उमरा दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री नरेश यादव (अटेली): अध्यक्ष महोदय, छ तारीख को महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो यहां अभिभाषण दिया उस पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। जो आपने मुझे समय दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद करटा हूँ। सर्वप्रथम तो एक फरवरी, 2009 को संविधान सभा के एकमात्र जीवित सदस्य चौधरी रणबीर सिंह को मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। किसी मौके पर श्री वी०पी० सिंह जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका व्यक्तित्व बहुत ही ईमानदारी का था। मुझे खुशी है कि जो सपना चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी और श्री वी०पी० सिंह जी ने देखा वह माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया हैं माननीय श्री वी०पी० सिंह जी के सास हमने एस०ई०जैड० मूवमैंट मै०पर दो–तीन मीटिंग की थी उनकी इच्छा थी कि अगर किसान की जमीन अधिग्रहण होती है तो किसानों के पास कुछ मालिकाना हक जरूर होना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी कन धन्यवाद करता हूं कि जो चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी और माननीय श्री वी०पी० सिंह जी की इच्छा थी तह उन्होंने पूरी की है कि आज जय किसान की जमीन का अधिग्रहण किया जाता है तो किसान का उस जमीन पर मालिकाना हक रहे उसे 33 साल तक 30 और 15 हजार रुपये प्रति एक्क के हिसाव से प्रति वर्ष दिए जाने का फैसला किया है। आज एस०ई०जैड० के बारे में– उत्तरप्रदेश, वैस्य बंगाल, मुम्बई और देश के अन्दर अनेक जगहों पर मूवमैंट हुआ। लेकिन किसी सरकार ने किसान के बारे में नहीं सोचा कि अगर उसकी जमीन अधिग्रहण होती है तो उस एरिया में रहने वाले किसान का क्या होगा। उसके बुढापे का

सहारा कौन बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों की मांग को स्वीकार करके बहुत क्त कार्य किसानों और देश के हित में किया हैं। राजस्थान में हम गये थे वहां पर भी किसानों का यह मुद्दा था कि हमें हरियाणा की तर्ज पर किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा दिया जाए ताकि आने वाले कई वर्षो तक उस जमीन का पैसा मिलता रहे। वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी है और वहां की सरकार ने हरियाणा की पॉलिसी को असैप्ट किया है। पूरा देश इस बात पर विचार कर रहा है कि हरियाणा की तर्ज पर एक पॉलिसी वनाई जाए ताकि किसानों की जमीन अगर अधिग्रहण होती है तो उस किसान को मालिकाना हक 33 साल तक प्रति वर्ष 30 या 15 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मिल सके। हो सकता हैं माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले वर्षो में इस अवधि को और बढ़ा दें। इसी प्रकार से पानी के बंटवारे के बारे में सदन में लगातार बहस होती रहती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा कि दो बातों पर बहस होकर खत्म हो जाती है कि हांसी बुटाना लिंक नहर और सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण में देरी क्यों हो रही है। इसके वारे में कानूनी प्रक्रिया क्या है क्या स्थिति है यह तो सिंचाई मंत्री महोदय ही इस बारे में बता पायेंगे। जहां तक हांसी बुटाना लिंक नहर बनाने की बात है यह बिल्कुल सीधा नक्शा है इसके बारे में अपोजिशन के भाई पद यात्रा निकाल रहे हैं। इससे पहले हमने किसानों की पद यात्रा राष्ट्रपति भवन तक निकाली थी और हमने गोद बलावा गांव के अलावा 250 गांवों में जहां का वाटर लेवल

एक हजार से 1600 फीट नीचे चला गया है जहां पीने के पात्रो की बड़ी किल्लत है उस बारे में हजारों किसानों के साथ इस मुद् दे को लेकर राष्टपति भवन तक गये थे। उस समय हमने अपोजीशन के भाइयों को कहा था कि अगर आप दक्षिणी हरियाणा या हरियाणा के के बारे में कोई सिम्पैथी रखते हैं तो हमने राष्ट्रपति जी से इस बारे में मिलने का टाईम ले रखा है आप भी हमारी पद यात्रा में शामिल हो जाइये लेकिन इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज जय चुनाल नजदीक आ रहे हैं तन ये पद यात्रा निकाल रहे हँ लेकिन महेन्दगढ–भिवानी जो लाक सभा चुनाव का हल्का बना है। वहां के लोगों ने पूर्ण रूप से इनकी पार्टी को बैगलैक्ट कर दिया उसके बाद एक–एक गांव में चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी और उनके बेटे अजय चौटाला जी घूम–घूम कर आये। जब बिल्कुल जनता का समर्थन नहीं मिला तब पैदल चलने का ढोंग रखा उसमें भी वहां के लोगों ने इनको बिल्कुल नैगलैक्ट कर दिया है। मैं वित मंत्री और माननीय. मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वहां के 350 गांवों में जहां वाटर टेबल नीचे चला गया है उनके लिए बजट में विशेष प्रावधान किया जाए और जहां वाटर टेबल नीचे चला गया है उसको दोबारा से रिचार्ज किया जा सकता है। हांसी बुटाना लिंक नहर के पानी को लाने के लिए रोड़ा है उसके लिए सरकार कोई इंतजाम करे। हम चौटाला और प्रकाश सिंह बादल की राजनीति का शिकार हो रहे हैं। बादल के खेत में भी पानी की कमी नहीं है और चौटाला के खेत में भी पानी की कमी नहीं है लेकिन इसका

खामियाजा हमारे हरियाणा के 10–12 जिले भुगत रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि फैसला जब होगा शा नहीं होगा लेकिन इसके लिए कठोर कदम उठाए जाएं। हरियाणा की जनता इस पानी के लिए बाट जोह रही है। मुख्यमंत्री महोदय को कोई तरीका अपनाना चाहिए कि यह पानी हरियाणा के खेतों में पहुंचे। अध्यक्ष महोदय, एस०वाई०एल० का मामला वहुत समय से लम्बित है। इस नहर की मरम्मत पर हमारी सरकार भारत सरकार पर या जो भी एजैन्सीज हैं उन पर दबाव डलवाए और इस काम को करवाए।

श्री अध्यक्षः यादव साहब, आप बाकी लिखवाकर भिजवा दें वह इनकारपोरेट कर लिया जाएगा।

श्री नरेश द्वार प्रधान (बादली): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपने आपको राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के साथ जोड़ता हूं। श्री रणबीर सिंह जी का निधन एक फरवरी 2009 को हुआ, इससे देश और प्रदेश को जो क्षति हुई है उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। उनका निधन पूरे राष्ट्र के लिए एक शोक था। श्री रणबीर सिंह जी एक सच्चे राष्ट्र भगत थे जिनके निधन पर हम सब शोक प्रकट करते हैं तथा शोकाकुल परिवार को और शोक संतप्त परिवार को अपनी हार्दिक सांत्वना प्रकट करते हैं। उन्होंने हरियाणा की उन्नति और प्रगति के लिए बहुत कार्य किए। उन्हीं की नीतियों पर चलते हुए हम हरियाणा की प्रगति और उन्नति के लिए कार्य करें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते

हुए हरियाणा के उत्थान में योगदान दें। राज्य की कुल कृषि आय में पशु पालन क्षेत्र का एक तिहाई से भी अधिक का योगदान है। ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में सरकार ने जो महत्वपूर्ण कार्य किए हे उनके लिए सरकार बधाई की पात्र है और मैं इसके लिए सरकार को बधाई भी देता हूँ। लोगों के घर द्वार तक आज पशु चिकित्सा की सुविधा है। 2008–09 के दौरान 80 पशु चिकित्सा संस्थानों का दर्जा बढाने और नए पशु चिकित्सा संस्थान खोलने की सरकार की जो योजना है उससे ग्रामीण क्षेत्र का जो किसान है काफी लाभ पहुंचेगा। चालू वित्त वर्ष में भिवानी और सोनीपत में पाली क्लीनिक चालू किए जा रहे हैं जो किसान के लिए हर्षोल्लास की बात हैं। हमारी सरकार उच्च कोटि की नस्ल के और अधिक दूध देने वाले पशुओं की खरीद कर रही है। हरियाणा में पशुओं की मुंहखुर जैसी बीमारी के नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे किसानों को काफी लाभ हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जन हित में मेरा एक सुझाव है कि सरकार ने जो सफल प्रयास किए हैं, वे अच्छे हैं लेकिन कुछ ऐसे .....

श्री बलवन्त सिंहः स्पीकर सर, माननीय सदस्य को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बलवन्त सिंह जी, माननीय सदस्य ने किसी का नाम नहीं लिया है। (शोर एवं व्यवधान) प्लीज, आप बैठ जायें और इस बारे में मेरी रूलिंग सुनें। माननीय सदस्य श्री नरेश शर्मा जी की बातों से अगर किसी माननीय सदस्य की फीलिंग आहत

हुई हो तो माननीय सदस्य की स्पीच के उस हिस्से को हाउस की कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

श्री नरेश कुमार प्रधानः स्पीकर सर, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है मैंने तो सिर्फ पशुओं की एक विशेष नस्ल के बारे में बात की है। स्पीकर सर, मैंने जो बात की है वह जनहित के दृष्टिगत कही है और मैं अभी भी उस पर कायम हूँ।

Mr. Speaker: Naresh Sharma Ji, please continue your speech on Governor's Address.

श्री नरेश आर प्रधानः स्पीकर सर, मैंने किसी सदस्य विशेष का नाम नहीं लिया है। फिर भी अगर कोई माननीय सदस्य अपने आपको या अपने किसी नेता को ..... समझ रहा है तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है।

डॉ० सुशील इन्दौराः स्पीकर सर माननीय सदस्य ने जो आपत्तिजनक शब्द प्रयोग किये हैं आप नन्हें कृपा करके हाउस की कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अध्यक्षः इन्दौरा जी, श्री नरेश जी ने जो ऐसे शब्द प्रयोग किये हे जिनसे किसी की फीलिंग आहत हुई हों उन्हें सदन की कार्यवाही से निकलवा दिया गया है। अब आप चीज बैठें।

डॉ० सुशील इन्दौराः धन्यवाद, स्पीकर सर।

Mr. Speaker: Yes, Mr. H.S. Chatha Ji, what would you like to say?

12.00 बजे

कृषि मंत्री (सरदार एच०एस० चट्ठा): स्पीकर सर, गवर्नर एड्रैस पर बोलते हुए मेरे क्य भाइयों ने एक तो पैडी की बात की, एक पैरटीसाईड की बात की और एक स्प्रिकंलर वगैरह की नालियां खरीदने की बात की है। जहां तक पैडी की बात है बहुत अच्छा होता अगर अपोजीशन के भाई यह बात कहते कि पिछले दो साल से जितना पैडी का रेट किसान को मिला है उतना पिछले 60 साल में कभी नहीं मिला। मुझे याद पर्दे कि जब 1121 का ऐक्सपोर्ट बंद हुआ था तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री विदेश के दौरे पर थे। उनको वहां पर जब 1121 के ऐक्सपोर्ट पर पाबंदी का पता चेला तो इन्होंने अपना टूर कैंसिल कर दिया। मुझे आदेश दिये कि मैं दिल्ली पहुंच जाऊं। मुख्यमंत्री जो एयरपोर्ट से सीधे प्रधानमंत्री रुपी से मिलने गये और उसको बासमती की वैरायटी मँ शामिल करवाकर पुनः उसका ऐक्सपोर्ट शुरू करवाया और फिर से 1121 की कीमत पहले जैसी हो गई। इस प्रकार का काम आज तक के किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस प्रयास के लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। इस दफा भी क्या हुआ कि 1121 को बासमती में काऊंट नहीं किया गया। इस बात के खिलाफ न तो पंजाब ने, न दिल्ली वालों ने, न उत्तर प्रदेश वालों ने ही कोई आवाज उठाई। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात उठाई कि यह बासमती है और यह वैरायटी एक्सपोर्ट होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने अपनी पर्सनल कोशिश के साथ

1121 को बासमती डिक्लेयर करवाया और जिसका किसानों को 3400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब सै मूल्य मिला। बासमती की वैरायटी नम्बर 1121 का आज जो इतना अधिक रेट हमारे किसानों को मिल रहा है यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सदप्रयत्नों का ही परिणाम है। इसके लिए हम सभी को उनका दिल से आभार व्यक्त करना चाहिए। स्पीकर सर, मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि बासमती का यह रेट माननीय मुख्यमंत्री जी की ही देन है। जब वह बासमती डिक्लेयर हो गई तो बाद में रेट कम हो गये। रेट कम होना वर्ल्ड फिनोमिना रहा है। जिन्होंने कांट्रैक्ट बाहर दिये हुए थे उनके कांट्रैक्ट पूरे हो गये इसी वजह से रेट 1900 रुपये प्रति क्विंटल हो गया और बाद में 2300 रुपये प्रति क्विंटल पर आ तया है। लेकिन बारिश की वजह से कुछ पैडी डैमेज हुई है। जहां तक ये साथी कहते हैं कि कई–कई दिन तक पैडी नहीं उठी यह कतई गलत बात हैं में मंडियों में रहा हूँ और मैंने देखा है कि जिस भाई की जीरी शाम को 4 बजे तक मंडी में पहुंच गई उसकी उसी दिन तुलाई होकर बोंरियों में भर कर स्टोर पर पहुंच जाती थी। कभी भी कोई किसान अपनी जीरी कौ वजह से रात को मंडी में नहीं सोया वह अपने घर जा कर सोया है। अगले .दिन हम देखते थे तो मंडी में जगह खाली मिलती थी। पिल्ले कई सालों से हम देख रहे हैं कि गेहूं के सीजन में भी किसान इसी प्रकार रात को अपने घर ही सोया है उसको अपने गेहूं के लिए रात को मंडी में नहीं रुकना रक्षा हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने वह समथ भी देखा है कि जय किसान हफ्ते–हफ्ते तक मंडियों में पड़ा रहता था

लेकिन उसकी फसल की बिक्री नही होती थी। वह एफ०सी० आई० के अधिकारियों के चक्कर लगाता था कि मेरी जीरी खरीद लो और कोई खरीदता भी नहीं था। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अब तो युग ही ऐसा आ गया है कि जिसकी जीरी शाम को 4 बजे मक मंडी में पहुंच गई तो उसकी बिक जाती हैं और वह आराम से वर जाकर सोता है। पैडी के मावल में एक किसान के तौर पर मैं सहमत हूं। एक बात और कहना चाहूंगा कि जो मोटी पैडी है जो बासमती नहीं है उसकी लॉंग डूरेशन है। हमारी जमीन के नीचे पानी कम हो रहा है! इस बात पर माननीय मुख्यमंत्री –न भी हमें कुछ आदेश दिये हैं कि किस तरह से पानी को प्रिजर्व किया जा सक्ता है। पानी का घाटा किस तरह से कम किया जाये। उसी के तहत हमारे किसानो ने साठी जीरी की पैदावार वंद कर दी। हिन्दुस्तान में हरियाणा ही वह सूबा है जहां साठी की खेती बाई परसुएशन बंद की है। बाई परसूऐशन हमने किसानों को कहा कि आप साठी जीरी ना लगाओ और मैं किसानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुख्य मंत्री जी की बात को मानते हुए सीठी जीरी की खेती करनी बंद कर दी। अध्यक्ष महोदय, इन भाइयों ने दूसरी बात पेस्टीसाईड की कही हैं। मैं मानता हूँ कि 2 साल पहल पेस्टीसाईड में गड़बड़ी थी। ख्य भाइयों के गेहूँ, जल गये थे हमने उन विक्रेताओं के लाईसैंस रद्द कर दिये थे और वे अपील में चले गये जहाँ से उनको राहत मिल गई। उन विक्रेताओं से किसानों को पैसा दिलवाया। अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने आढतियों की मार्फत जीरी खरीदी हुई थी उनको भी पैसा दिलवाया। अध्यक्ष

महोदय, मुश्किल से 5– 10 परसैंट किसान ऐसे. हैं जिनके हमने अदालत में केस डलवाये, उनमें से. क्य के फैसले हो गये 'और क्य के. केस अभी चल रहे हैं। लेकिन हमने कोशिश की है कि किसान को ज्यादा नुकसान न हो। हमने निरीक्षण के लिए टीमों का गठन किया है। दो टीम पहले भी काम कर रही थी और अब एक टीम और बनाई है जो सीधे ही यहाँ से रेड करेगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वह जानकारी नहीं देशो कि उनको कहीं पर रेड करना है और कहाँ पर नहीं करना। अध्यक्ष महोदय, राह दात भी आई थी कि सैम्पलिंग कम होती है। पिछले साल हमने 2596 सैम्पल लिये जिनमे से 77 ऐडल्टेटिड पाये गये। इस साल हमने 3075 सैम्पल लिये जिसमें से 113 ऐडल्हेकि पाये गये। हमने इसके बारे में भारत सरकार से भी बात की है और हमें विश्वास मिला हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि पार्लियामैंट में इस सैशन में शायद कोई अमैंडमैंट आ जाये कि जो ऐडल्ट्रैशन करता है, उस पर सजा बढ़ाई जाये या कोई और सख्त तरीके हों जिससे फर्टिलाइजर आदि में ऐडल्ट्रैशन न हो। एक भाई ने कहा कि फर्टिलाईजर मिला नहीं। अध्यक्ष महोदय, यह बात बिलकुल गलत है। हमने 400 करोड़ रुपये पहले ही जमा करता दिये ये और सारा फर्टिलाईजर डी०ए०वी० फार्म से आया है। हमने सारी रकम पहले ही जमा करवा दी थी। दूसरे किसी सूबे को मिला हो या नहीं लेकिन यहाँ फर्टिलाईजर की कमी नहीं आई। एक बात जो कही गई उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हौर्टीकल्चर या ऐग्रीकल्चर डिपार्टमैंट कोई पाइप नहीं खरीदता हैं पाइप किसान खुद खरीदती है। हम

किसान से एक बात जरूर कहते हैं कि पाइप पर आई०एस०आई० की मोहर हो और वे गइप सरकार की हाई कवर कमेटी से पास हों वह माल अगर कोई खरीदे और हमें रसीद दे दे तो जो भी 25 परसैंट या 50 परसैंट की छूट है वह हम दे देंगे और कही–कही पर तो 100 परसैंट तक छूट हम दे देते हैं।

श्री अध्यक्षः गवर्नर एड्रैस पर डॉ० सीता राम जी ने बोलना था उनकी पर्ची आई हुई है। श्री हर्ष कुमार जी ने बोलना था, श्री रमेश गुप्ता, श्री आनन्द सिंह डली जी ने बोलना था और बरवाला से सदस्य श्री रणधीर सिंह जी की भी पर्ची आई हुइ है। क्योंकि टाईम कम है इसलिए मैं रिक्वैस्ट करूंगा कि यदि हाउस की परमिशन हो तौ ये लने बजट पर बोल लेंगे।

आवाजें: ठीक हैं जी।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the Hon' ble Chief Minister will give the reply.

मुख्यमंत्री (श्री भुपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान् सदन में हरियाणा के महामहिम राज्यपाल डॉ० ए०आर० किदवई द्वारा 6 फरवरी, 2009 को जो अभिभाषण दिया गया है उसके लिए उनका हार्दिक धन्यवाद करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। स्पीकर सर, हमारी सरकार को बने तकरीबन चार साल हो गये हैं। यह जो वर्ष 2009 है हमारी सरकार ने इस साल को किसान मजदूर वर्ष के रूप में मनाने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। स्पीकर सर, कांग्रेस पार्टी जब वर्ष 2000 में चुनाव लड़ी उस समय

हमने जो चुनावी घोषणा–पत्र था और लोगों के सामने जो वायदे किये थे, मैं यह गर्व के साथ यह कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने उस घोषणा पत्र में जो जो भी वायदे किये हो वे सारे पूरे किये हैं और उन वायदो मे और आगे वह कर हमने अनेकों कार्य किये हैं जो सबके सामने हैं। (इस समय मेजें थपथपाई गई) स्पीकर सर, शायद यह पहली सरकार होगी जिसने अपने घोषणा पत्र में जितने भी वायदे किये थे वे सारे पूरे किये हैं। स्पीकर सर, जो वायदे हमने किये थे उनसे से एक वायदा एस०जी०पी०सी० के बारे में किया था, वह अभी पूरा करना बाकी हे, उसके लिए अभी चट्ठा साहब की का इन्तजार है। बाकी सभी वायदे हम पूरे कर चुके हैं। स्पीकर सर, मैंने और मेरे कांग्रेस के साथियों ने और हरियाणा के आम आदमी ने वर्ष 2005 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो एक सपना देखा था कि हरियाणा प्रदेश को पूरे देश में नम्बर एक बनाना है। हर पहलू से आगे चलना है और प्रदेश का विकास करना है। मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी है कि बहुत सारी चीजों में हरियाणा नम्बर एक पर है और हमने कई मील के पत्थर स्थापित किये हैं। (इस पर मेजें थपथपाई गई) स्पीकर सर, प्रति व्यक्ति निवेश में हमारा हरियाणा प्रदेश पांच साल पहले चौदहवें नम्बर पर था जो कि अब पूरे देश में नम्बर एक पर है। (इस समय मेजें थपथपाई गई) वित्तीय प्रबन्धन में हरियाणा प्रदेश देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदेशों में से एक है। स्पीकर सर, आज हरियाणा में प्रतिव्यक्ति आय 67891 रुपये हे जो कि गोवा के बाद पूरे देश में सबसे अधिक है। गोवा प्रतिव्यक्ति आय में हम से आगे

है क्योंकि गोवा एक छोटा प्रदेश है और वहां पर टूरिज्म की आमदनी है। स्पीकर सर, दूध के उत्पादन में हरियाणा देश में नम्बर एक पर है (इस समय मेजें थपथपाई गहे गेहूं की उत्पाक्ता में हम पंजाब से भी पीछे थे आज गेहूं की उत्पादकता में भी हरियाणा प्रदेश देश में नम्बर एक पर है। (इस समय मेजें थपथपाई गई) स्पीकर सर, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार आने से पहले हमारे सामने बैठे भाइयों की सरकार थी। वर्ष 2004–06 में तत्कालीन सरकार ने जो बजट दिया था वह मात्र 2305 करोड़ रुपये का प्लान्ड बजट दिया था और उसमें कुल साधन 2108 करोड़ रुपये के जुटा पाए। जितना बजट इन्होंने दिया था वह भी पूरा नहीं कर पाए। स्पीकर सर, सभी को यह बात जानकर खुशी होगी कि वर्ष 2009–10 में हम जो बजट पेश करने जा रहे हैं वह करीब दस हजार करोड़ रुपये का है। (इस समय भेजें थपथपाई गई) इसका मतलब यह है कि 500 प्रतिशत की बढ़ौत्तरी हमने बजट में की है जो अपने आप में एक रिकार्ड है और यह दर्शाता है कि हमारा प्रदेश कितनो तेजी से प्रगति कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमने अपनी सरकार को वड़ी परदर्शिता से और स्वच्छता से चलाया है। हमारे समने जो बैठे हुए हैं, मैं उन पर कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहता हूँ। हम किसी ढोंग या नाच का सहारा नहीं लेते हैं जिस तरह से हमारे विपक्ष के साथी लेते हैंय ये जब भी इलैक्शन लड़ते हैं तो कभी कर्जे माफी के वायदे करते हैं, कभी बिजली के बिल माफी के वायदे करते हैं, कभी पानी देने के वायदे करते हैं और सदन में आने के बाद कुछ नहीं

करते हैं अध्यक्ष महोदय, ये जो चेहरे पर चेहरा लगाकर बात करते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि–

'हम तो दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है,

जिस तरफ भी चल देंगे, रास्ता बन जाएगा। '

यह बात इनको समझ जानी चाहिए। (विघन) मैं हरियाणा सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करूं तो केन्द्र में जो यू०पी०ए० की सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में चल रही है और श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में यू०पी०ए० की सरकार बनी हुई है, उस सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है जो कि विघ्न में कहीं पर भी नहीं लिया गया होगा। केन्द्र को सरकार ने 71 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा के किसानों के कर्जे माफ किए हैं। यह एक ऐतिहासिक फैसला है। हमारे से पहले भी कर्जे माफ किए गए हैं लेकिन हमारे इस रिकार्ड को कोई चौलेंज नहीं कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, इस माफी से हिन्दुस्तान के 4 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ हुआ है और हरियाणा में 7 लाख 15 हजार किसानों के परिवारों को 21 सौ 36 करोड़ रुपये का लाभ पहुंचा है। जैसे मैंने कहा है कि पहले भी कर्जे माफ हुए हैं लेकिन उनका ढिंढौरा ज्यादा पीटा जाता था कि हमने इतने कर्जे माफ कर दिए, इतने लोगों को उससे फायदा पहुंचा है। अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी आज स्वर्ग में हैं। हम उनका मान–सम्मान करते हैं। उनकी पार्टी ने सत्ता में

आने से पहले वायदा किया था कि हम कर्जे माफ करेंगे लेकिन सत्ता में आने के बाद, उनकी सरकार बनने के बाद उन्होंने जो किसानों का कर्जा माफ किया था वह 33.64 करोड़ रुपए था। अध्यक्ष महोदय, कहां 33.64 करोड़ रुपए और कहां 71 हजार करोड़ रुपए। हमने तो 21 सौ 36 करोड़ रुपए सिर्फ हरियाणा के किसानों के ही माफ हैं। (विच)

डॉ० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि उस वक्त महंगाई की क्या दर थी और आज क्या है। वह भी आप बता दें। श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः यह सब कौ पता हे।

डॉ० सीता रामः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में यह कहना चाहता हूँ कि शुरुआत करना मुस्किल होती है जो हमने की थी। बुजुर्गो को पेंशन देने की भी हमने ही शुरूआत की थी।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, आपने इन लोगों को पहले भी बोलने का मौका दिया था और आगे भी देंगे। (विघ्न) अब इनको बेठकर मेरी बान सुननी– चाहिए। जब ये बोल रहे थे तो हम इनकी तरह बीच में टीका–टिप्पणी नही कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, 1600 करोड़ रुपये बिजली के बिलों के हमारी सरकार के आने के बाद हमने माफ किए टेप। हमारे इस फैसले से 6 लाख 19 हजार 137 उपभोक्ताओं नै लाभ उठाया है। इसके

साथ ही जो सहकारी बैंकों से फसलों के लिए ऋण की आज की दर 11 प्रतिशत थी उसको घटाकर हम ते 7 प्रतिशत कर दिया है। यह हमारी कटिबद्धता है कि हम किसान हितैषी हैं और मैं स्वयं किसान का बेटा हूं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही हमारी सहकारी समितियों में एक काला कानून था कि अगर किसान या दस्तकार उन समितियों से पाप हजार रुपये का कर्जा ले लेता था और उसको लौटा नहीं पाता था तो उसको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता था। हमने उस कानून को खत्म कर दिया है। (इस समय मेजे थपथपाई गईं।) अध्यक्ष महोदय, एक और काला कानून है कि कर्जे के बदले में जमीन की नीलामी की जाती है। इस बारे में मैं पूरे सदन के सामने कहना चाहता हूँ कि मैंने एक फैसला किया है कि वित्तमंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा और हम इस काले कन्न को खत्म करेंगे। इसके साथ ही हमने पूरे प्रदेश में अगर कहीं पर जमीन ऐक्वायर की जाती हे तो उसका मिनिमम फलोर प्राईस 8 लाख रुपए प्रति एकड़ दिया है, इससे ख्य रेट नहीं दिया जाएगा। लेकिन यह जो सहकारी बैंक हैं या लैण्ड डिवैलामैंट बैंक हैं जब कोई किसान कर्ज लेने जाता हैं तो तीन एकड़ जमीन उसकी मोर्टगज की जाती है। अगर किसान ट्रैक्टर लेने जाता है तो ट्रैक्टर की कीमत होगी चार या पांच लाख रुपये, लेकिन उसके लिए तीन एकड़ जमीन उसको गिरवी रखनी पड़ती है। अष्यक्ष महोदय, हमने यह फैसला किया है क्योंकि 8 लाख रुपये फ्लोर रेट फिक्स है अब 8 लाख रुपये तक अगर कोई किसान ट्रैक्टर या मशीनरी के लिए सहकारी

बैंकों से कर्ज लेगा तो उसकी एक एकड़ से ज्यादा जमीन मौर्टगेज नहीं की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक और काला कानून है जब किसान अपना कर्जा नही दे पाता तो उसकी जमीन की नीलामी की जाती है। मैं मानता हूं क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ कि जितना कर्ज लेते हैं वह देना चाहिए, उसकी पाई–पाई चुकानी चाहिए। उसके तरीके भी हैं। लेकिन जो अब तक किसान की जमीन की नीलामी की जाती थी तो उसके कारण वह अपनी जमीन से वंचित हो जाता था। जो हम कमेटी गठित कर रहे हैं वह कमेटी ऐसा उपाय बताएगी कि जो किसान अपना कर्ज नहीं दे पा रहे हैं तो उसकी जमीन की नीलामी के बजाए जो चकोता है उसके 50 परसेंट से या किसी दूसरे तरीके का रास्ता रिकवरी का अख्तियार किया जाए तो वह किस तरह से किया जाए। हम चाहते हैं कि किसी भी किसान की जमीन को नीलामी न हो, इसलिए ऐसा कानून हम बनाने जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, भूमि की जहां तक वात है आप सबको मालूम है कि एक नई नायाब किस्म की हमने स्कीम दी हे। हमारी सरकार आने से पहले क्या था कि 50 हजार रुपये से लेकर दो. लाख रुपये तक किसान की जमीन एक्वायर की जाती थी। उस समय किसान बगैर जमीन के हो जाते थे। लेकिन हमने सरकार में आते ही घूरे प्रदेश में फ्लोर रेट जमीन के फिक्स किए हैं। अध्यक्ष महोदय एक स्कीम जिसको के०एम०पी० भी कहते हैं, वह 135 किलोमीटर लम्बी रोड है। यह स्कीम हमारी सरकार के बनने से पहल की है इस स्कीम के लिए किसानों की जमीन ऐक्वायर करने का जो कुल कम्पनसेशन उस

समय आका गया था वह 160 या 167 करोड रुपये के करीब था। लेकिन जब हमने अपनी सरकार आने के बाद जमीन का फ्लोर रेट फिक्स किया तो उतनी ही जमीन का रेट कहां के किसानों का 660 करोड़ रुपये से ज्यादा मिला है। उस उमरा एक किसा से जो किसान थे उनके साथ जो लूट हो रही थी उसको हमने बंद किया। हमें पता है कि किसान की जमीन ऐक्वायर भी करनी पड़ती है लेकिन हमने यह फैसला किया कि जिस किसी किसान की जमीन सडक के लिए, नहरों कै. लिए या किसी और दूसरे काम के ऐक्यायर करनी भी पडती है ताकि प्रदेश का विकास हो तो हरियाणा प्रदेश पहला प्रदेश है जिसने जमीन में किरमान की हिस्सेदारी रखी है। अगर किसी किसान की जमीन ऐक्वायर की जाएगी तो अब उसके लिए हमने रायल्टी देने का प्रावधान भी रखा है। जड़ जिस किसी किसान की जमीन सरकारी काम के लिए, सड़क के लिए, नहर के लिए या दूसरे किसी काम के लिए ऐक्वायर की जाएगी तो हम उसको उसकी जमीन का कम्पनसेशन का पूरा अमाउंट' तो देंगे ही, साथ ही साथ उसको रायल्टी भी 16 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष 33 वर्ष तक देंगे और 500 रुपये का हर वर्ष इसमें इजाफा होकर भी किसान को मिलेगा। इसी प्रकार से जहां तक एस०ई०जैड० के लिए जमीन एक्वायर करने की बात है, हमने एस०ई०जैड० के लिए जमीन एक्वायर करके नही दी है। परन्तु फिर भी हमने फैसला किया है कि वादे किसान की कोई जमीन एस०ई०जैड० के लिए ऐक्वायर करनी भी पड़ती है तो उस किसान को कम्पनसेशन देने के साथ–साथ 30 हजार रुपये प्रति

वर्ष प्रति एकड़ 33 वर्षों तक उसकी रायल्टी की सांझेदारी रखी जाएगी और एक हजार रुपये उसमें प्रति वर्ष इजाफा भी किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश है जिसने यह फैसला किया है। इससे लोगों को काफी लाभ मिलेगा। यहां पर मेरे एक साथी धान के मूल्य के बारे में, गेहूं के मूल्य के बारे बात कर रहे थे और मंडियों में गेहूँ के बारे में बात कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, जहां तक– गेहूँ के मूल्य और धान के मूल्य की बात का सवाल है, वह तो आकड़े बताते हें कि हमारी सरकार आने के बाद केन्द्र में यू०पी०ए० की सरकार बनने के बाद इसमें कितना इजाफा हुआ. है। जहां तक सवाल है मेरा और मेरी पार्टी का, मैं भी स्वयं एक किसान का बेटा हूँ और एक ऐसे व्यक्ति का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है जो हिन्दुस्तान में ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने 1948 में सविधान सभा में एम०एस०पी० के बारे में बात की थी। अध्यक्ष महोदय, मेरे पिता स्वर्गीय रणबीर सिंह जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि किसान को एम०एस०पी० मिलना चाहिए। हमने उनका सपना पूरा करना है। उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि किसानों को उनकी फसल के उचित भाव मिलें और उसके लिए हम सदैव प्रयासरत रहे हैं कि उनकी फसल समय पर बिके। अध्यक्ष महोदय, 27 मई, 2004 को केन्द्र में यू०पी०ए० की सरकार श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में बनी। उस समय गेहूँ का भाव 630 रुपये प्रति क्विंटल था और आज वह बढकर 1080 रुपये किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि चार साल की अवधि में 450 रुपये गेहूँ का रेट बढ़ा है। इस

प्रकार वर्ष 2004 के मुकाबले में 72 परसैंट गेहूं की एम०एस०पी० बड़ी है। जब इनेलो–भाजपा पार्टी के गठबंधन की केन्द्र में सरकार चल रही थी उस समय 1999 से लेकर 2003–04 के बीच में किसानों की फसल का कितना भाव बढ़ा था यह मैं बताना चाहूँगा कि जब इनकी सरकार 1999 में बनी थी उस समय 580 रुपये रेट था और सरकार जब गई तब 630 रुपये प्रति क्विंटल रेट था। इसी प्रकार से ग्रेड–ए धान का रेट देखें। धान में उक्त रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ौतरी हुई, वर्ष 2003–04 में 580 से बढ़कर 2008–09 में 930 रुपये प्रति क्विंटल रेट किया है। इस प्रकार यह रेट भी कोई कम नहीं बग। इस प्रकार सामान्य धान के रेट में भी 350 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ौतरी बट्टी गई।

डा० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे है कि धान पर समर्थन मूल्य आपकी सरकार ने बढ़ाया। चाहे बाजरे की फसल है, चाहे धान की फसल है। खरीद तो एम०एस०पी० पर नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्षः यह कोई प्वायंट ऑफ आर्डर नहीं है। Please do not interrupt. सदन के नेता जबाव दे रहे हैं। Please maintain the decorum of the House.

श्री भुपेन्द्र सिहं हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, या तो ये यह कहें कि यह भाव नहीं था तब तो प्वायंट ऑफ ऑर्डर की बात है। मैं तथ्य रख रहा हूँ। जहां तक आप उस रेट पर नहीं खरीदने की बात कह रहे हैं तो मेरे पास किसी एक भी किसान भाई को ले

आयें और वह कहे कि मेरा गेहूं इस रेट से कम पर बिका है तो मैं देने के लिए तैयार हूं। (शोर एवं व्यवधान) कम में बिकने का तो रायपाल ही नहीं है। आप 54–54 मिनट बोलते रहे और हम सुनते रहे, आप भी सुनने के लिए तैयार रहें। मैं तो असलियत बता रहा हूं आपको सुननी चाहिए। जो अच्छी बातें हैँ उनको ऐप्रीशिएट भी करना चाहिए। आप यह बताएं कि आप किसान के हितैषी हैं या विरोधी हैं। हितैषी हैं तो बात सुनें। अगर आपको किसान हित की बात. पसंद नहीं आती है तो दूसरी बात है। (विघन) हमने धान के भाव में 64 प्रतिशत की बढौतरी भी है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि बी०जे०पी० और लोकदल की सरकार के समय में जब केन्द्र में एन०डी०ए० की सरकार थी उत समय ए–ग्रेड धान का रेट 40 रुपये प्रति क्विंटल के से बढ़ाया गया था। वर्ष 1999–2000 में 520 रुपये से बढाकर 500 रुपये प्रति क्विंटल रेट किया गया था और गेहूं का 480 से बढ़ाकर 350 रुपये प्रति क्विंटल किया गया था और यह भी 40 रुपये बढ़ा था। हमने सरकार आने के बाद 350 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ौतरी दी है। (इत समय मेजें थपथपाई गई।) पूसा– 1121 नामक किस्म के बारे में जिसे पूरा देश जानता है, प्रदेश का किसान जानता है। धान जो पैदा करता है वह जानता है। पूसा 1121 वैरायटी को किसने शामिल करवाया है वह इस साल शामिल किया गया है। इनकी सरकार के समय में पांच–पांच– साल हरियाणा के किसान दर–दर ठोकरें खाते रहे लेकिन किसान की कहीं पर सुनवाई नही की गई। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर गन्ने का उत्पादन होता

है। आज मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि आज पूरे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा गन्ने का भाव हरियाणा सरकार दे रही है। वर्ष 2004–2005 में 117 रुपये प्रति क्विंटल था आज 170 रुपये प्रति क्विंटल हे। मेरे पास इसकी डिटेल है। यह भाव आज सबसे ज्यादा है। आज मैं सदन में यह घोषणा करता हूँ कि जो अगेती, मध्यम और पछेती तीनों फसलें गन्ने की हैं आज जिनका भाव क्रमशः 170/–, 165/– और 160/– रुपये हैं अगले साल उन सभी वैरायटीज के भाव में 16 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से और इजाफा कर देंगे। इसी प्रकार से बाजरे की फसल का हमारी सरकार के कार्यकाल में 325 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है, जौं में 140 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है, चने में 305 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है, कपास में 1040 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है और सरसों में 120 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है। अगर पिल्ली सरकार का रिकार्ड देखें तो कमी पांच–पांच रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य बढ़ाया गया कमी एक या दो रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य बढाया गया। (शोर एवं व्यवधान) माननीय इन्दौरा जी मेरे साथ पार्लियामैंट में सांसद रहे हैं। जब ये चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे थे तो हाउस को बहुत अच्छी तरह से कण्डक्ट कर रहे थे। दूसरे मैम्बर्ज को सीख दे रहे थे कि बीच में न बोलें, सुनो और अपनी सीट पर जाकर बोलो। मैं अपर्ना सीट पर से बोल रहा हूँ।

श्री अध्यक्षः डॉक्टर साहब, रनिंग कमैंट्री न करें। आप बजट पर बोल लेना। अब सदन के नेता बोल रहे हैं इसलिए बीच में न बोलें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, आज किसी माननीय सदस्य ने चर्चा की कि हमारे प्रदेश में कहीं–कहीं पर ओलावृष्टि हुई है। यह बात मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। हमने पहले से ही आदेश दे दिया था कि उस इलाके की स्पेशल गिरदावरी की जायेगी और उन किसानों को पूरा मुआवजा देंगे। माननीय साथियों को मालूम होना चाहिए कि वर्ष 2004–2005 में किसानों को उनकी फसल के नुकसान का कितना मुआवजा दिया गया था उस समय वर्ष 2004–2005 गे 26 से 50 प्रतिशत तक ही फसल के नुकसान के लिए एक हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया गया। लेकिन हमारी सरकार ने वर्ष 2006–07 में 26 से 50 प्रतिशत तक के फसल की नुकसान के लिए तीन हजार रुपये प्रति एक्स के हिसाब से दिया है। उस समय की सरकार ने वर्ष 2004–2005 में 60 में से 75 प्रतिशत तक की फसल के नुकसान के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया था जबकि हमारी सरकार ने वर्ष 2006–2007 में 50 से 75 प्रतिशत तक की फसल के नुकसान के लिए चार हजार रुपये प्रति एकड के हिसाब से दिया है और वर्ष 2006–2007 में जो 75 प्रतिशत से फालतू फसल का खराबा हुआ है उसके लिए हमने 5 हजार रुपये प्रति एकड का मुआवजा दिया है। यह अपने आप में पूरे हिन्दुस्तान में

सबसे ज्यादा है। हमारे प्रदेश से किसी प्रदेश का ज्यादा नहीं है। चाहे आप पड़ोस में पंजाब से पता कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष में था मुझे याद है कि इनके समय में कभी चार–चार आन्ने किसानों को दिया गया इससे ज्यादा शर्म की क्या बात है। यही असलियत है रिकार्ड मंगा कर देख सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान) यह अखबार में खबर आई थी कि किसी को 4 आन्ने मिले हैं और किसी को एक रुपया मिला है। ये तो न के बराबर कन्पनसेशन देते थे।

डॉ० सीतारामः अध्यक्ष महोदय, हिस्सेदारी अगर आज भी हो जाए तो भी उतना ही कम्पनसेशन मिलेगा।

श्री अध्यक्षः सीताराम जी, अब बहुत ज्यादा मुआवजा मिला हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, जहां तक सिंचाई का सवाल है। हमने पहले से अपने घोषणा पत्र में भी यह कहा था और आज थी चर्चा हुई कि जितना पानी उपलब्ध है उसके न्यायोचित बंटवारे के लिए हमारी सरकार ने कदम उठाए हैं। हांसी बुटाना लिंक नहर जिसका 100 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और इस पर 387 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इससे 2000 क्यूसिक पानी हम आखिरो छोर तक ले जाएंगें। आपको यह बात नापसंद हो तो न सही, आपने अपोज करना है तो करो लेकिन यह नहर बनेगी और पानी भी जाएगा। सी०डब्ल्यू०सी० ने भी रिपोर्ट हमारे

हक में दे रखी है। अध्यक्ष महोदय, शाहबाद में दादुर नलवी नहर योजना के बारे में जब से हरियाणा बना है हर असैम्बली में चर्चा हुई है लेकिन दादुपुर नलवी योजना का कभी किसी सरकार ने निर्माण नहीं करवाया बल्कि यह योजना केवल कागजों में ही रही। इसका कार्य हमने 267 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किया है जिसका 60 प्रतिशत अर्थवर्क पूरा हो चुका हँ और 50 परसैंट स्ट्रक्चर पूरा हो चुका है। इसका पहला फेज जून, 2009 में पूरा कर दिया जाएगा। डॉ० सीता राम जी, डा० इन्दौरा जी, ओटू झील का कितने दिनों से कितना शोर था, इस पर 70 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे जिसमें से 17 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इससे 5000 एकड़ जमीन को लाभ होगा। वाटर सचाई मैं 322 करोड़ रुपये की हम एक नहर खोद रहे हैं। एस०वाई०एल० की लड़ाई हम ही लड रहे हैं और अपने हक का पानी ले कर रहेगे। कौशल्या डैम हम बना रहे हैं और सिचाई के पूरे साधनों का इंतजाम हम कर रहे हैं। जो वाटर बौडीज हैं चाहे ओटू है चाहे भिंडावास है और चाहे बीबीपुर है और जितनी भी अच्छी वाटर बौडीज हो सकती हैं उनका पूरा कार्य कर रहे हैं। आने वाला समय ऐसा है कि ग्लेशियर खत्म हो रहे हैं और 20 साल के बाद या 25 साल के बाद पानी की भारी किल्लत आ सकती है। वाटर बोडीज बनेंगी तो बारिश के मौसम में पानी इकट्ठा रहेगा ताकि सबको लाभ पहुंचे। वाटर टेबल०पर पहुंचे। चाहे कितना भी खर्च हो हनात विजन है वाटर बौडीज को हम तैयार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, बिजली के बारे में हमारे साथी कहते हैं कि बिजली एक

घंटा आती है या दो घंटे आती है। मैं मोटे तौर पर बताता हूँ कि 2004–05 में 579 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन थी जबकि 2008–09 में 31 दिसम्बर तक 748 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन हम देंगे। इसी प्रकार इन्होंने 5 सालों के कार्यकाल में कोई प्लांट नहीं लगाया। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा को बने हुए 40 साल से ज्यादा हो गए हैं। 40 सालों में हरियाणा में बिजली का उत्पादन 1587 मेगावाट था जबकि हमने फैसला किया है कि हम 5000 मेगावाट बिजली का उत्पादन और करेंगे।

डॉ० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्यायंट ऑफ आर्डर है। मुख्यमंत्री महोदय हर स्टेज पर कहते थे कि 3 साल में हरियाणा प्रदेश को पूरी बिजली देंगे लेकिन इनका 4 साल से०पर का कार्यकाल हो गया है लेकिन पूरी बिजली नहीं जाती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भुपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, जो मैं कहता था मैंने वह करके दिखाया है। (शोर एव व्यवधान) सारे प्लांट चालू हो चुके हैं। मैं एकएक प्लांट के बारे में बता रहा हूं। जो वायदा हमने किया था वह हमने निभाया है। एक प्लांट को चालू करने में 58 महीनों से ज्यादा का समय लगता है। अध्यक्ष महोदय, पिल्ली चौटाला सरकार के 5 साल मैं बिजली पर कुल खर्च 4095 करोड़ था। पिछले चार वर्षो के दौरान मौजूदा सरकार द्वारा इस मद पर 9519.14 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं और 11वीं पंच वर्षीय योजना में डस मद पर 25,630 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे

क्योंकि हमारी सरकार निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक बिजली का उत्पादन करने के लिए प्रतिबद्ध, है। अध्यक्ष महोदय, यमुनानगर में जिस पावर प्लांट से 600 मैगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो चुका है उस पावर खाट का शिलान्यास हमने किया था। अध्यक्ष महोदय, इस पावर प्लांट के सम्मपूर्ण निर्माण पर लगभग 2400 करोड़ रुपये की लागत आयेगा। इसी प्रकार से गांव खेदड हिसार में राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट पर 3775 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। इस पावर प्लाट का 57 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और उस पर अब तक 1393 करोड खर्च हो चुके हैं और वर्ष 2009 के अन्दर यह पावन खाट बिजली का उत्पादन हरू कर देगा। इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट, झाडली जिसकी उत्पादन क्षमता 1500 मैगावाट है और लागत 7892 करोड़ रुपये हैं। इस पावर प्लांट का कार्य भी बड़े जोर–शोर से चालू है। इसी प्रकार से महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट जिसकी उत्पादन क्षमता 1320 मैगावाट है, का निर्माण क्रार्य भी बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। इसके अलावा जो नॉन कंनवैंशनल ऐनर्जी है हमने उससे 706 मैगावाट बिजली के उत्पादन के लिएय समझौता किया है चा हे वह वायो –मास से हो या अन्य प्रकार से अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के साथियों को यह भी बताना चाहूंगा कि अगर हमें गैंस मिली तो हम गैस से भी बिजली बनाने के लिए फरीदाबाद और झज्जर में गैस पर आधारित पावर सैट लगायेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से चण्डीगढ़ हवाई अड्डे का बार–बार इश्यू आया कि किस प्रकार से चण्डीगढ़ हवाई अड्डा को हाईजैक किया जा रहा था। हमने

समय पर उचित कार्यवाहा करते हुए हरियाणा कै। मांग को उठाया क्योंकि चण्डीगढ़ हरियाणा की राजधानी हैं और उसमें हरियाणा का भो बराबर का हिस्सा है। चण्डीगढ़ हवाई अड्डे में भारत सरकार का छ 1 प्रतिशत हिस्सा है, हरियाणा और पंजाब का क्रमशः 24.5—24.5 प्रतिशत हिस्सा है। अध्यक्ष महोदय यइ एक कमर्शियल प्रोजैक्ट है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि कुछ लोग इस बारे में इस सदन और प्रदेश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मूर्रे सदन 'और प्रदेश की जनता को बताना चाहूंगा कि इससे जो भी आमदनी होगी उसमें हरियाणा सरकार को अपना पूरा हिस्सा मिलेगा। मैं यह बात ऑन दी फ्लोर आफ दी हाउस कह रहा हूँ कि इस प्रोजैक्ट से पूरे हरियाणा प्रदेश को पूरा लाभ होगा। अध्यक्ष महोदय, चण्डीगढ हरियाणा की राजधानी है और चण्डीगढ़ के हिस्से का एयरपोर्ट किसी दूसरे प्रदेश के किसी शहर में नहीं बन सकता। इस बात का श्रेय विपक्ष के साथियों को हमारी सरकार कों देना चाहिए कि हमने अपने प्रयासों से चण्डीगढ़ एयरपोर्ट मैं हरियाणा को उसका वाजिब हक दिलवाया है। अध्यक्ष महोदय इसी प्रकार से हमारी सरकार ने गुड़गांव में 581 करोड़ रुपये की लागत से मैट्रो सर्विस के विस्तार की योजना तैयार की है जो कि जनवरी, 2010 तक पूरी हो जायेगी। इसके साथ—साथ फरीदाबाद शहर तक मैट्रो रेल सेवा पहुंचाने के लिए भी मंजूरी दे दी गई है और बहादुरगढ़ तक मैट्रो रेल सेवा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार प्रयासरत है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही हमारी सरकार ने सड्कों और पुलों के निर्माण के लिए बहुत ज्यादा काम

किया है। पिल्ली सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना पर 100 करोड़ रुपये खर्च किये और हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना कै तहत 1102.51 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। इसके अलावा हमारी सरकार ने 28 नवम्बर, 2007 को 3 हजार करोड़ रुपये के राजीव गांधी ब्रिजिज एण्ड रोड्ज इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवैल्पमैंट प्रोग्राम की शुरुआत भी की हैं। अध्यक्ष महोदय, जब हमारी सरकार धनी तब हरियाणा प्रदेश को बने 40 साल पूरे हो चुके थे। इन 40 सालों में कुल 16 आर०ओ०बीज० का निर्माण किया गया और हमारी सरकार के पिछले तीन साल के कार्यकाल के दौरान 9 आर०ओ०बीज का काम कम्पलीट कर दिया है और इसके साथ–साथ 31 दिसम्बर, 2009 तक हमारी सरकार द्वारा 7 और आर०ओ०बीज० का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा। इस प्रकार से हम इस साल के अंत तक 16 आर०ओ०बीज० का निर्माण कर चुके होंगे। हमारी सरकार ने प्रदेश में बनने वाले 95 अन्य पुलों के लिए 82 करोड़ रुपये की शीशे की सैंक्शन जारी की है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हमारी सरकार के दृढ प्रयासों से दिल्ली–रोहतक हाईवे को 6 मार्गी बनाने का काम भी बड़ी तेजी से चल रहा है और लगभग पूर्ण होने जा रहा है। इसके साथ–साथ पानीपत की एलीवेटिड कॉरीडोर सड़क का काम भी कम्पलीट हो गया है। जो एक बोटल नैक चना हुआ था। दिल्ली और फरीदाबाद के बीच में दिल्ली बदरपुर फ्लाई ओवर के निर्माण कार्य को भी मंजूरी मिल गई है। उसके काम का भी अवार्ड हो गया है इस फ्लाई ओवर का कार्य

भी तेजी के साथ आरम्भ हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की यह प्राथमिक्ता है कि पूरे प्रदेश में इसी प्रकार से चहुमुखी विकास की रफ्तार बनी रहे। जहां तक विकास के लिए जमीन की वात है जमीन तो हमारी सीमित है वह नहीं बढ सकती इसलिए हमारी सरकार इण्डस्ट्री के बल पर प्रदेश के समुचित विकास के लिए प्रयासरत है। हमारी' सरकार चाहती है कि प्रदेश मैं ज्यादा सं ज्यादा इण्डस्ट्री की स्थापना हो ताकि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले खाई बेरोजगारी समाप्त हो। अध्यक्ष महोदय, जब से हरियाणा बना है तब से अब तक 40 साल में हरियाणा में कुल इनवैस्टमैंट 40 हजार करोड़ रुपये का हुआ गा। अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन साल में हरियाणा में 33 हजार करोड़ रुपये का इनवैस्टमैंट हुई है और 90 हजार करोड़ रुपये के नये प्रस्ताव पाईपलाईन में है। (इस समय मेजे थपथपाई हुई इसी प्रकार से हरियाणा से 2007–08 में लगभग 40 हजार करोड़ रुपये का निर्यात हुआ है। रोहतक, फरीदाबाद, खरखौदा व यमुनानगर में 4 नये आई०एम०टी० की स्थापना की गई है। 1900 करोड़ रुपये की लागत से के०एम०पी० एक्सप्रैस हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पानीपत में पेट्रो कैमिकल हब का निर्माण किया जा रहा है जिसमें 35 हजार करोड़ रुपये का निवेश होने की उम्मीद है। अध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि मिनिमम वेजिज देश में हरियाणा में सबसे ज्यादा दिये जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा ने बहुत तरक्की की है। हमने बहुत सी यूनिवर्सिटीज बनाई हैं और भी कई यूनिवर्सिटीज बनाई जा

रही हैं। डिफैंस यूनिवर्सिटी भी आ रही है, सैंट्रल यूनिवर्सिटी भी बन रही है। आई०आई०एम० भी आ रही है और आई०आई०आई०टी० भी आ रही है। केन्द्र से भी शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है और हमने भी बहुत सी स्कीमें शुरू की– हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता लेकिन आप एक बात से अन्दाजा लगा सकते हैं कि शिक्षा की ओर हमारा ध्यान कितना है। वर्ष 2004–06 में जब हमारे से पहली सरकार थी उस समय शिक्षा पर कुल 1622.89 करोड़ रुपये खर्च किया गया था और 2009–10 में शिक्षा का जो हमारा प्रस्तावित खर्च है वह 5812.40 करोड़ रुपये का है। इस प्रकार से साढ़े तीन सौ प्रतिशत का इजाफा हमने शिक्षा के बजट में किया है। उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय हमने हरियाणा में बनाया है।

डा० सुशील इन्दौराः आप सार के –अरे में भी बतायें कि शिक्षा का स्तर कितना गिरा है? (शीर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः इन्दौरा जी, सर तो पहले गिर गया था अब तो शिक्षा के स्तर में लगातार सुधार हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, 8.5 लाख अनुसूचित जाति, पिछडे वर्ग तथा गरीब रेखा सें नीचे के बच्चों को पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक वजीफा योजना शुरू की है जिस पर तकरीबन 28 करोड रुपये सालाना खर्च किये जायेंगे। अनुसूचित जाति के लड़की को पहली से तवी तक 100/– रुपये और लड़कियों को 150/– रुपये मासिक वजीफा दिया जायेगा। 5वी से 8वीं कक्षा तक अनुसूचित जाति के

लडको को 150/– रुपये तथा लड़कियों को 200/– रुपये मासिक वजीफा दिया जायेगा। 9वीं से 12वीं तक के अनुसूचित जाति के लड़कों को 200/– रुपये और लड़कियो को 300/– रुपये मासिक वजीफा देने का हमने फैसला लिया है। इसी प्रकार से गैस्ट टीचर्स के बारे में भी चर्चा हो चुकी है। टीचरों की वैकेंसी हम पूरी कर रहे हैं। इन 4 वर्षों में हमने 30 नई आई०टी०आई० और 107 नये पॉलीटैक्निक की स्थापना की है। जिस समय हमारी सरकार आई तो तकनीकी शिक्षण संस्थानों में कुल 24 हजार सीटें थी और अब इन चार सालों में उनको बढ़ा कर हमने एक लाख 10 हजार कर दिया है ताकि आगे बच्चों को रोजगार मिल सके। (इस समय भेजें थपथपाई गई इसी प्रकार से अनुसूचित जाति व समाज कल्याण पर कितना खर्च हुआ इस बारे में मैं इन्दौरा जी व डॉ० सीता राम जी को बताना चाहता हूँ।

डॉ० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्षः डॉ० इन्दौरा आप प्लीज बैठ जाईये। हाउस चल रहा है सदन के नेता राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जवाब दे रहे हैं। आप बीच में वैसे ही इन्द्रप्ट कर रहे हैं यह कोई तरीका नहीं है। Nothing is to be recorded. (interruptions) मैं आपको बजट पर बोलने का मौका दूंगा और सीता राम जी को भी मौका दूंगा। Please keep silence (interruptions). Please maintain the decorum. (interruption) Please sit down.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय सदन की कुछ मर्यादाएं होती हैं कुछ परम्पराएं होती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह सोचता था कि इन्दौरा साहब पार्लियामैंट में रहे हैं और इनको डैकोरम का पता होगा लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इनको डैकोरम का कोई ज्ञान नहीं है (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, सब को मालूम है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और वहां पर सरकार ने ऐफिडैविट दे रखा है कि हम वही नीति रखना चाहते हैं जो पहले अपना रखी थी। स्पीकर सर, मैं यह बात ऑन दि फ्लोर ओफ दि हाउस कह रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूँ कि अनुसूचित जाति और समाज कल्याण के लिए वर्ष 2004–05 में इनकी सरकार के वक्त में सरकार का कितना बजट था और कितना खर्चा था। 40.94 करोड़ का इनका बजट था आप इसको 41 करोड लगा ले। वर्ष 2008–09 में यह बजट 714.77 करोड़ रुपये छै। उस बजट के कम्पैरिजन मे यह कितने गुणा हो गया और वर्ष 2009–10 में यह बढ़ कर 745.17 करोड़ रुपये हो गया है। आप यह देख लें कि यह कितने गुना हो गया है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग कल्याण के लिए विभाग के बजट में वर्ष 2004–06 में 55.95 करोड़ बजट था और वर्ष 2008–09 में 168.95 करोड़ रुपये बजट है और वर्ष 2009–10 में यह और बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से अनुसूचित जातियों, बी०सी० कैटेगरीज और बी०पी०एल० के परिवारों के लिए जो 100–100 गज के प्लाट्स दे रहे हैं हमने यह एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अनुसूचित जातियों के पहली क्लास से बारहवीं

क्लास तक पढ़ने वाले लड़के लड़कियों को हमने 100 से 400 रुपये तक मासिक वजीफा देने की स्कीम शुरु की है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से इन्दिरा गांधी पेयजल स्कीम में अनुसूचित जातियों के 3 लाख परिवारों को पानी के मुफ्त कनेंक्शन दिये जाएंगे जिसमें दो सौ लिटर की टंकी और एक टूटी भी फ्री दी जाएगी। स्पीकर सर, 31 जनवरी, 2009 तक 5 लाख 13 हजार कनैक्शन्ज हम दे चुके हैं और बाकी के कनैक्शन्ज धी जल्दी ही देने जा रहे हैं। इसी प्रकार से गांवों में अनुसूचित जातियों कै 11000 सफाई कर्मचारियों को लगाने का हमने फैसला किया है। इनमें से काफी लोग लग चुके हैं और बाकी भी जल्दी ही लग जाएगें। 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जातियों की जनसंख्या वाले जो शहरी वार्ड हैं सभी वार्डों को एक–एक करोड़ रुपये का अनुदान देने का हमने फैसला किया है। 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जातिय।, की जनसंख्या वाले गांवों में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति योजना के तहत 50 लाख रुपये की डिवैल्पमैंट ग्रांट देने का कार्य हमने किया। स्पीकर सर, इसी प्रकार से इन्दिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना हमने लागू की जिसमें 15,000 रुपये का कन्यादान देते हैं। 64,557 परिवारों ने इस योजना का लाभ उठाया है। आम आदमी तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का कार्य भी हमने किया है और उसमें नये अस्पताल नई सी०एच०सीज० का निर्माण, 40 नई पी०एच०सीज० का निर्माण, पांच सक–सैंटर्ज का निर्माण, रिवाड़ी, अम्बाला, यमुनानगर में ट्रॉमा केन्द्रों के निर्माण का कार्य जारी है। स्पीकर सर, इसी तरह से

और बहुत सारी स्कीमें हमने लागू की हैं। अध्यक्ष महोदय, आप जब दिल्ली से आते हैं तो आपने देखा होगा कि रोड के साथ कई इण्डस्ट्रियल यूनिट्स लगे हुए हैँ, मैं सोनीपत और करनाल की विशेषतौर से चर्चा करना चाहता हूँ। वैसे तो सारे प्रदेश में बहुत सारी इण्डस्ट्रियल यूनिट्स कार्य कर रही थीं जो कि नान कन्क्रर्मेटरी जोन में थी जिनको गिराने का फैसला हो चुका था लेकिन हमने उन सभी यूनिट्स को चेंज आफ लैंड यूज देने का फैसला किया है। वे आन प्रिसक्राईब्ड फीस देकर इसके लिए परमिशन लेंगे ताकि इन यूनिट्स में जिन लोगों को इम्पलॉयमैंट दे रखी थी, जिन लोगों को रोजगार दे रखा था वह रोजगार कम न हो। अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस सदन में बहुत सारी घोषणाएं करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे हरियाणा में घूमता रहता हूँ और हमारी सरकार ने हर वर्ग के लिए कार्य किया है वह चाहे अनुसूचित जाति हैं, बैकवर्ड हैं, गांव हैं या शहर हैं, व्यापारी हैं या कर्मचारी हैं सबके लिए काम किया है.! जय मैं गांव में जाता था तो मुझे बुजुर्ग मिलते थे, वे कहते थे कि सव का काम कर दिया लेकिन हमारा कुछ नहीं किया। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, हमने पहली अप्रैल से वृद्धों की पैंशन 300 रुपये प्रति माह से बढाकर 500 रुपये प्रति माह कर दी है। (इस उभय मैंजें थपथपाई गई)। (विघन)

Mr. Speaker: Indora Ji, I am sorry to say that this is highly objectionable on your part.

श्री भूपेन्द्र सिंहः मैंने पहले ही कहा था कि बुजुर्गो की पेंशन वाला रोग मै ही काटूंगा। (विघ्न) इन्होंने इलैक्शन से पहले बुजुर्गों की पैंशन 300 रुपये करने की घोषणा कर दी लेकिन दी तो मैने ही। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः डॉक्टर साहब, आप बैठै–बैठे मत बोल,। फैक्ट्स कुछ और ही हैं। (दिव्य) आपने तो सोनीपत की रैली में कहा था कि हम चौधरी देवी लाल के हर जन्मदिन पर बुजुर्गों को पैंशन बढ़ाएगे। (विघन) आप यह बताएं कि यह जो बुजुर्गों की पैंशन बढ़ाई गई है क्या आप इससे खुश हैं या नहीं हैं। (विघन)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, बुजुर्गो की पैंशन स्कीम 1981 –82 मै शुरू हुई थी और उस नक्त 25 या 50 रुपये पैंशन मिलती थी और यह पैंशन 14 हजार 986 बुजुर्गों को मिलती थी। फिर यह पेंशन 60 रुपये प्रति माह हुई, उसके बाद 100 रुपये प्रति माह हुई, अब हमने इसका 500 रुपये प्रति माह किया है। इस बात के लिए आपको खुश होना चाहिए। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इस फैसले से 276 करोड़ रुपए का अतिरिकत भार सरकार खजाने पर पड़ेगा। हम यह पैंशन 11 लाख 55 हजार बुजुर्गो को देंगे। 2004–05 में पेंशन लेने वालों बुजुर्गों की संख्या 9 लाख 94 हजार थी। अध्यक्ष महोदय, पहले चार साल में सर्वे किया जाता था अब हमने फैसला किया है कि हर साल सर्वे करेंगे। (विघ्न) हम अब हर साल सर्वे करके बुजुर्गो को पैंशन देते हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, हम जो बेरोजगारों को भत्ता देते थे उस बारे में हमने

पालिसी बनाई हुई है उसी दमे अनुसार बे–रोजगारी भरत देते हैं। जो बच्चा 12वी पास है और वह विज्ञान नहीं पड़ता था उसको पहले 300 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देते थे अब हम उसको 500 रुपये प्रति माह देंगे। इसी प्रकार स्नातक बेरोजगार युवकों को जिन्होंने विज्ञान विज्ञान नही पढा है उनको 500 रुपये की बजाए 750 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देंगे। इसी तरह से जिस बच्चे ने 12वीं कक्षा विज्ञान सब्जैक्ट के साथ की हुई थी और वह बेरोजगार था उसको 450 रुपए प्रतिमाह दिए जाते थे हमने उस राशि को बढ़ाकर 750 रुपए प्रति माह कर दिया है। इसी प्रकार विझान में स्नातक बेरोजगार युवकों को 750 रुपए प्रति माह की बजाए 1000 रूपए प्रति माह के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता देंगे। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार 12वीं पास सामान्य विज्ञान शिक्षित बेरोजगार युवतियों को पहले 450 रुपए प्रतिमाह बेरोजगार भत्ता दिया जाता था उनको भी हम 900 रुपये प्रतिमाह देंगे। अध्यक्ष महोदय, विज्ञान स्नातक तथा सामान्य स्नातक बेरोजगार महिलाओं को बेरोजगारी भत्ता हम अब तक 750 रुपए प्रति माह देते थे, अब उनको इस एक अप्रैल से डेढ़ हजार रुपये प्रति माह देंगे। इसी प्रकार से विधवावों को हम अब तक 850 रुपये प्रति माह पेंशन देतें थे, अब उनको 550 रुपये प्रति माह पेंशन देंगे। इसी प्रकार जो 70 प्रतिशत तक विकलांग व्यक्ति हैं उनको पहले हम उक्त रुपये प्रति माह देते थे लेकिन अब उनको हम 500 रुपये प्रति माह भत्ता देंगे। इसी तरह से जो 100 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति हैं जिनको अब तक 600 रुपये प्रति माह दिए जाते थे

उनको अब 750 रुपये प्रति माह देंगे। इसी तरह से बेसहारा बच्चों को अव तक हम 100 रुपये देते हें, उनको अब 150 रुपये प्रति माह देंगे। ऐसे हमारे प्रदेश में 73 हजार बच्चे हैं।

डॉ० सीता रामः 150 रुपए क्यों आप उनकी 200 रुपए दें?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः ठीक है, सीता राम जी हम उनको 150 रुपए के बजाए 200 रुपए ही कर देंगे'। आप कंस्ट्रक्टिव सुझाव तो दें हम उनको मानने के लिए तैयार है। अध्यक्ष महोदय मैं भी एक स्वतंत्रंता सेनानी परिवार से हूँ इसलिए मेरे को मालूम है कि एकएक करके स्वतंत्रता सेनानी हमें छोड्कर जा रहे हें। उनके दिसम्बर महीने में हमने 5125 रुपए से बढ़ाकर 5500 रुपए पेंशन की थी लेकिन इसमें चिकित्सा भत्ता 250 रुपये पति माह फिक्स था। ज्यादा उम्र होती है उतनी है। उतनी चिकित्सा की जरूरत होती है इसलिए हमने इनके लिए चिकित्सा भत्ता 250 रुपए से बढ़ाकर 750 रुपए प्रति माह कर दिया है। इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, आप जब सुबह पार्कों में सैर करने के लिए जाते हैं मैं भी सैर करने रोजाना जाता हूँ वहां पर जितने भी रिटायर्ड पेंशनर्ज हैं वे बेचारे भी वहां पर घूमते हैं। वे वहां पर अपने–अपने परिवारों की बात करते है।। वे घूमने के साथ–साथ इस बात की भी चर्चा करते हैं कि यार, जब हम नौकरी में थे तो हमें एल०टी०सी० की सुविधा मिलती थी लेकिन अब नहीं मिलती है। अध्यक्ष महोदय, हमने फैसला किया है कि जिस प्रकार से एल०टी०सी० की सुविधा

राज्य के सरकारी कर्मचारियों को मिलती है उसी प्रकार की सुविधा अब पेंशनर्ज को भी दी जाएगी। इस सुविधा से तीन लाख से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। अध्यक्ष महोदय एक वर्ग ऐसा है जिसको हम आगनवाडी कहते हैं। इसमें जो महिलाएं होती हैं वे बहुत अच्छी तरह से सेवा करती हैं। अध्यक्ष महोदय, आगनवाडी तथा हैल्पर्ज का जो मानदेय है वह हमने एक अप्रैल से बढ़ाने का फैसला किया है। आगनवाडी वर्कर्ज को जो अब तक 500 रुपए दिए जाते हैं उसको बढाकार अब डेढ़ हजार रुपये प्रति माह के हिसाब से कर दिए गए हैं। हैल्पर्ज को अब तक 400 रुपये देते थे लेकिन अब उनको भी 400 रुपये देंगे इसका मतलब यह है कि जितना इनको केन्द्र सरकार देगी उतना ही हम उनको देंगे। (विघन) पूरे देश में आगनवाडी वर्कर्ज को हम सबसे ज्यादा भला देने जा रहे हैं। इसी प्रकार से जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके बारे में भी हमने ध्यान दिया है। जिला परिषद् के प्रधान का मानदेय हमने चार हजार रुपये से बढ़ाकर 6 हजार रुपये प्रति माह कर दिया है। उप–प्रधान को अब तक मानदेय तीन हजार रुपये प्रति माह दिए जाते थे लेकिन अब हमने यह राशि तीन हजार रुपये से बढ़ाकर साढ़े चार हजार रुपये कर दी है। इसी तरह से सदस्य, जिला परिषद् का जो मानदेय पहले एक हजार रुपए प्रति माह होता था, वह अब हमने बढ़ाकर दो हजार रुपये प्रति माह देने का फैसला किया है। इसी प्रकार से प्रधान, पंचायत समिति का मानदेय 3 हजार रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 450 रुपये प्रति माह किया है, सदस्य पंचायत का हअ रुपये प्रति माह से बढ़ाकर एक

हजार रुपये किया है और सरपंच का मानदेय 1 हजार रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये किया है। पंच को 200 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये देंगे। नगर निगम में अध्यक्ष महोदय, मेयर का मानदेय 3 हजार रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 5 हजार रुपये प्रति माह किया है। वरिष्ठ उप मेयर का 2 हजार रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 3 हजार रुपये और उप मेयर का 1500 से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रतिमाह किया है। पार्षद का मानदेय एक हजार रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये और नगर परिषद प्रधान का 2 हजार रुपये से बढ़ाकर 3 हजार रुपये और उप प्रधान का एक हजार रुपये से बढ़ाकर 2 हजार रुपये और पार्षद नगर परिषद का मानदेय एक हजार रुपये से बढ़ाकर पन्द्रह सौ रुपये करने का फैसला किया है। इसी प्रकार नगर पालिका प्रधान का मानदेय 1500 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये, उप प्रधान का मानदेय 1 हजार रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रतिमास और पार्षद नगर पालिका का 500 रुपये से बढ़ाकर 1 हजार रुपये मानदेय देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा जो हमारा एक जरूरी अंग है। कोई व्यक्ति चाहे रात को 12.00 बजे किसी गांव में जाए तो वह सबसे पहले पूछेंगे कि चौकीदार कौन है। चोकीदार सबसे गरीब आदमी है उसका मानदेय पहले भी हमने बढ़ाकर 1 हजार रुपये किया था अब उसका मानदेय एक हजार रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। इसी प्रकार चौकीदार को वार्षिक वर्दी भत्ता 1 हजार रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये देंगे और सीटी, लाठी व बैट्री का 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये वार्षिक देंगे। एक और जरूरी अंग है जो

समाज को व सरकार को जोड्ने का और लोगों की सेवा करने का काम करता है वह हैं नंबरदार। नंबरदारों की बहुत बड़ी फौज है और उनके बगैर काम भी नहीं चल सकता। नंबरदार को मानदेय पहले हम 500 रुपये प्रतिमाह देते थे अब नंबरदारों का मानदेय 500 से बढ़ाकर 750 रुपये प्रति मास कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, गांव में हमारा जो पोटेंशियल हे खेलों में जैसे एशियाड में कर दिया है। कामन वैल्थ में हमारे बच्चे जाते हैं। पिछले दिनों बीजिंग में भी हमोर बच्चे गए थे और बीजिंग गेमों से हमारे यहां के खिलाड़ी पदक भी लेकर आये हैं यह सब सोचकर हमने ग्रामीण स्टेडियम बनाने का फैसला किया था उनमें से बहुत सारे ग्रामीण स्टेडियम्ज बन भी गए हैं अब हमने फैसला किया है कि उनमें 1 – 1 कोच और एक स्पोटिंग स्टाफ भी लगाएंगे और जहां पानी उपलब्ध होगा वहां उन स्टेडियप्स में ट्यूबवैल भी लगाकर देंगे ताकि वह ठीक तरीके से मेन्टेन रह सकें। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हम गांवों में गरीब आदमियों के लिए प्लॉट दे रहे हैं। शहरों में भी हम देखते हैं कि गरीब आदमियों और कमजोर वर्गों के लिए रहने की जगह की कमी है उनके लिए घर मुहैया कराने के लिए सरकार ने फैसला किया है। जगाधरी, फरीदाबाद, पलवल, हिसार, सोनीपत और अम्बाला मे जहां जमीन आज के दिन उपलब्ध है वहां लगभग 15 हजार मकान एक साल के अंदर बना कर देंगे वह मकान 16356 मकानों के अतिरिक्त होंगे और तह बहादुरगढ, गुडगांव, हिसार, जींद, कैथल, हिसार, रोहतक और सिरसा में मकान बनाने की प्रकिया जारी है।

13.00 बजे

इसके अतिरिक्त पन्द्रह हजार मकान प्राइवेट सैक्टर के माध्यम से बनाए जाएगें। एक मैं यह जिक्र कर रहा था कि जमीन सिकुड़ती जा रही है, खेती कम होती जा रही है। अब जो किसान गांव में बैठा है उसकी अतिरिक्त आमदनी का एक ही जरिया और रास्ता अब दुग्ध रह गया है। दुग्ध उत्पादन में हरियाणा प्रदेश आज नंबर– 1 पर है लेकिन किसान को दुग्ध का उचित भाव मिले, दुग्ध उत्पादकों को दूध का उचित भाव मिले उसके लिए राज्य के दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए मिल्क सब्सिडी देने का हमने निर्णय लिया है और उसके लिए हम 50 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान कर रहे हैं ताकि दुग्ध के उत्पादकों को उचित लाभ मिले। जहां तक शिक्षा की बात है हमारा पूरा प्रयास रहा है कि शिक्षा में गुणवत्ता हो, चाहे कोई प्रदेश है, चाहे देश है या चाहे कोई वर्ग है दुनिया की दौड़ में आगे वही जायेगा जो शिक्षा में आगे जायेगा। शिक्षा का आधार ऐलीमैंट्री और प्राईमरी ऐजूकेशन से बनता है। आज विश्व एक हो चुका है। इस वास्ते हमने फैसला किया है कि प्राइमरी लैवल की शिक्षा में सुधार लाने हेतु विशेषकर अंग्रेजी पड़ाने के लिए अंग्रेजी अध्यापकों का एक नया कैडर आरम्भ किया जाये। इसके लिए एक हजार अंग्रेजी अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी जिनकी शैक्षणिक योग्यता अंग्रेजी में स्नातक (आनर्ज) या बी०ए० (ऑनर्ज) 50% अंकों सहित होगी। इन अंग्रेजी अध्यापकों की नियुक्ति के बाद इनको छः महीने

का प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। हम इस बात पर चले हैं कि शुरू से ही हमारे बच्चों की शिक्षा का आधार मजबूत हो। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बहुत सारे सदस्यों ने भाग लिया और कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये गये। हम इन सब मुद्दों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके आवश्यक कार्यवाही करेंगे। मेरी सरकार को हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति का आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त है। हरियाणा को सही मायने में नश्वर एक प्रान्त बनाने के लिए मैं इस महान यज्ञ में आहूति देने के लिए इस महान सदन के सभी सदस्यों का समर्थन मांगता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। बहुत–बहुत धन्यवाद।

Mr. Speaker: Question is --

That an address be presented to the Governor in the following terms —

"That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 6th February, 2009 at 2.00 P.M."

(The motion was carried unanimously)

वर्ष 2008–09 के लिए अनुपुरक अनुमान (द्वितीय किस्त) प्रस्तुत करना

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will present the Supplementary Estimates (Second Instalment) for

the year 2008-2009.

Finance Minister (Sh. Birender Singh): Sir, I beg to present the Supplementary Estimates (Second Instalment) for the year 2008-2009.

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now, Shri Udai Bhan, Chairperson,. Committee on Estimates will present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (Second Instalment) for the year 2008-2009.

Shri Udai Bhan (Chairperson Committee on Estimates): Sir, I beg to present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (Second Instalment) for the year 2008-09.

वर्ष 2008–2009 के लिए अनुपूरक अनुमानों की मांगों (द्वितीय किस्त) पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now discussion and voting on Supplementary estimates (Second Instalment) for the year 2008-2009 will take place.

As per the past experience and in order to save the time of the House, the demands (1 to 3, 5 to 15 and 17 to 24) on the order paper will be deemed to have been read and moved together. Hon'ble Members can discuss on any demand but they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise the discussion.

That a Supplementary sum not exceeding Rs.

7,36,39,000;- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 1—Vidhan Sabha.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 89,98,91,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 2-General Administration.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 283,98,80,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 3—Home.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 22,33,02,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 5—Excise & Taxation.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 3,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 6—Finance.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 4,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No.

7—Other Administrative Service.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 94,02,83,000/- for revenue expenditure and Rs. 147,10,88,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 8—Buildings & Roads.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 684,83,95,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 9—Education.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 260,77,53,000/- for revenue expenditure and Rs. 53,03,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 10—Medical & Public Health.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 99,00,52,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 11—Urban Development.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 36,82,51,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 12—Labour & Employment.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 8,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 13—Social Welfare and Rehabilitation.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 30,13,83,000/- for revenue expenditure and Rs. 60,83,95,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 14—Food & Supplies.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 686,49,31,000/- revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 15-Irrigation.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 89,27,66,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 17—Agriculture.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 7,71,64,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 18—Animal Husbandry.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,32,89,000/- for revenue expenditure be granted to the

Governor to defray cnarges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 19—Fisheries.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 15,39,02,000/- for revenue expenditure and Rs. 1,37,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 20—Forests.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 169,33,18,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 21—Community Development.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 9,33,00,000/- for revenue expenditure and Rs. 13,06,11,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 22—Co-operation.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 69,55,82,000/- for revenue expenditure and Rs. 64,60,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 23—Transport.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 26,85,000/- for revenue expenditure and Rs. 9,40,00,000/- for

capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 24—Tourism.

श्री अध्यक्षः इन्दौरा जी, एक तो प्लेटफार्म से घोषणाएं होती हैं, एक घोषणाएं मैनीफैस्टो में होती हैं और एक घोषणाएं आन दि खोर आफ दि हाउस होती हैं, क्या आप इस डिफरैंस को समझते हैं? आपकी तो बोलने की आदत सौ बन गई है जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है।

डॉ० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, मुझे अपने शब्द तो पूरे करने दें। मैं यह कह रहा था कि आपने कहा कि कुछ घोषणाएं प्लेटफार्म से होती हैं और कुछ घोषणाएँ सदन में होल हें।

श्री अध्यक्षः डॉ० साहब, अब खीर हलवा बन गया है क्यों बीच में रोड़ा अटका रहे हो। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, हमारे रोड़े अटकाने से काम अटकते होते तो काम अटक जाते। जब हमारी बात नहीं सुनी जाती तो आप हरियाणा के लोगों को क्या दोगे। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नं० 24 पर बोलना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार पर्यटन में क्या कर रही है। पर्यटन पर मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं कल ही जटायु पर्यटन स्थल में गया। वहां 1200 रुपये प्रति कमरे का किराया था। सुविधाओं

के हिसाब से देखें, कर्मचारियों का व्यवहार देखें तो वह कमरा ठहरने के बिल्कुल लायक नहीं था। मैंने कहा कि मेरा कमरा कैंसिल कर दो।

श्री अध्यक्षः इन्दौरा जी, आप जटायु पर्यटन स्थल में क्या करने गए थे। आप रैडबिशप में जाते, आप एम०एल०ए० होस्टल में जाते। दूसरे मार्किटिंग बोर्ड के अनेक रैस्ट हाउसिज हैं उनमें जाते, आप जटायु पर्यटन स्थल में क्या करने गए थे।

डा० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, एम०एल०ए० होस्टल में मुझे कमरा मिलता नहीं। मेरे पास फ्लैट है। मेरे कुछ गैस्ट आ गए थे। वर्कर्ज को मैंने फ्लैट पर ठहरा दिया तो आदमी कहीं तो ठहरेगा।

श्री अध्यक्षः आप यात्री निवास में चले जाते, पंचायत भवन में चले जाते। चंडीगढ़ के पंचायत भवन में चल जाते।

डॉ० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, मैंने फोन करके पता कर लिया था। कहीं जगह खाली नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, फ्लैट में जगह कम रह गई क्योंकि कल हरियाणा से हमारे कुछ वर्कर्ज हरियाणा विधान सभा का घेराव करने के लिए आए थे। उन लोगों की बात हमारी सरकार तो सुनती नहीं लेकिन हमने तो उनकी बात सुननी है।

श्री अध्यक्षः डा० साहब आपकी पूरी सुनवाई हुई है। चलो अब डिमांड्ज पर बोलो।

डा० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि जब मैंने उनको कमरा कैंसिल करने के लिए कह दिया तो वे कहने लगे नहीं कमरा कैंसिल नहीं कर सकते। बेचारा कोई आदमी कमरा बुक करवा ले उसके तो 1200 रुपये लग गए। हमारा उनसे विवाद हो गया। ऐसे विवाद करवाना तो कांग्रेस पार्टी को आदत है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक परिवहन की बात है तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि गांवों में बसें नहीं जाती ' हमारे मिर्जापुर खेड़ी और महमूदपुरिया गांवों में बसें नहीं जाती। शिक्षा मंत्री जी ने स्कूलों की अपग्रेडेशन की बात की। फतेहपुर मे पिछले 3 सालों से लगातार एक 5वी के स्कूल को 8वीं के स्कूल में अपग्रेडेशन की बात चल रही है लेकिन उसकी अपग्रेडेशन नहीं हुई। इन्होंने न जाने कितने नाम गिना दिए कि हमने इतने स्कूल अपग्रेड कर दिये। इसके अलावा हरियाणा में रानियां का जो रैस्ट हाउस है वहाँ रख–रखाव के लिए कोई आदमी नहीं है। मैंने कई बार कहा है कि रानियां के रैस्ट हाउस में कोई आदमी रख–रखाव के लिए रख दो ताकि कम से कम सफाई हो जाए और उसकी मैंटीनैंस हो जाए। एक एस०डी०एम० आया था और वह ए०सी० उठाकर ले गया। जब मैंने आवाज उठाई तो वह ए०सी० वापिस लेकर आया। सरकार की जो घोषणाएं हैं, हो सकता है कि कुछ घोषणाएं अच्छी भी हो लेकिन उनमें प्रशासनिक अधिकारी जो रोड़ा अटकाए हुए हैं उस विषय में मुझे चिंता है। इम्पलीमैंटैशन ऑफ स्कीम्ज न के बराबर हैं। अध्यक्ष महोदय मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी पेयजल योजना के तहत 200 लीटर पानी

की टंकी एक जगह दो घरों को मुश्किल से मिली है। स्वच्छता अभियान के तहत सिरसा जिले को अभी तक अवार्ड नहीं दिया गया। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Now, the demands will be put to the vote of the House. Demand No. 1 to 3

Mr. Speaker: Question is—

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 7,36,39,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 1—Vidhan Sabha.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 89,98,91,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 2—General Administration.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 283,98,80,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 3—Home.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is -

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 22,33,02,000/- for revenue expenditure be granted to the

Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 5—Excise & Taxation.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 3,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 6—Finance.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 4,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 7—Other Administrative Service.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 94,02,83,000/- for revenue expenditure and Rs. 147,10,88,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 8—Buildings & Roads.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 6,84,83,95,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 9—Education.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 260,77,53,000/- for revenue expenditure and Rs. 53,03,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of

payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 10—Medical & Public Health.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 99,00,52,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 11—Urban Development.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 36,82,51,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 12—Labour & Employment.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 8,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 13—Social Welfare and Rehabilitation.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 30,13,83,000/- for revenue expenditure and Rs. 60,83,95,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 14—Food & Supplies.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 686,49,31,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 15-Irrigation.

The motion was carried

Mr. Speaker: Question is—

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 89,27,66,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 17—Agriculture.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 7,71,64,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 18—Animal Husbandry.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,32,89,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 19—Fisheries.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 15,39,02,000/- for revenue expenditure and Rs. 1,37,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 20—Forests.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 169,33,18,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of

Demand No. 21—Community Development.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 9,33,00,000/- for revenue expenditure and Rs. 13,06,11,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 22—Co-operation.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 69,55,82,000/- for revenue expenditure and Rs. 64,60,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand No. 23—Transport.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 26,85,000/- for revenue expenditure and Rs. 9,40,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of Government for the year ending 31st March, 2009 in respect of Demand payment No. 24—Tourism.

The motion was carried

कार्य सूची की एक मद को अस्थगित करना

Mr. Speaker: Hon' ble Members, due to paucity of time this item of business i.e. resumption of discussion on special report of Committee of Privileges may be deferred for 20th February, 2009.

Now, the House is adjourned till 2.00 P.M. today,

the 13th February, 2009, Second sitting.

***13.16 Hrs.**

(The Sabha then adjourned till 2.00 P.M. today, the 13th February, 2009, Second Sitting.)